M.P./BHOPAL/642/2018-20

• निकाय चुनाव की बिसात बिछी • 'शेरनी' के साथ डिनर की चाह

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

2023 का टेंशन

वर्ष 19, अंक-5 | 1 से 15 दिसंबर 2020 | पृष्ठ-48 | मूल्य 25 रूपये

R.N.I. NO.HIN/2002/8718

सरकार सख्त प्रशासन पस्त

शिवराज के सख्त फैसलों में नए अध्याय के संकेत

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

मप्र कांग्रेस

12 | असमंजस में नाथ

मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ इन दिनों असमंजस में हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मिली हार के बाद वे प्रदेश कार्यकारिणी भंग करना चाहते हैं, लेकिन असमंजस यह है कि इसे नगरीय निकाय चुनाव...

मुद्दा

14 | इनकी सुध कौन लेगा?

देह व्यापार एक सामाजिक व्याधि है, जिसका दोषी यौनकर्मी महिलाओं को ही ठहराना पूर्णतया अनुचित है। यह क्रय और विक्रय की वह प्रक्रिया है, जिसमें पुरुषों की भी समान भूमिका होती है। तो फिर यह घृणा सिर्फ स्त्री...

महंगाई

16 | 90 पार पहुंचा पेट्रोल

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और बीते 6 माह में ही 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। भोपाल में 90.05 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव हो चुका है। इसी तरह डीजल के दाम 80.10 रुपए के पार पहुंच गए हैं...

जांच

18 | खुलेगी चावल घोटाले की परतें

कोरोनाकाल में भ्रष्टाचार के जरिए आपदा को अवसर में बदलने वाले मिलर्स और अफसरों की मुश्किल बढ़ गई हैं। घटिया चावल मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली। प्रदेश सरकार के आदेश पर जबलपुर ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही थी। जांच में सामने आया कि फरवरी 2020...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

उपचुनाव के बाद सरकार मजबूत होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कमर कस ली है। अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से लेकर मंत्रालय और फील्ड में पदस्थ अफसरों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की हिदायत दे दी है। सरकार के इस सख्त रुख से अधिकारी संकट में फंस गए हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वे सरकार के निर्देशों पर सख्त होते हैं तो उन पर कभी भी गाज गिर सकती है।

सियासत

32-33 | राज्यों में पस्त होती कांग्रेस

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस केंद्र के साथ ही राज्यों में भी धीरे-धीरे पस्त होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस को दमदार नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। आज देश में जहां भाजपा की जड़ें मजबूत हो रही हैं, वहीं कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है।

राजस्थान

35 | घिरीं वसुंधरा

राजनीति में यादें कभी धुंधली नहीं पड़तीं। लेकिन सियासी दांवपेच की तेज रफ्तार कब, किसे फिसड्डी और किसे माहिर साबित कर दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कब, कौन महारथी गुमनामी की खोह में धकेल दिया जाए, तो अचरज नहीं होना चाहिए।

उप्र

37 | लव जिहाद पर नकेल

उप्र में लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं कानून-व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही थीं। ऐसी घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बना दिया है। अब राज्य में छल-कपट...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

जेल की नौबत ही क्यों आने दें...?

किसी शायर ने लिखा है...

सुना है, गुनहगारों को जरूर मिलती जेल है,
इसलिए पूरी मानवजाति आज कैद है।

यह शेर पढ़कर आप आश्चर्यचकित जरूर होंगे, क्योंकि आप तो कैद में हैं ही नहीं। लेकिन मप्र में कब आपको जेल हो जाए यह कोई नहीं जानता। दरअसल, मप्र में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब अलग-अलग शहरों में प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ-साथ उन्हें 10 घंटे के लिए जेल (खुली जेल बनाई गई है) भी भेजा जा रहा है। शासन-प्रशासन का यह कदम हमारी सुरक्षा के लिए ही है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जेल की नौबत ही न आए। दरअसल, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी बन गया है, जिसे मास्क पहनने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि हमें सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मास्क पहनना चाहिए। अगर हम सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते रहते तो सरकार को कठोर दंड का प्रावधान नहीं करना पड़ता। वैसे भी लॉकडाउन के दौरान पूरा देश घरों में कैदी की तरह रहा है। अपने घर में भी बंद रहना किसी जेल से कम नहीं लगा। इसलिए हमें हर हाल में यह कोशिश करनी है कि सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन न हो। सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन का ही परिणाम है कि देश में कोरोना एक बार फिर चरम पर है। जिस कारण गुजरात हाईकोर्ट को यह सख्त निर्देश देना पड़ा है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उससे कोविड सेंटर में काम कराएं। जेल भेजने और कोविड सेंटर में काम कराने की यह जो नौबत आई है इसके पीछे शासन-प्रशासन का नरम रवैया भी रहा है। प्रशासन ने शुरू में लॉकडाउन के दौरान सख्ती बरती, लेकिन जैसे-जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे प्रशासन सुस्त पड़ता गया और जनता लापरवाह होती गई। प्रशासन ने मान लिया कि कोरोना के मामलों में कमी आने का मतलब है कि अब कोरोना की विदाई का वक्त आ गया है और जनता को भी लगा कि संक्रमण दर में कमी आने का अर्थ है घरों से बाहर बेवजह घूमना। बहुत से लोग मास्क से नाक व मुंह को न ढंककर, उसे गले में लटकाकर घूमने लगे, बिना मास्क के घूमने लगे। अब जब हालात बेकाबू हो गए हैं तो सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने चिंता व्यक्त करके सभी देशवासियों को चिंता में डाल दिया है। चिंतित लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अब फिर सियासत हो रही है। क्योंकि अब त्योहार निकल गए हैं और राज्यों के चुनाव भी हो चुके हैं। दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक और बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर अन्य 11 राज्यों के उपचुनावों के दौरान देश में अप्रत्याशित तरीके से कोरोना के मामले घटने लगे थे। जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, बिहार में सरकार बनी और त्योहारों की रौनक कम हुई और फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। कोरोना महामारी को लेकर जानकारों और डॉक्टरों ने बताया कि अगर देश में इसी तरह सियासत होती रही, तो आने वाले दिनों में कोरोना भयंकर रूप ले लेगा। जहां आपदाएं, विपदाएं आती हैं, वहां कुछ व्यापारिक और सियासी लोग अपना लाभ देखते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अचानक कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे दवाओं और वैक्सीन का बाजारीकरण है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 5, पृष्ठ-48, 1 से 15 दिसंबर, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2018-20

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

शहर होंगे स्मार्ट

प्रदेश के चार महानगरों में से ग्वालियर स्मार्ट सिटी की रफ्तार सबसे धीमी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शहर के विकास को गति नहीं मिल पा रही है। वहीं स्मार्ट सिटी का फंड दूसरे शहरों को ट्रांसफर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कार्य को गति मिल रही है।

● **रोहन शर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

किसानों पर ध्यान दें

मप्र सहित देशभर में बिचौलियों और व्यापारियों ने प्याज के गोरखधंधे में बहुत मुनाफाखोरी की है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है और वहीं की लासलगांव की मंडी से प्याज के दाम तय होते हैं। किसानों को महंगाई के मुताबिक कम फायदा हो रहा है।

● **शुभम सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

बिजली का नया टैरिफ

मप्र सरकार बदलने के बाद से अटका हुआ बिजली का नया टैरिफ लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। 7 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई जा सकती हैं। कोरोनाकाल के अलावा उपचुनाव होने के कारण सरकार भी नया टैरिफ लागू करने के पक्ष में नहीं बताई जा रही थी।

● **सागर पाठक,** इंदौर (म.प्र.)

शिवराज पर जनता को विश्वास

मप्र में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था, लेकिन करीब दो साल बाद हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मतदाताओं ने एक बार फिर भाजपा सरकार के 7 महीने के कामकाज पर भरोसा जताया है। उपचुनाव के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि मप्र में शिवराज है तो विश्वास है। परिणामों व रुझानों ने साबित कर दिया कि मप्र में शिवराज की लोकप्रियता सबसे अधिक है। कोरोनाकाल में मतदान प्रतिशत बढ़ने से लेकर अधिक संख्या में महिलाओं के मतदान करने के पीछे भी उनकी मामा की छवि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कामयाबी में कांग्रेस सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का योगदान भी शामिल है।

● **हेमलता मकोडिया,** सीहोर (म.प्र.)

आपदा को अवसर में बदलने में जुटा संघ

सेवा, अनुशासन, संयम और देशभक्ति ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान है। देश पर कोई भी आंच आने पर संघ अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर राष्ट्र व समाज की मदद के लिए सेवा कार्य करता रहा है। कोरोनाकाल में भी संघ द्वारा वृहद स्तर पर जरूरतमंदों के लिए मुहिम जारी रही। कोरोना वायरस के कारण देश में आई आपदा को अवसर में बदलने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुटा हुआ है। इसके तहत संघ लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है।

● **निशांत विश्वकर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

कार्यवाही करे सरकार

गरीबों व कुपोषितों को पोषित करने के लिए मूंग दाल के बाद अब चना बांटा जा रहा है। हाल ही में शासन स्तर से 106 मीट्रिक टन चना बांटने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को सप्लाई किया गया। जिसे निगम ने खाद्य आपूर्ति विभाग को दे दिया और खाद्य आपूर्ति विभाग ने बिना जांचे ही यह चना गरीबों में बांटने के लिए उचित मूल्य दुकानों पर भेज दिया। सरकार को ऐसी लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए।

● **प्रिया सोलंकी,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

नीतीश के लालू प्रेम से भाजपा असहज

बिहार में भले ही नीतीश सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, सरकार के मुखिया खासे व्यथित और असहज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इस असहजता का कारण 13 बरसों में पहली बार उनकी पार्टी जद(यू) का भाजपा की बरस्क विधानसभा में कम सीटें जीत पाना है। अपनी शर्तों पर भाजपा संग सत्ता में साझेदारी करने के आदि नीतीश को अब भाजपा के इशारों पर सरकार चलानी पड़ रही है। जद(यू) के बड़े नेताओं को आशंका है कि आने वाले समय में भाजपा कांग्रेस और राजद में फूट डाल इन पार्टियों के विधायकों से दलबदल करा राज्य विधानसभा में खुद का बहुमत पाने का प्रयास करेगी। यदि ऐसा हुआ तो नीतीश के बजाय भाजपा अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाएगी। जद(यू) नेताओं का मानना है कि अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए ही बिहार की राजनीति से सुशील मोदी को दूर किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक नीतीश कुमार के विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर फूटे गुस्से के इन्हीं कारणों के चलते अलग निहितार्थ निकाल रहे हैं। तेजस्वी पर तीखा प्रहार करते समय लालू को अपना मित्र कह पुकारने वाले नीतीश कुमार ने इशारों-इशारों में भाजपा नेतृत्व को चेता दिया है कि नाराज मित्र को वे जब चाहे मना भी सकते हैं।

ओवैसी को भाजपा ने बड़ा बना दिया

भाजपा हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के बिहार में किए अहसान का बदला चुका रही है। भाजपा ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव को भाजपा बनाम एमआईएम बनाया है। इससे भी आगे बढ़कर भाजपा ने इसे असदुद्दीन ओवैसी बनाम अमित शाह या असदुद्दीन ओवैसी बनाम योगी आदित्यनाथ बनाया है। तभी ओवैसी को कहने का मौका मिला कि अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार में आना बाकी रह गया। सोचें, अमित शाह ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को कितना बड़ा बना दिया, जो उन्होंने कहा कि ओवैसी के हंगामे की वजह से सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं निकाल पा रही है। उन्होंने कहा कि ओवैसी लिखकर दें तो देखें सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सोचें, विपक्ष को ठेंगे पर रखकर अमित शाह संसद में कश्मीर का विशेष राज्य का दर्ज बदल देते हैं, समूचे विपक्ष के विरोध के बावजूद कृषि कानून बदल देते हैं, श्रम कानूनों में सुधार कर देते हैं पर एक अकेले ओवैसी के विरोध के कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने का फैसला नहीं कर पाते हैं। इसका क्या यह मतलब नहीं है कि एक ओवैसी संसद में समूचे विपक्ष से भारी है?

दक्षिणी राज्यों को साधने की कोशिश

अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सारे चुनाव एकसाथ कराने की पहल करते हैं तो विपक्षी पार्टियों को इसके लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। खासकर दक्षिण भारत की पार्टियों को, जो अपने को किसी तरह से राष्ट्रीय चुनाव से अलग रखने का प्रयास करती हैं। ध्यान रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने-अपने राज्य के चुनाव को लोकसभा चुनाव से अलग करने के लिए आठ महीने पहले ही विधानसभा भंग कर दी और अलग चुनाव कराया। वे नहीं चाहते थे कि राज्य के चुनाव पर लोकसभा के प्रचार का असर हो क्योंकि उनको अंदाजा है कि लोकसभा के साथ चुनाव होने पर उत्तर भारत की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। सो, अगर प्रधानमंत्री एकसाथ चुनाव की पहल करते हैं और वह भी 2022 में सबसे ज्यादा मुश्किल दक्षिण भारत की विपक्षी पार्टियों को तैयार करने की होगी। ध्यान रहे तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में अगले साल अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं। सो, इन तीन राज्यों की पार्टियां एक साल बाद ही फिर चुनाव के लिए तैयार होंगी, इसमें संदेह है। समय से चार साल पहले चुनाव कराने के लिए उनको तैयार कराना मुश्किल होगा।

कंधे की दरकार

भाजपा की निगाह पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु पर भी टिकी है। तभी तो अपने सरकारी चेन्नई दौरे का अमित शाह ने सियासी समीकरण बिठाने में पूरा इस्तेमाल किया। जयललिता की मौत के बाद अन्नाद्रमुक में नेतृत्व का संकट किसी से छिपा नहीं है। जयललिता की सहेली शशिकला के जेल जाने के बाद पलानीस्वामी ने केंद्र सरकार की मदद से सरकार तो चला ली पर उनके लिए विधानसभा चुनाव में द्रमुक को टक्कर देना आसान नहीं होगा। उन्होंने ओ पनीरसेल्वम से हाथ मिलाकर शशिकला के भतीजे दिनाकरण को फिलहाल भले ही हाशिए पर धकेल दिया हो पर शशिकला के जल्द जेल से बाहर आने की खबर से वे परेशान हैं। तभी ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी भाजपा से मिलकर लड़ेगी अन्नाद्रमुक। द्रमुक के पूर्व सांसद केपी रामलिंगम के भाजपा में शामिल होने को पार्टी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रामलिंगम के जरिए भाजपा द्रमुक नेता स्टालिन के बागी भाई अझागिरी को भी लेने की जुगत में हैं।

सरकार मजबूत है या विपक्ष?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। प्रधानमंत्री यह शिकायत पहले भी कर चुके हैं। सवाल है कि जब सारी बातें वे देश के लोगों को समझा लेते हैं और देश के लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। जिनको वे नहीं समझा पाते हैं, उनको पार्टी का आईटी सेल समझा देता है। उनकी पार्टी और आईटी सेल ने तो देश के लोगों को ऐसी-ऐसी चीजें समझा रखी हैं, जिनका कोई बेसिक आधार नहीं है। कोई सिर-पैर नहीं है। फिर भी लोग उन बातों पर यकीन करते हैं। फिर हैरानी की बात है कि कृषि कानूनों के मामले में सरकार, प्रधानमंत्री और आईटी सेल मिलकर किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? और उससे भी अहम है कि विपक्ष के पास इतनी ताकत अचानक कहां से आ गई कि वह इतनी आसानी से किसानों को गुमराह कर ले रहा है? असल में यह समझाने या गुमराह करने का मामला ही नहीं है। यह असली मुद्दा है और किसान इसको समझ रहे हैं।

होली का इंतजार

फिल्म काला पानी का गीत 'नजर लागी राजा तोरे बंगले पर' तो आपने सुना ही होगा। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों मप्र की राजनीति में बने हुए हैं। जहां एक तरफ कुछ विधायक मंत्री बनने की कवायद में जुटे हुए हैं, वहीं एक मंत्रीजी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले मंत्रीजी को होली का इंतजार है। जानकारों का कहना है कि मंत्रीजी को इस बात की उम्मीद है कि होली के बाद उनकी महत्वाकांक्षा को पंख लग जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री बनने की उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि अपनी सरकार में हमेशा संकटमोचक की भूमिका निभाने वाले मंत्रीजी की प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनाने में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो सरकार बनने की उम्मीद जैसे ही जगी तब से ही मंत्रीजी को मुख्यमंत्री बनने के सपने आने लगे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया। हालांकि मंत्रीजी अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी को किसी ज्योतिषाचार्य ने भी विश्वास दिलाया है कि होली या उसके बाद आपका मुख्यमंत्री बनने का प्रबल योग है। उसी विश्वास के साथ मंत्रीजी मुख्यमंत्री बनने के सपने में खोए हुए हैं। अब देखना यह है कि मंत्रीजी की होली क्या गुल खिलाती है। मंत्रीजी का सपना साकार होता है या बेकार जाता है।

पैर जमीन पर नहीं

मप्र में जबसे सत्तारूढ़ पार्टी उपचुनाव जीतकर मजबूत हुई है, तबसे सरकार हवा-हवाई हो गए हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि उपचुनाव की जीत का सारा श्रेय उन्हें ही दे दिया है। दूसरा यह कि उन्होंने पूरी सरकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी है। वैसे जबसे नए विमान से सरकार ने उड़ान भरना शुरू किया है, तबसे कुछ ऐसे संयोग भी बन रहे हैं कि वे स्टेट हैंगर से एक जगह जाते हैं फिर वहां से लौटकर कपड़े बदलते हैं और दूसरी जगह के लिए उड़ान भर देते हैं। इन दिनों उनका लगभग रोजाना गोंदिया जाना हो रहा है। इस कारण वे सुबह गोंदिया के लिए उड़ान भरते हैं और वहां का काम निपटाकर राजधानी पहुंचते हैं और फिर नई जगह के लिए उड़ान भर देते हैं। वैसे सरकार के बारे में यह ख्यात है कि वे कभी थकते नहीं हैं। उनकी लगातार काम करने की क्षमता देख अच्छे-अच्छे युवा भी शरमा जाते हैं। अब अगर ऐसे में सरकार को नए विमान से उड़ान भरने को मिल रहा है तो फिर थकने का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार की उड़ान को देखकर उनके कुछ साथी जल भुन भी रहे हैं। वे कहते हैं कि इन दिनों सरकार के कदम जमीन पर तो टिक ही नहीं रहे हैं।

नौकरशाहों का मप्र से मोहभंग

देश का हृदय प्रदेश मप्र हमेशा से आम और खास के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। देश के हर नौकरशाह की मंशा होती है कि उसका मप्र में बसेरा हो। लेकिन विसंगति यह देखने को मिल रही है कि मप्र कैडर के नौकरशाहों का मप्र से मोहभंग होता रहता है। वर्तमान समय में कई अफसरों को मप्र की जमीन सूट नहीं कर रही है। इसलिए वे या तो प्रतिनियुक्ति पर केंद्र पर चले गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरों के मप्र मोहभंग के कारणों की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश में अच्छी पोस्टिंग न मिलने से अफसर दिल्ली में जाना उचित समझते हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में अधिकतर यह परंपरा रही है कि सरकार अपने प्रिय अफसरों को अच्छी पोस्टिंग देती है। अफसर की कार्यप्रणाली चाहे कैसी भी हो। ऐसे में कई अफसरों को अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल पाती है। जिस कारण आईएएस हो या आईपीएस इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनकी केंद्र में पोस्टिंग हो जाए। हाल ही में कई आईएएस-आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं और कई जाने की कोशिश में हैं। मप्र में कई अफसर तो ऐसे हैं जो वर्षों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वे मप्र आने की अपेक्षा दिल्ली में ही पदस्थी के लिए जोर-जुगाड़ लगाते रहते हैं। कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के वक्त दिल्ली में ही अंतिम समय बिताना चाहते हैं, ताकि वहीं से सकुशल घर जा सकें।

मंत्रियों को रेटिंग की चिंता

पहले जुगाड़, फिर जनता के समर्थन से मिली सरकार को जनप्रिय बनाने के लिए सरकार के मुखिया ने कमर कस ली है। इस कड़ी में उन्होंने अपने मंत्रियों की कार्यप्रणाली सुधारने की कवायद शुरू की है। इसके तहत उन्होंने मंत्रियों के कामकाज के आधार पर उनकी रेटिंग करने का निर्देश जारी किया है। मंत्रियों की रेटिंग उनकी मासिक रिपोर्ट कार्ड पर निर्भर करेगी। मासिक रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों को खुद ही तैयार करनी है। इसलिए इन दिनों मंत्रियों को अपनी रेटिंग की चिंता सताने लगी है। मंत्रियों को रेटिंग की चिंता इस कदर है कि उन्होंने अपने विभाग और अपने क्षेत्रों पर अपना पूरा फोकस कर दिया है। कई मंत्री अलसुबह अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं और लोगों से मेल-मिलाप करते हैं, तो कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अपने विभाग की कार्यप्रणाली सुधारने पर जोर दे रहे हैं। यही नहीं मंत्रियों की कोशिश यह भी रहती है कि उनके दैनिक कार्यों की रिपोर्ट अधिक से अधिक प्रसारित हो। इसलिए मंत्री इन दिनों सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। मंत्रियों की लगातार कोशिश है कि वे अच्छे से अच्छा काम कर अपनी रेटिंग बढ़ाएं।

गरीबी में आटा गीला

मप्र इस समय आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि प्रदेश सरकार को हर महीने कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद सरकार नई-नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। ऐसे में अफसरों के सामने यह समस्या बढ़ गई है कि गरीबी के इस दौर में वे किस योजना के क्रियान्वयन के लिए फंड की जुगाड़ करें। अफसर एक योजना के लिए फंड की जुगाड़ करते हैं, तब तक दूसरी योजना उनके सामने आ खड़ी होती है। ऐसी घड़ी में सरकार की काऊ पॉलिटिक्स ने अफसरों को उलझा दिया है। दरअसल, सरकार की काऊ पॉलिटिक्स पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इस रकम से प्रदेश में गौ-वंश संवर्धन के लिए विभिन्न कार्य होने हैं। गौशाला निर्माण से लेकर उनके बेहतर संचालन के लिए यह राशि खर्च होनी है। अफसरों की समझ में यह नहीं आ रहा है कि गरीबी में सरकार आटा गीला क्यों कर रही है। इसके अलावा कई और घोषणाएं ऐसी हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता से अमलीजामा पहनाना चाहती है। लेकिन पैसा कहां से आएगा, किसी को नहीं पता।

राजनीति में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह पार्टी तय करेगी। मैं भाजपा का सिपाही हूं और भाजपा में नेताओं की राजनीति की दिशा और दशा संगठन तय करता है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी जल्द ही मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा।

● **सुशील मोदी**

किसानों पर इस तरह की लाठी किसी ने नहीं चलाई होगी और इस तरह का आतंकी हमला किसी सरकार ने नहीं किया होगा, जैसा भाजपा की सरकार में हो रहा है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने किसानों से कहा था कि वे सत्ता में आने पर उनके सिर्फ कर्ज माफ नहीं करेंगे बल्कि पैदावार की कीमत देंगे, लेकिन जबसे भाजपा सरकार आई है, तबसे किसान बर्बाद हुए हैं।

● **अखिलेश यादव**

इंज्युरी खेल का हिस्सा है। एक तरफ आप बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं और दूसरी तरफ इंज्युरी की। अगर दो खिलाड़ी चोटिल होते हैं, तो आपको लगता है कि टीम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी प्रॉपर रिहैब के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो चोटिल होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। और भी खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जो मौके का इंतजार करते हैं।

● **मदनलाल**

लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेक आशंकाओं से भरा है जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता और ना ही स्वीकार्यता है।

● **मायावती**

मैं जॉन अब्राहम के साथ सत्यमेव जयते-2 फिल्म कर रही हूं। इस फिल्म में मेरा किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक भारतीय नारी को रिप्रजेंट करूंगी। इस फिल्म के डायरेक्टर मिलाप झवेरी ने मेरे किरदार में डिग्निटी, स्ट्रेंथ और भारतीय नारी की शक्ति इन तीनों को बखूबी पिरोया है। अपने रोल के लिए भी मैंने काफी मेहनत की है। जॉन अब्राहम एक बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर हैं। वे सेट पर हमेशा टाइम से आते हैं। शूटिंग के दौरान हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे बहुत ही डाउन टू अर्थ, हंबल व्यक्ति हैं। शूटिंग के दौरान कभी-कभी हम उनकी फुटबॉल टीम के बारे में भी डिस्कशन किया करते थे। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक्टिंग पर ही केंद्रित है। मैं अच्छे किरदार निभाना चाहती हूं। हां भविष्य में फिर से किसी फिल्म को जरूर डायरेक्ट करना चाहूंगी। मैं अक्सर अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में रहती हूं और उन्हें अपने पास सहेज के रखती हूं।

● **दिव्या खोसला कुमार**

वाक्युद्ध

अपने 6 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर वर्ग को नाखुश किया है। सरकार कारपोरेट घरानों के हाथ में खेल रही है। इस कारण देश में हर तरफ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की मनमानी के खिलाफ अब लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जनता सड़क पर है।

● **राहुल गांधी**

कांग्रेस जनाधार खोने के बाद भी सचेत नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी को न जाने यह कहां नजर आ रहा है कि लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की हर समय कोशिश यही रही है कि वह देश की जनता को बरगला कर शासन करे। लेकिन अब उसकी दाल गल नहीं रही। इसलिए राहुल गांधी को देश में हंगामा नजर आ रहा है।

● **रविशंकर प्रसाद**

अपने विवादास्पद बयानों और कार्यप्रणाली के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। इस बार वे अभिनेत्री विद्या बालन के साथ डिनर की चाह में घिर गए हैं। आरोप है कि मप्र में फिल्म शेरनी की शूटिंग कर रही विद्या बालन ने मंत्री के डिनर के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो मंत्री ने फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। हालांकि मामला तूल पकड़ने पर शूटिंग शुरू हो गई है।

'शेरनी' के साथ डिनर की चाह

विवादों से विजय शाह का पुराना वास्ता है। चाहे विधायक रहे हों या मंत्री विवाद हमेशा उनके पीछे लगे ही रहते हैं। अभिनेत्री विद्या बालन को डिनर का ऑफर देना और उनके द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने के बाद शूटिंग क्रू के साथ वन विभाग के अफसरों के बर्ताव ने कई पुराने विवादों को ताजा कर दिया है। मप्र की जनता को यह भी अच्छे से याद है कि एक बार तो अपनी टिप्पणी के कारण शाह को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उनकी यह टिप्पणी सालों तक लोग भूल नहीं पाए थे। हालांकि विद्या बालन एपिसोड के बाद सरकार के रवैये को देखते हुए शाह को बैकफुट पर आना पड़ा है। गौरतलब है कि विदेशी महिलाओं को नचाने और विवादित बयानों के कारण शाह कई बार चर्चा में रहे हैं।

मंत्री की मंशा और कार्यप्रणाली को लेकर मप्र में भले ही शांति है लेकिन देशभर में प्रदेश की साख गिरी है। खासकर मायानगरी मुंबई में इस प्रकरण की जमकर चर्चा हो रही है। मराठी भाषी अखबारों में इस घटनाक्रम को खूब उछाला गया है। इससे मप्र में शूटिंग के लिए आने वाले लोगों का मन बदल सकता है। गौरतलब है कि एक तरफ उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसके लिए फिल्मी हस्तियों को रिझाने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मप्र में फिल्म निर्माता और निर्देशक बिना निमंत्रण के यहां फिल्मों की शूटिंग करने आ रहे हैं। ऐसे में मंत्री के व्यवहार का यहां के फिल्म उद्योग पर असर पड़ सकता है।

गौरतलब है कि अभिनेत्री विद्या बालन इन दिनों मप्र में अपनी नई फिल्म 'शेरनी' की शूटिंग कर रही हैं। वह यहां के जंगलों में पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म के लिए सीन शूट कर रही हैं। लेकिन अचानक से उनकी शूटिंग को रोक दिया गया है। शूटिंग रोकने की वजह मप्र के वन मंत्री विजय शाह को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विजय शाह ने विद्या बालन को अपने साथ डिनर करने का न्यौता भिजवाया था, जिसे विद्या ने स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की प्रोडक्शन टीम की गाड़ी को कथित तौर पर शूटिंग के लिए जंगल में जाने से रोक दिया गया। बालाघाट के जिला वन अधिकारी ने प्रोडक्शन टीम की गाड़ियों को जंगल में जाने से रोका और कहा कि सिर्फ दो गाड़ियों के जाने की अनुमति है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि अगले दिन जब शूटिंग यूनिट टाइगर रिजर्व पहुंची तो साउथ डीएफओ जीके बरकड़े ने उनकी गाडियां रोक दीं। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि केवल 2 ही गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति है। इस बारे में जब उच्च अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने तुरंत फिल्म यूनिट को शूटिंग के लिए टाइगर रिजर्व में प्रवेश दिए जाने का आदेश स्थानीय फारेस्ट डिपार्टमेंट को दिया। इसके बाद शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी। कांग्रेस का कहना है कि इस व्यवहार के लिए विजय शाह को माफी मांगनी चाहिए।

वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि विद्या बालन से मुलाकात की बात एकदम सही थी। लेकिन डिनर की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई थी। उन्होंने फिल्म यूनिट की गाड़ियों के रोके जाने के बारे में कहा कि शूटिंग के लिए सिर्फ दो जनरेटर ले जाने की अनुमति थी, लेकिन उस दिन अलग-अलग गाड़ियों पर लदे कई जनरेटर टाइगर रिजर्व में ले जाए जा रहे थे। इसलिए डीएफओ ने उन्हें प्रवेश से रोका था। वन मंत्री विजय शाह ने कहा- 'मैं पूछना चाहता हूं शूटिंग कब कैंसिल हुई? जिन्होंने अनुमति ली थी उनके निमंत्रण पर मैं गया था, एक महीने बाद। अक्टूबर से शूटिंग चल रही थी। मैं नहीं गया। उन्होंने कहा था आप जब महाराष्ट्र जाएं तो बालाघाट होते हुए जाएं। हमारी यूनिट के साथ डिनर करिए। जब मैं एक महीने बाद बालाघाट गया तो वहां से महाराष्ट्र गया। किसी कारण से डिनर कैंसिल हो गया। ये कारण तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने अनुमति ली।'

● **राकेश ग्रोवर**

आरोपों-विवादों के चलते शाह को गंवाना पड़ा था मंत्री पद

आदिवासी वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले विजय शाह वर्तमान सरकार में वन मंत्री हैं। शाह पिछली सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री थे। अप्रैल 2013 में झाबुआ में स्कूली छात्राओं के एक कार्यक्रम में वे ऐसे बहके कि वहां मौजूद छात्राएं और शिक्षिकाएं शर्म से पानी-पानी हो गईं। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे शाह ने मंच पर मौजूद एक नाम की दो महिला नेताओं को देखकर कहा था- 'लगता है झाबुआ में एक के साथ एक फ्री मिलती है।' वे शिविर में बैठी लड़कियों की ओर इशारा करते हुए बोले 'पहला-पहला जो मामला होता है, वह आदमी भूलता नहीं।' मंत्रीजी की हिम्मत इतनी बढ़ी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इससे बवाल मच गया। रातोरात शाह को तलब कर उनसे इस्तीफा ले लिया गया।

मप्र की राजनीति में 2018 का विधानसभा चुनाव ऐसी खुमारी दे गया है कि भाजपा-कांग्रेस के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 सालों से सत्ता का संग्राम अब जाकर थमा ही है कि दोनों पार्टियों को 2023 के विधानसभा चुनाव का टेंशन सताने लगा है। दोनों पार्टियों के विधायक अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए अभी से मैदानी मोर्चा संभाल चुके हैं।

2023 का टेंशन

भाजपा-कांग्रेस में अभी से बनने लगी रणनीति

उपचुनाव की खुमारी उतरते ही मप्र की दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने अभी से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने आगे के चुनावों की तैयारियां शुरू कर एक-दूसरे को घेरने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया हैं। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस को जीत मिली है और जहां पहले से ही कांग्रेस चुनाव जीतते आई है, वहां मुख्यमंत्री शिवराज ने टीम-बी को उतार दिया हैं। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज की टीम-बी के मैदान में उतरते ही कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ भी हरकत में आ गए हैं। कमलनाथ की टीम-सी भाजपा के खिलाफ प्लान तैयार कर रही है। शिवराज कैबिनेट के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले इलाको में पार्टी ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी की हैं। 2023 के चुनाव में दोनों कांग्रेस नेताओं के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर जीत की प्लानिंग शुरू हो चुकी है।

मप्र में अगले विधानसभा चुनाव होने में अभी 3 साल का समय बाकी है। अगले विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन चुनाव का टेंशन अभी से विधायकों पर छा गया है। 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित रहे नतीजे विधायकों के टेंशन का बड़ा कारण बन गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही मौजूदा विधायकों ने अपनी सीट को बचाने के लिए अभी से चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। ताकि सीट को कोई दूसरा भेद ना पाए। भाजपा, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल वोटरों से संपर्क बढ़ाने में जुट गए हैं। विधायकों को अब अपने क्षेत्र की समस्याएं भी नजर आने लगी हैं।

भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपने भोजपुर विधानसभा सीट पर अफसरों के साथ बैठक कर लंबित प्रस्तावों पर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा बताते हैं कि वह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से संपर्क में हैं और लगातार बैठक कर आम लोगों से जुड़े मुद्दों को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर अभी से विधानसभा में पकड़ को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रमुख होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के साथ जीतू पटवारी अपने विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के विधायक ही नहीं निर्दलीय विधायक भी 2023 के चुनाव के टेंशन में हैं और निर्दलीय विधायकों ने भी चुनाव के 3 साल पहले अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने विधानसभा में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर टीम तैयार करना शुरू कर दिया है। सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि उन्होंने अगले 3 साल का रोडमैप तैयार किया है। स्थानीय मुद्दों पर जनता की शिकायतों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2020 में हुए 28 सीटों के उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस के साथ ही सपा, बसपा, निर्दलीय विधायकों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। जिन सीटों पर भाजपा को जीत की उम्मीद थी वहां उसको हार का सामना करना पड़ा है तो जिन सीटों पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी वहां कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली है और यही कारण है कि विधानसभा वार अप्रत्याशित नतीजों से परेशान माननीय ने अब जनता दरबार में अपनी हाजिरी देना अभी से शुरू कर दिया है। प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 3 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस-भाजपा ने अभी से एक-दूसरे की घेराबंदी का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता गोपनीय तरीके से एक-दूसरे का गढ़ भेदने की प्लानिंग में जुट गए हैं। 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद भाजपा ने मिशन 2023 के लिए कांग्रेस के अभेद्य किले को भेदने के लिए प्लान तैयार किया है।

शिवराज की टीम-बी को उन इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां कांग्रेस लगातार जीत हासिल करती आ रही है। शिवराज की टीम-बी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा, बैतूल और दिग्विजय सिंह के राजगढ़ में सक्रियता बढ़ाकर कांग्रेस को घेरने की प्लानिंग में जुट गई है। हाल ही में शिवराज के करीबी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और प्रदेश के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कमलनाथ के प्रभाव वाले छिंदवाड़ा-बालाघाट-सिवनी सहित कई जिलों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। शिवराज सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि 2023 के चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी की है। उन इलाकों पर सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले हैं। 2023 के चुनाव में दोनों कांग्रेस नेताओं के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर जीत की प्लानिंग शुरू हो चुकी है।

कांग्रेस के गढ़ में शिवराज की टीम-बी के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस भी हरकत में है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी है। 28 सीटों के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और अब भाजपा के गढ़ कांग्रेस के निशाने पर हैं। कमलनाथ की टीम-सी गोपनीय तरीके से भाजपा के अभेद किलों को गिराने का प्लान बना रही है। 2018 और उसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना गढ़ बचाने की थी। अब 2023 के चुनाव में दोनों ही सियासी दल एक-दूसरे के प्रभाव वाले इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में हैं। आगामी चुनाव में भले ही 3 साल का समय हो लेकिन अभी से लॉन्ग टर्म प्लान के तहत भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं।

भाजपा अब मालवांचल के सहारे ही 2023 के विधानसभा चुनाव में वापसी की तैयारी कर रही है। पार्टी का पहला लक्ष्य नगरीय निकाय चुनाव में सफलता पाना है। दरअसल, मालवा-निमाड़ में हुए नुकसान के कारण ही 2018 के

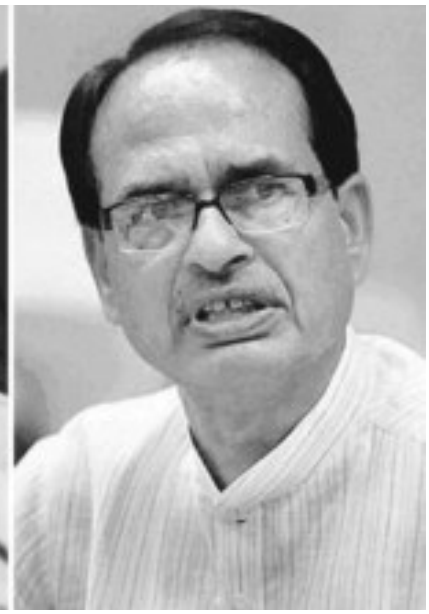

विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से वंचित हुई थी। मालवांचल में 66 सीट में से भाजपा को मात्र 27 सीटें मिली थी। इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई भाजपा ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव से कर ली। मालवा-निमाड़ अंचल में पार्टी सात में से छह सीटों पर विजयी रही। इंदौर संभाग में 37 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास पहले 9 सीटें थीं, जो बढ़कर अब 12 हो गई हैं। वहीं, उज्जैन संभाग में 29 में से 18 सीटें भाजपा को मिली थीं, जो अब 21 हो गई हैं। भाजपा ने उपचुनाव में इंदौर में वार रूम बनाया और आक्रामक लड़ाई लड़ी, वहीं कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत ग्वालियर-चंबल इलाके में झोंक दी, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा।

वर्ष 2003 से लेकर 2013 तक के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जब-जब मप्र में सरकार बनाई तब मालवा-निमाड़ के रास्ते ही उसे सफलता मिली थी। 2018 में भाजपा को इस अंचल से निराशा हाथ लगी थी क्योंकि उसे 29 सीटों पर भारी नुकसान हुआ था। यही वजह है कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। इनमें से अधिकांश पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। अब उपचुनाव में भाजपा को मालवांचल से सफलता मिली। पार्टी ने अपनी एक सीट आगर तो खो दी लेकिन बाकी 6 सीटें कांग्रेस से छीन लीं। प्रदेश में भाजपा सरकार में तो आ गई लेकिन सत्ता समीकरण के लिहाज से अभी भी ग्वालियर-चंबल और विंध्य क्षेत्र में पार्टी की स्थिति कमजोर है। उपचुनाव में भी ग्वालियर-चंबल अंचल में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद भी उपचुनाव में तीन मंत्री चुनाव हार गए। 16 सीटों में से भाजपा को सर्वाधिक 9 सीटें तो मिलीं लेकिन कांग्रेस भी 7 सीटें जीतने में सफल रही। उपचुनाव में भाजपा ने इंदौर में अपना वार रूम बनाया लेकिन कांग्रेस ने पूरी ताकत ग्वालियर अंचल पर लगाई। भितरघात रोकने से लेकर संगठन की मजबूती तक का मोर्चा इंदौर संभाग के संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा ने संभाला। उन्होंने हर सीट पर चार-पांच बार जाकर बातचीत की। उज्जैन संभाग के संगठन मंत्री विजय दुबे ने भी तमाम ऐसे नेताओं से संपर्क साधा, जिनसे भितरघात का खतरा था।

● **कुमार राजेन्द्र**

भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर

उपचुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का इस समय पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर है। दोनों पार्टियों में संगठन की विस्तार की तैयारी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही सांसद वीडी शर्मा की नई टीम का इंतजार किया जा रहा है। उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा की नई कार्यसमिति की घोषणा जल्द ही हो सकती है। इस संबंध में वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच मंत्रणा भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस टीम में 8 से 10 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश महामंत्रियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब प्रदेश भाजपा में नई कार्यसमिति का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक इसकी तैयारी की जा रही है और नए चेहरों को भी तलाशा जा रहा है। इसके लिए कई नेता लॉबिंग भी कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि वीडी शर्मा इस बार ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भी ज्यादा जगह मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की इस टीम में करीब 4 सिंधिया समर्थक शामिल किए जाने की चर्चा हैं। वहीं इस टीम में 8 से 10 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश महामंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसमें भी संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी।

असमंजस में नाथ

सर्वे और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट प्रत्याशी चयन का आधार बनेगी

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रत्याशी चयन के लिए तीन तरह का सर्वे कराया था। उसके बाद ही जीतने योग्य प्रत्याशी को टिकट दिया गया था। इसका परिणाम यह रहा था कि 15 साल के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मगर राजनीतिक उठापटक के चलते 15 महीने में ही यह सरकार गिर गई। सर्वे के अच्छे परिणाम सामने आने के बाद निगम चुनाव में भी इसे महत्व दिया जाएगा। तीन तरह का सर्वे पार्षद प्रत्याशी के लिए होगा और वार्ड के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक की रिपोर्ट प्रत्याशी चयन का आधार बनेगी।

मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ इन दिनों असमंजस में हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मिली हार के बाद वे प्रदेश कार्यकारिणी भंग करना चाहते हैं, लेकिन असमंजस यह है कि इसे नगरीय निकाय चुनाव से पहले भंग करें या बाद में। नाथ पर दबाव यह है कि कार्यकारिणी को निकाय चुनाव तक बने रहने दिया जाए। वहीं, नई पीढ़ी चाहती है कि निकाय चुनाव से पहले कार्यकारिणी भंग कर नए और युवा चेहरों को स्थान दें, ताकि कांग्रेस चुनाव में भाजपा का डटकर मुकाबला कर सके। पार्टी नेताओं की सोच है कि फिलहाल विधानसभा चुनाव (2023) में लगभग पौने तीन साल बाकी हैं। पार्टी को इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए। एक बेहतर विपक्ष का रोल अदा करने के साथ रणनीति यह होनी चाहिए कि अगले विधानसभा चुनाव में वह प्रदेश में सरकार बना सके।

15 साल सरकार से बाहर रहकर जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो उम्मीद जागी थी कि अगले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस का ही राज रहेगा, लेकिन 15 महीने में ही ऐसा सत्ता संघर्ष चला कि सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दोनों सीट जीत रही थी, लेकिन एक सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव बढ़ गया। उपचुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह सरकार में लौटने का माहौल बनाया या यूं कहें कि आत्मविश्वास दिखाया, इसी कारण पार्टी 9 सीट जीत पाई। पार्टी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती निकाय चुनाव है। पार्टी यदि इसमें बेहतर परफॉरमेंस दिखाएगी तो अगले विधानसभा चुनाव में वह भाजपा को पटखनी देने की स्थिति में होगी। इन चुनावों में कांग्रेस को हार मिली तो कार्यकर्ता पूरी तरह टूट जाएंगे। फिर कमलनाथ भी उनमें जान नहीं फूंक पाएंगे। पार्टी नेताओं का मानना है, अब **वह वक्त** आ गया है कि प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर नई टीम बनाई जाए। युवा पीढ़ी को आगे लाएं।

कांग्रेस के चाणक्य और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में कुछ बड़े बदलाव अपेक्षित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कांग्रेस के अंदरखाने के सूत्रों की मानें तो सोनिया गांधी के करीबी और विश्वासपात्र होने के कारण कमलनाथ को एआईसीसी में विशेष जिम्मा सौंपा जा सकता है। अहमद पटेल के निधन से खाली हुई जगह को भरने के लिए कमलनाथ की विशेष भूमिका रह सकती है। कमलनाथ की भूमिका तय करने के लिए उनको दिल्ली भी बुला लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ वे एआईसीसी में भी प्रमुख भूमिका में रह सकते हैं। इसके लिए उनको दिल्ली में ज्यादा समय गुजारना पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पहले ही आर्थिक मामलों से संबंधित समिति का सदस्य बनाया जा चुका है। कमलनाथ अभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं। उपचुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वे एक पद छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों की मानें तो कमलनाथ विधानसभा के इसी शीतकालीन सत्र में किसी और नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉ. गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा और बाला बच्चन के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। विधानसभा सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र तीन दिन का रहेगा जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इस बारे में कांग्रेस ने अभी फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ युवा विधायकों को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी देकर दूसरे राज्यों का प्रभार भी दिया जा सकता है।

28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक रहे, मगर कांग्रेस ने हार को भूलकर आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। शहर कांग्रेस कमेटी ने बकायदा शहर के 85 वार्डों के लिए नियुक्त ब्लॉक, मंडलम् अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों को कांग्रेस कार्यालय में तलब कर वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने की शुरुआत की है, वहीं निगम चुनाव के लिए मतदाता सूची की भी छानबीन की जा रही है। इसके अलावा अब तक **बूथ कमेटियां** वार्ड में गठित करने में लापरवाही बरतने वाले कांग्रेसियों को एक-दो दिनों में नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। मप्र में 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, मगर राजनीतिक उठापटक के चलते यह सरकार मात्र 15 महीने ही चल पाई, 15 महीने की अवधि में कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं और उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के वचन पत्र के जो वादे पूरे किए गए हैं, उसे आम जनता के बीच ले जाने का निर्देश भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही वर्तमान की भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह उपचुनाव के दौरान जनता को बरगलाने के लिए जो झूठे वादे किए हैं, उसकी सच्चाई भी जनता को बताने का निर्देश दिया गया है।

● **अरविंद नारद**

निकाय चुनाव की बिसात

मप्र में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला नगरीय निकाय चुनाव में होगा। लंबे समय से अटके नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। उपचुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिली और अब 3 साल सरकार चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लिहाजा अब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। भोपाल नगर निगम के चुनाव भी फरवरी-मार्च में ही होने थे, जो नहीं हो पाए और प्रशासक काल चल रहा है। अब अनुमान है कि जनवरी अंत तक निगम के चुनाव करवाए जा सकते हैं। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ महापौर पद का आरक्षण ही किया जाना है और नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायत चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु प्लान और कैलेंडर भी तैयार कर लिया है।

पूर्व की कमलनाथ सरकार ने महापौर के सीधे चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन किया था और पार्षदों के जरिए महापौर चुनने का नियम बना दिया, क्योंकि इंदौर सहित सभी बड़े शहरों में कांग्रेस के पास ऐसे जीतने वाले उम्मीदवार ही नहीं हैं, जो सीधे चुनाव में भाजपा को टक्कर दे सकें। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार के काबिज होते ही शिवराज मंत्रिमंडल ने कुछ दिनों पहले फिर से महापौर के चुनाव जनता द्वारा ही करवाए जाने का अपना पुराना नियम ही लागू कर दिया। यानी भोपाल के महापौर का भी अब पहले की तरह ही जनता द्वारा चुनाव किया जाएगा। महापौर का आरक्षण बचा है, जो भोपाल में संपन्न होगा। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन ने कुछ समय पूर्व ही पूरी कर ली थी। अब मतदाता सूची का काम अवश्य किया जाएगा।

शहर के 85 वार्ड में पार्षदों के लिए भी राजनीतिक जोड़तोड़ शुरू हो गई है। वहीं दोनों ही प्रमुख दल अब नगरीय निकाय, पंचायत और मंडी चुनाव में जुट गए हैं। भोपाल नगर निगम में चुनी हुई परिषद् का कार्यकाल भी फरवरी में ही समाप्त हो गया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 6 माह चुनाव आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसी बीच कोरोना महामारी आ गई, जिसके चलते चुनाव और टल गए। वहीं फिर उपचुनावों की हलचल शुरू हो गई। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी निपट गए और 19 सीटें जीतकर भाजपा उत्साहित हो गई और अब जोर-शोर से नगर निगमों पर फिर से कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है।

भोपाल में ही पिछले 20 सालों से भाजपा के ही महापौर के साथ उन्हीं के ही अधिक पार्षदों की परिषद् शिवराज सरकार पर काबिज रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए कैलेंडर तैयार कर लिया है, जिसमें मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रोत्साहित करना, मतदान केंद्रों की स्थापना, नए नियमों, नवाचारों में संशोधन और कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन, ईवीएम मशीनों का प्रदर्शन, संचालन, कम वोटिंग वाले क्षेत्रों का आंकलन, सरकारी विभागों, मीडिया की जिम्मेदारियों का निर्धारण, नुक्कड़ नाटक, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से लेकर सभी तरह के आयोजन शुरू किए जा रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक मतदाता सूची से लेकर महापौर आरक्षण और अन्य प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संभवत: जनवरी और अगर थोड़ा विलंब हुआ तो फरवरी में निगम चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं।

चुनाव की तैयारी पूरी

प्रदेश में नगरीय निकायों में अभी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को बदलते हुए यह तय कर दिया है कि चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे तौर पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार राज्य सरकार की हरी झंडी का है। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जो तय करेगा जीत का सरताज कौन होगा।

भाजपा और कांग्रेस ने नगरीय रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए नगरीय निकाय चुनाव में उम्र के बंधन को खत्म करने का फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। जिताऊ उम्मीदवार पार्टी का प्रत्याशी होगा। नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की अग्निपरीक्षा होगी। इससे पहले प्रदेश के 16 नगर निगमों में भाजपा का कब्जा था। 15 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का था जबकि एक सिंगरौली नगर निगम में बीएसपी का नेता प्रतिपक्ष था। सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। प्रदेश में 278 नगरीय निकायों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव के जरिए फिर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बैठाने की तैयारी शुरू होती नजर आ रही है।

नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर पद के लिए खर्च की सीमा 35 लाख रुपए और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए 15 लाख रुपए की सीमा रहेगी। इसी तरह एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद् के लिए चुनावी खर्च की सीमा 10 लाख रुपए और 50 हजार से 1 लाख के बीच की पालिका के लिए 6 लाख खर्च सीमा तय की गई है।

● **नवीन रघुवंशी**

इनकी सुध कौन लेगा?

देह व्यापार एक सामाजिक व्याधि है, जिसका दोषी यौनकर्मी महिलाओं को ही ठहराना पूर्णतया अनुचित है। यह क्रय और विक्रय की वह प्रक्रिया है, जिसमें पुरुषों की भी समान भूमिका होती है। तो फिर यह घृणा सिर्फ स्त्री के हिस्से क्यों? अगर सामाजिक व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के संसाधन उपलब्ध कराने में सफल हो, तो क्यों महिलाएं अपने देह का व्यापार करेंगी।

दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। देश का हर तबका इसकी चपेट में आ रहा है और विश्वभर की सरकारें अपने नागरिकों को इससे उबारने में सहायता भी कर रहीं हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक सहायता से लेकर राशन तक उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। पर भारत ही नहीं, विश्व के **अनेक देशों** में एक वर्ग ऐसा भी है, जिसके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है। उस वर्ग की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उसके पास अपनी पहचान का सबूत नहीं है। मानवाधिकारों की बात करने वाले भी उनकी चर्चा करने से हिचकते हैं। पर राहत का विषय है कि देश की उच्चतम अदालत ने उनकी पीड़ा को समझा है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि पहचान प्रमाण-पत्र पर जोर दिए बगैर यौनकर्मियों को मासिक सूखा राशन वितरण और नकद हस्तांतरण किया जाए। न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया, जिसमें महामारी के कारण यौनकर्मियों को हो रही कठिनाइयों को उजागर किया गया था।

आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1.2 लाख यौनकर्मियों के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि महामारी की वजह से इनमें से 96 प्रतिशत आबादी अपनी आमदनी का जरिया खो चुकी हैं। बड़ी संख्या में यौनकर्मियों को आधार और राशन कार्ड जैसे पहचान-पत्र न होने के कारण राहत कार्यक्रमों से बाहर रखा गया है। इन्हें पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह कोताही उस आदेश की अवहेलना है, जो उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को पहले दिया था। यौनकर्मियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण की जांच करते हुए अदालत ने 2011 में नियुक्त पैनल की सिफारिशों के आधार पर सरकार को आदेश दिया था कि वे यौनकर्मियों को राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र और बैंक खातों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का अनुमान है कि देश में लगभग नौ लाख से अधिक यौनकर्मी हैं।

देह व्यापार का मकड़जाल इतना गहरा है कि वास्तविक गुनहगार, जो मानव तस्करी कर महिलाओं को इस ओर धकेल देते हैं, वे मुक्त वातावरण में सांस लेते हैं, पर यौनकर्मी नारकीय जीवन जीने को विवश होती हैं। कलंक और घृणा के बीच उनका जीवन मुक्ति की राह चाहकर भी नहीं ढूंढ़ पाता है। ये महिलाएं आम महिलाओं की भांति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके भीतर यह भय सदा व्याप्त रहता है कि उनकी पहचान जाहिर न हो। क्या समाज की नैतिकता का ह्रास देह व्यापार के फलने-फूलने का कारण नहीं है?

भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में यौनकर्मियों को लेकर संकीर्ण मानसिकता व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी इनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति निराशाजनक रवैया रखते हैं। अमेरिका ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मदद पहुंचाने के लिए मदद की पेशकश की है, जिसमें वे लोग ऋण ले सकते हैं जो छोटे-मोटे कारोबार में संलग्न हैं, पर इसमें वह तबका शामिल नहीं है, जिन्हें कथित सभ्य समाज यौनकर्मी कहता है। हफ पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार यौन व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई ऋण नहीं देगी। ब्रिटेन में यौन कर्मियों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की, क्योंकि अधिकतर यौनकर्मी महिलाएं एकल माएं भी हैं और आर्थिक मंदी के इस दौर में प्रश्न सिर्फ उनके नहीं, उनके बच्चों के जीवन का भी है। लंदन में इंग्लिश कलेक्टिव ऑफ प्रॉस्टिट्यूट ने हजारों यौनकर्मियों को कर्मचारियों की तरह फायदा देने की मांग की है, पर क्या यह संभव है। प्रश्न है कि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं अब उनकी मदद कौन करेगा।

देह व्यापार की समस्या दुनियाभर में एक जैसी है। बांग्लादेश में यों तो इस व्यवसाय के लिए कानूनी मान्यता है, पर वहां भी उनकी स्थिति खराब हैं। द गार्जियन में पिछले दिनों प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से बांग्लादेश में एक लाख से ज्यादा महिलाएं बेघर हो गईं और भुखमरी के कगार पर पहुंच गईं। वहां की सरकार ने इनके लिए योजना बनाई है, पर वास्तविकता यह है कि वह इन महिलाओं तक पहुंच नहीं पा रही। सवाल है कि क्या वे हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, क्या देह व्यापार में उतर जाने के बाद उनका मानवीय हक छीन लिया जाना ही सभ्य समाज का अधिकार है।

● **आशीष नेमा**

अदालत के निर्देश के बाद भी नहीं सुधरे हालात

2010 में यौनकर्मियों की स्थिति सुधारने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 में संशोधन की सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की थी, ताकि यौनकर्मी संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के तहत गरिमा के साथ जीवन-यापन कर सकें। गरिमा के साथ जीवन जीना तो दूर, महिला यौनकर्मी अपने रोजमर्रा के जीवन के संघर्ष को ही नियति मान चुकी हैं। पर इस निराशा भरे वातावरण में एक राहत की बात यह है कि मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में रहने वाली यौनकर्मियों की बदतर स्थिति को न केवल समझा गया, बल्कि मानवोचित दृष्टिकोण रखते हुए महिला और बाल विकास के प्रभारी ने जुलाई माह में एक पत्र लिखकर कहा कि इन महिलाओं को कोविड-19 के दौरान आवश्यक सेवा मुहैया कराई जाए। पत्र में यह भी उल्लेख था कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम भी नहीं मिल रहा, जिससे उनके और उनके परिवार वालों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। यह पत्र स्वयं में अलग इसलिए है कि शायद पहली बार किसी ने उनके कामों को मान्यता दी है और साथ ही उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखा है।

बागी बीहड़ के लिए बदनाम ग्वालियर-चंबल अंचल अब सफेद जहर के काले कारोबार का गढ़ बन चुका है और इस जहर को आसपास के राज्यों में भी धड़ल्ले से पहुंचाया जा रहा है। जिस दूध का उपयोग लोग अच्छी सेहत के लिए करते हैं वही दूध उनको मौत के मुंह में धकेल रहा है। सफेद दूध का काला बाजार जिस तरीके से चलता है उसकी तस्वीर उतनी ही हैरान करने वाली है। यहां पीने वाला दूध किसी जहर से कम नहीं है।

चंबल में सफेद जहर

बीहड़ों और दस्यु आतंक के लिए कुख्यात चंबल अंचल अब सफेद जहर के लिए बदनाम है। यहां दूध के नाम पर भी जहर बेचा जा रहा है। इस पूरे इलाके में सिंथेटिक दूध का कारोबार इतना बढ़ चुका है कि बार-बार कार्रवाई के बाद भी दूध माफिया मान नहीं रहे हैं। खतरनाक पदार्थों से तैयार किया जाने वाला दूध सीधे तौर पर जहर है। चंबल अंचल की बात करें तो जीवन के इस सबसे बड़े पौष्टिक खाद्य पदार्थ को कुछ पैसों के लालच में मिलावट खोर सफेद जहर बना रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के वाबजूद लचीली कानून व्यवस्था के कारण यह मिलावट खोर निडर होकर यह सफेद जहर का काला कारोबार बदस्तूर जारी रखे हैं। हालांकि समय-समय पर प्रशासन कार्रवाई करता है लेकिन यह कार्रवाई यदा-कदा होने के कारण प्रशासनिक खौफ मिलावटखोरों में कम ही देखने को मिलता है। खास बात यह है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के शुद्ध पर युद्ध की मुहिम ने अंचल में मिलावटखोरों पर नकेल कसने में काफी हद तक सफलता हासिल की थी। लेकिन यह मुहिम सरकार के गिरते ही ठंडे बस्ते में चली गई और यह काला कारोबार फिर से अपनी जड़ें पसारने लगा।

ज्यादातर मिलावटखोर नकली दूध बनाने के लिए सपरेटा दूध (क्रीम लेस, जो दूध किसी काम का नहीं रह जाता) का उपयोग करते हैं, जो काफी सस्ते दाम पर मिलता है। इसके साथ रेंजी पाउडर का उपयोग झाग बनाने के लिए किया जाता। फिर **सस्ता रिफाइंड पॉमकर्नल ऑयल** की इसमें मिलावट करते है जिससे चिकनाहट और फैट, दूध में बनाया जा सके। एसएमपी पाउडर मिठास के लिए मिलाते हैं। फिर क्रीम सेपरेटर मशीन से इन सबको अच्छे से मिलाते हैं। इसके बाद नकली दूध तैयार हो जाता है। कई बार दूध बनाने के लिए यूरिया और डिटर्जेंट पावडर के इस्तेमाल की खबरें भी आती हैं।

दूध रूपी सफेद जहर सेहत के लिए बेहद घातक है। इससे इंसान धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आता है। खाद्य विभाग कार्रवाई कर दूध के सैम्पल ले जाता है लेकिन जांच रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। तब तक मिलावटखोर अपना धंधा चलाता रहता है। जब-जब सैम्पल रिपोर्ट में दूध सिंथेटिक होने की पुष्टि हुई तब-तब प्रशासन ने रासुका के तहत आरोपी पर कार्रवाई की। लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर वह इस काले कारोबार को धड़ल्ले से करने लगता है।

मप्र में 6 सहकारी (आम लोगों की नजर में सरकारी) दूध संघ हैं। ये सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों से दूध एकत्र कर उसका प्रोसेसिंग करती हैं और पैकेटबंद दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। मप्र दुग्ध महासंघ की सहकारी समितियों के लगभग 2 लाख 37 हजार पशुपालक सदस्य हैं। महासंघ का प्रतिदिन कुल दूध उत्पादन 7 लाख 40 हजार लीटर है। इनमें सबसे ज्यादा खपत वाला दूध संघ भोपाल का है, जो रोजाना 3 लाख 53 हजार लीटर दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, इनमें भी सबसे ज्यादा दूध के खरीदार भोपाल शहर के हैं। या यूं कहें कि सांची दूध भोपालवासियों की पहली पसंद और जरूरत बन चुका है। लेकिन सांची को शुद्धता की जांच में चले अभियान ने बेनकाब किया है। यहां जो दूध लोगों को पिलाया जाता रहा है, उसमें पानी मिलाने की खबरें तो दो साल पहले भी आई थीं, लेकिन अब यह डरावना खुलासा भी हो रहा है कि सांची दूध के सप्लाई टैंकरों में जहर समझे जाने वाला यूरिया और डटर्जेंट भी बेखटके मिलाया जा रहा है। यानी दूध संघ के अफसर-कर्मचारियों और सप्लायरों का गठजोड़ शहरवासियों को दूध के नाम पर धीमा जहर पिला रहा था। सांची दूध को गाढ़ा करने के नाम पर उसमें सोडियम क्लोराइड की मिलावट की जा रही है। यह न केवल जन स्वास्थ्य बल्कि पूरे समाज के प्रति गंभीर अपराध है।

वैसे तो इस देश में हर चीज में मिलावट है। चिंतन से लेकर चरित्र तक। उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर खाद्य वस्तुओं तक। विडंबना ये है कि जीवन में शुचिता की बात करने वाले हम लोग जीवन के हर क्षेत्र में मिलावट के साथ जीने के इतने आदी हो चुके हैं कि जहर मिले खाद्य पदार्थों, फल सब्जी और पेय तक निश्चिंत भाव से पेट में सरकाते जाते हैं। कहने को देश में 2011 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू हो चुका है। इसके तहत मिलावट के दोषी को 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसे और कड़ा बनाने का प्रस्ताव भी है। लेकिन ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई बहुत कम मामलों में हो पाती है। शायद इसलिए भी कि जिस देश में रेप जैसे मामलों में भी फांसी को बरसों लग जाते हों, वहां दूध में मिलावट तो केवल विश्वास का शीलभंग ही है। उल्टे कई बार कार्रवाई की आड़ में 'लेन-देन' कर मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। यदा-कदा कोई 'बदनसीब' जेल भी जाता है।

● **सुनील सिंह**

अभी तक की बड़ी कार्रवाई 2019 से 2020 तक

19 दिसंबर 2019 को मुरैना में महेश शर्मा पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। 1 फरवरी को 2020 को अम्बाह में आरोपी सोनू अग्रवाल और उसके भाई पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। 8 अप्रैल 2020 अम्बाह में सैम्पलिंग की गई। 13 नवंबर 2020 को सोनू अग्रवाल जेल से निकलने के बाद फिर यही कारोबार करने लगा। 12 नवंबर 2020 को महाराजपुरा में नकली पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 20 नवंबर 2020 को नकली दूध की फैक्ट्री कोट सिरथरा गांव में पकड़ी गई।

90 पार पहुंचा पेट्रोल

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और बीते 6 माह में ही 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। भोपाल में 90.05 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव हो चुका है। इसी तरह डीजल के दाम 80.10 रुपए के पार पहुंच गए हैं, मगर विरोध के नाम पर सन्नाटा ही पसरा है। वरना इससे आधी कीमत कुछ वर्ष पहले तक थी और 10-20 पैसे भी बढ़ने पर विपक्ष में बैठी भाजपा शहरों की सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा मचा देती थी। मगर कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जनता से जुड़े ऐसे मुद्दे जोरदार तरीके से उठाने में फ्लॉप हो रही है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से लोगों के मासिक बजट पर भी असर पड़ रहा है।

अभी कोरोना संक्रमण के चलते लोक परिवहन की बजाय लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं और यही कारण है कि अभी दीपावली पर दो पहिया से ज्यादा चार पहिया यानी कारों की बिक्री हुई। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हर 24 घंटे में कुछ पैसों की बढ़ोतरी हो जाती है और जनता को पता ही नहीं चलता। बीते 10 दिनों में ही एक से सवा रुपए प्रति लीटर तक प्रति लीटर दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है और प्रदेश से लेकर केंद्र की भाजपा सरकार ने करोड़ों रुपया टैक्स में बढ़ोतरी कर कमा लिया है। वरना जब 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा, तब रोजाना प्रदर्शन किया जाता था। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर साइकिल से सचिवालय पहुंचे थे और भाजपा के सारे नेता सड़कों पर बैलगाड़ी चलाने, धरने-प्रदर्शन से लेकर संसद में जोरदार हंगामा मचाते रहे। उस दौरान पेट्रोल-डीजल की कीमतें इतनी अधिक भी नहीं बढ़ी थी। अगर ऐसा ही रहा तो अगले 6 महीने के भीतर ही पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर आसानी से पहुंच जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑइल के दाम लगातार घटते रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के मामले में जनता को कोई राहत नहीं दी, जिसके चलते घर-घर का मासिक बजट भी बढ़ गया है, क्योंकि हर घर में कार के अलावा दो से तीन वाहन रहते हैं, वहीं डीजल वृद्धि से भाड़ा और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गईं।

दामों में हो रही वृद्धि से मप्र सरकार का टैक्स राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 11 हजार करोड़ रुपए के पार जा सकता है। सरकार इस साल पेट्रोल पर 9 प्रति और डीजल में 8 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा चुकी है। अभी मप्र में पेट्रोल पर 39 प्रतिशत और डीजल में 27 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। एक साल पहले पेट्रोल पर 30 प्रतिशत और डीजल पर 20 प्रतिशत ही टैक्स लग रहा था। दामों में हो रही बढ़ोतरी और ज्यादा टैक्स होने के कारण मप्र सरकार को सितंबर तिमाही में कुल 4495.20 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है।

यह 2019-20 की सितंबर तिमाही में 4154.10 करोड़ रुपए मिले थे। यानी अभूतपूर्व कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण अप्रैल, मई और जून में बिक्री 70 प्रतिशत घटने के बाद भी मप्र सरकार को पिछले साल से अधिक राजस्व मिलने जा रहा है। टैक्स विशेषज्ञ इस बात से खासे हैरान हैं। क्योंकि त्योहारों के समय नवंबर माह में भी पेट्रोल-डीजल की बिक्री पिछले साल से 10-15 प्रतिशत तक कम रही है।

आम आदमी, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सब लंबे समय से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती करने की मांग कर रहीं हैं। लेकिन सरकार ज्यादा कमाई होने के बाद भी आर्थिक संकट का हवाला देकर पेट्रोल-डीजल पर टैक्स नहीं घटा रही। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के विजय कालरा कहते हैं, ट्रांसपोर्टर की कमाई का 65 प्रतिशत हिस्सा डीजल खरीदने में चला जाता है। तीन माह ट्रांसपोर्टर्स के पास कोई काम नहीं था। वे कर्जों में डूबे हैं। सरकार से हमने कई बार मांग की कि मप्र में टैक्स ज्यादा है। इसे कम किया जाए। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है, डीजल के दाम यहां पड़ोसी राज्यों से ज्यादा हैं। इसलिए दूसरे राज्यों की सीमाओं पर लगे पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ गए हैं। आम आदमी की हालत तो पहले ही खराब है। ऐसे में सरकार को अब पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए। प्रदेश में अप्रैल-जून में पेट्रोल-डीजल की बिक्री 70 प्रतिशत, जुलाई से सितंबर के बीच 30 प्रतिशत और अक्टूबर-नवंबर में 20 प्रतिशत तक कम रही। इसके बावजूद सरकार को पिछले साल से ज्यादा मिल रहा है टैक्स। दिसंबर तिमाही में सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी होने का अनुमान है। 2019-20 में यह 2926 करोड़ रुपए थी। करीब 20 प्रतिशत अधिक राशि मिल सकती है।

● **जितेन्द्र तिवारी**

बिक्री पिछले साल से 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम

2019-20 में पेट्रोल-डीजल की बिक्री 786 करोड़ लीटर रही थी। यानी औसत 2.15 करोड़ लीटर की बिक्री हो रही थी। इस बार यह बिक्री घटकर जून तिमाही में 1.1 करोड़ लीटर के आसपास थी। जुलाई से सितंबर तक यह बिक्री 1.70 करोड़ लीटर रोजाना रही। अब यह बिक्री 1.90 करोड़ लीटर के आसपास चल रही है। पिछले साल मप्र में रोजाना पेट्रोल पदार्थ की बिक्री 2.20 करोड़ लीटर प्रतिदिन थी, इस बार कमाई 1.70 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। भोपाल में बीते एक माह में पेट्रोल के दामों में 1.16 रुपए व डीजल के कीमतों में 1.92 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद भोपाल में अब पेट्रोल 90.09 व डीजल 80.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। बीते 1 नवंबर को पेट्रोल के दाम 88.93 व डीजल के 78.22 रुपए प्रति लीटर थे। मप्र पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि कोरोनाकाल में खपत कम होने के कारण कच्चे तेल की कीमत कम थीं, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सामान्य होते हालातों के चलते खपत में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया हर साल ही नवंबर-दिसंबर में पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा होता है।

क्विनोवा बढ़ाएगा समृद्धि

बालाघाट जिले के नक्सल आदिवासी क्षेत्रों में अब क्विनोवा की फसल कोदो-कुटकी की जगह लेगी। जंगलों के खेतों में यह फसल न केवल आदिवासियों में पोषण बढ़ाएगी, बल्कि उनकी समृद्धि भी बढ़ेगी। जिले के 60 आदिवासी किसान 150 एकड़ में इसकी खेती करेंगे। इसकी फसल पर न मौसम की मार होगी न यह फसल बीमार होगी। निरोगी फसल के रूप में जानी जाने वाली अंग्रेजी बथुआ प्रजाति की यह फसल किसानों की समृद्धि भी बढ़ाएगी। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों ने सर्वे कर करीब दर्जन भर गांवों के 60 किसानों को चिन्हित किया है। अक्टूबर-मार्च में यह फसल लगाई जाती है।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. शरद बिसेन ने बताया कि क्विनोवा अन्य अनाजों की अपेक्षा बहुत ही पौष्टिक होता है। इसलिए इसे महाअनाज या सुपरग्रेन के नाम से जाना जाता है। क्विनोवा में प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट, ड्राइट्री फाइबर, वसा, पोषक तत्व व विटामिनों का अच्छा स्त्रोत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन ने वर्ष 2013 को क्विनोवा वर्ष घोषित किया था। शोध से पता चला है कि क्विनोवा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार की बीमारी से दूर रखते है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण डायबिटीज मरीज के लिए अच्छा माना जाता है। इसके **दाने ग्लूटीन** से फ्री होते है। अत: गेहूं से एलर्जी वाले लोग इसे खा सकते हैं। इसके फाइबर में बाइल एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रोल को बढ़ने से रोकता है। क्विनोवा में मैग्नेशियम, पोटेशियम, केल्शियम, सोडियम, लोहाए जिंक, मैग्निज, विटामिन ई, विटामिन बी.6, फोलिकअम्ल व ओमेगा.3 का मुख्य श्रोत है। इसलिए नासा के वैज्ञानिक इसे लाइफ सस्टेनिंग ग्रेन मानते हुए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्विनोवा उपलब्ध कराते हैं।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. उत्तम बिसेन ने बताया कि साउथ अमरिका की मुख्य फसल क्विनोवा पोषक तत्वों व एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। जिसके चलते ही शिक्षित समुदाय व महानगर इसकी मांग कुछ वर्षों में तेजी से कर रहे है। हर क्षेत्र में उपलब्ध न होने के कारण इसे ऑनलाइन माध्यम से मंगाया जा रहा है। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सैलानियों द्वारा भोजन में इसकी मांग की जा रही है। साथ ही भारत व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। जिसे ध्यान में रखते हुए बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गांवों के आदिवासियों को फसल के उत्पादन से पौषण मिलने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बैहर, बिरसा, गढ़ी व परसवाड़ा के नारंगी, भर्री, रेहंगी, लोरा, गुदमा, राजपुर व लगमा के 60 आदिवासी बैगा किसानों के खेतों में क्विनोवा फसल का प्रथम बार उत्पादन किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि क्विनोवा की फसल के लिए बालाघाट जिले की जलवायु उपयुक्त है। कम पानी कम लागत में ये फसल 120 दिन से 150 दिन में तैयार हो जाती है। उन्होंने बताया कि एक किलो बीज एक एकड़ खेती के लिए पर्याप्त होता है और 6 से 7 क्विंटल तक इसका उत्पादन होता है।

मप्र के खंडवा जिले का आदिवासी विकास खंड खालवा कुपोषण के लिए पूरे ही प्रदेश में जाना जाता रहा है। लेकिन अब यह क्षेत्र सुपोषण की जंग जमकर लड़ रहा है। इनकी इस लड़ाई में हथियार बना है। यह मोटा अनाज। जी हां! अब यहां पर कोदो, कुटकी, मक्का आदि पारंपरिक मोटे अनाजों की फसलों का रकबा काफी बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को इनके लाभ के बारे में लगातार जागरूक किया जाता रहा है। कोदो और कुटकी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, इससे शरीर को मिलता है। संस्था के प्रकाश माइकल बताते हैं कि वर्ष 2011 में खालवा क्षेत्र में कोदो, कुटकी की पैदावार महज दो फीसदी रह गई थी, जो कि जागरूकता के बाद बढ़कर कुल दस फीसदी हो गई है। इन फसलों का रकबा भी यहां 8 फीसदी तक बढ़ गया है। इसके साथ ही मक्का का रकबा भी तेजी से बढ़ा है। इनका कहना है कि सरकार को कोदो, कुटकी और मक्का को समर्थन मूल्य पर खरीदकर राशन दुकानों पर वितरित करना चाहिए। इससे स्थिति और बेहतर हो सकेगी।

यहां पर जागरूकता अभियान को चलाने से कुल 8 फीसदी तक रकबा बढ़ा है। वह मोटे अनाज के बारे में फायदे बता रहे हैं। बता दें कि कोदो-कुटकी के उत्पादन का सबसे बढ़ा फायदा यह होता है कि यह कोरकू, आदिवासियों की घरेलू खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। यह बिना कीटनाशक व कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देता है। कुटकी का पौधा धान की तरह ही होता है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन भरे होने के कारण यह पोषाहार के रूप में बेहतर विकल्प होते हैं।

● **लोकेन्द्र शर्मा**

अनाज से दूर हो रहा कुपोषण

मप्र के खंडवा जिले में गत दिनों हुए सर्वे में 2676 बच्चे अति कुपोषित मिले हैं। इसमें 747 खालवा में हैं। स्पंदन सामाजिक सेवा समिति भी यहां इसी काम में जुटी हुई है। समिति की सीमा प्रकाश को खालवा क्षेत्र में कुपोषण दूर करने के लिए किए गए प्रयासों पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। वह कहती है कि कुपोषण की मुख्य वजहों में आदिवासियों की परंपरागत अनाज से दूरी भी एक अहम वजह है। हमने प्रयास किया है कि आदिवासी की परंपरागत अनाज से दूरी भी एक अहम वजह है। हमने काफी प्रयास किया है कि आदिवासी कोदो, कुटकी, और मक्का की पैदावार कर इसे अपने आहार में शामिल करें, जिससे कि घरेलू खाद्य संकट की स्थिति न बनें।

खुलेगी चावल घोटाले की परतें

कोरोनाकाल में भ्रष्टाचार के जरिए आपदा को अवसर में बदलने वाले मिलर्स और अफसरों की मुश्किल बढ़ गई हैं। घटिया चावल मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली। प्रदेश सरकार के आदेश पर जबलपुर ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही थी। जांच में सामने आया कि फरवरी 2020 में समर्थन मूल्य पर धान खरीद कर राज्य सरकार ने कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलों को दिया था। उन मिलरों से मिलीभगत कर मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारियों ने बड़ा खेल किया। यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी घटिया चावल लाकर मिला दिया। ईओडब्ल्यू ने मामले में धारा 420, 272, 120बी भादवि, और आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया है।

दरअसल, सरकार धान खरीदती है जिसकी मिलिंग में कुटाई के जरिए चावल को अलग किया जाता है। एक क्विंटल धान के बदले मिलर सरकार को 67 किलो चावल लौटाता है। यहां नई धान ली तो गई लेकिन उसके बदले चावल पुराना और घटिया वापस किया, जबकि जो धान ली गई, उसी से निकला हुआ चावल वापस सरकार के पास आना था। जिसे गरीबों में वितरित किया जाता है। एसपी ईओडब्ल्यू जबलपुर देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि मंडला व बालाघाट में फरवरी 2020 में मप्र शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की गई थी। इस धान को कस्टम मिलिंग के लिए दोनों जिलों के पंजीकृत राइस मिलों को दिया गया था। संबंधित मिलरों को उक्त धान मिलिंग के बाद मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के माध्यम से पंजीकृत गोदामों में जमा किया गया था।

राज्य शासन के आदेश पर अगस्त में मंडला व बालाघाट जिले में **आदिवासी** परिवारों को खाद्यान्न वितरण के तहत चावल दिए गए थे। इन चावलों की गुणवत्ता इतनी घटिया थी कि जानवर तक नहीं खा सकते थे। पोल्ट्री ग्रेड का चावल बांट दिया गया था। मामला तूल पकड़ने लगा तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इसे लेकर दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था। इसके बाद केंद्रीय समिति गोदामों का निरीक्षण करने पहुंची थी। केंद्रीय समिति द्वारा गोदामों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में केंद्रीय समिति ने चावल के सैम्पल लेकर दिल्ली स्थित लैब में जांच कराई थी। जांच में पता चला कि चावल अपमिश्रित है। ये भी सामने आया था कि चावल को रखने वाले बारदाने दो से तीन वर्ष पुराने हैं। वहीं जांच में ये तथ्य भी सामने आया कि कुछ मिलर्स अपनी क्षमता से अधिक धान प्राप्त किए थे। अपने नाम पर धान लेकर अन्य मिलर्स से कस्टम मिलिंग कराई गई थी। कस्टम मिलिंग के दौरान मिलर्स द्वारा अन्य प्रदेशों से भी धान व चावल प्राप्त कर मिलिंग की गई है, जो संदिग्ध है।

कस्टम मिलिंग का धान जमा करते समय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाती है। पर यहां बिना जांच किए चावल गोदामों में जमा करा दिया गया। चावल की जांच नियमानुसार जिला प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भी नहीं की गई है। पूरी जांच में सामने आया कि मंडला, बालाघाट जिले के मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारियों और मिलिंग से संबंधित लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर शासन को अच्छे गुणवत्ता वाले चावल के स्थान पर अपमिश्रित और निम्न गुणवत्ता का चावल जमा करा दिया था। घटिया चावल बांटे जाने की शिकायतों के बाद केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम ने बालाघाट और मंडला जिले में गोदामों और राइस मिल्स का निरीक्षण कर 32 सैंपल लिए थे। इसकी जांच दिल्ली के कृषि भवन की ग्रेन एनालिसिस प्रयोगशाला में हुई। जांच में ये सैम्पल अनफिट और फीड कैटेगरी के पाए गए। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो चावल गोदामों से पीडीएस के जरिए बांटा गया, वह जानवरों और कुक्कुट को खिलाने लायक भर है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रालय की सितंबर में रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बालाघाट और मंडला जिले में चावल में गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराई जा रही है। मंडला के साथ बालाघाट के जिला प्रबंधक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब ईओडब्ल्यू की जांच में इस घोटाले की परतें एक के बाद एक सामने आ जाएंगी।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

सफेद चावल का काला कारनामा

बालाघाट प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में चावल की खास किस्मों, जायके और खुशबू के लिए खास पहचान रखता है। यही वजह है कि यहां के चावल की भारी डिमांड रहती है। बालाघाट बड़ा धान उत्पादक जिला है। 2019-20 में लगभग 40 लाख क्विंटल धान की खरीदी विपणन संघ ने की थी। जिले में अनुबंध के तहत राइस मिलर्स को 30 लाख क्विंटल धान चावल की मिलिंग के लिए दी गई थी। इसका 67 फीसदी राइस मिलर्स को वापस सरकारी गोदामों में जमा करना था। लेकिन अधिकारियों और राइस मिलर्स की सांठगांठ से मिलिंग से पहले ही धान को दूसरे राज्यों में बेच दिया गया। बिहार-उप्र जैसे राज्यों से घटिया चावल मंगवाकर सरकारी गोदाम में जमा करने की बात सामने आई है। बालाघाट जिले में करीब 150 राइस मिलों को मिलिंग के लिए विपणन संघ की ओर से धान दिया गया था। मिलिंग के बाद इन मिल्स ने सरकारी गोदाम में चावल जमा किए थे। नागरिक आपूर्ति निगम इस चावल की गुणवत्ता जांच गोदाम में जमा करवाता है और फिर इसे पीडीएस के जरिए बांटा जाता है। एक लाट में 580 बोरियां होती हैं। इस लाट में किसी भी एक बोरी की जांच की जाती है। पर जांच के लिए तो अच्छे चावल भेज दिए गए और गोदामों में घटिया चावल जमा करा दिया गया।

जमीन अधिग्रहण पर असमंजस

राजस्थान में कोई सुगबुगाहट नहीं

प्रोग्रेस-वे पहले श्योपुर के खातौली से शुरू होकर वीरपुर, मुरैना के गढ़ोरा, अंबाह होते हुए भिंड के शिहुदा होकर उप्र के नेशनल हाईवे 719 से जुड़ना था। बाद में इसे दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर से उप्र के दिल्ली-इलाहाबाद कॉरीडोर से जोड़ने का फैसला लेते हुए खातौली की बजाय इसकी शुरुआत राजस्थान के दीगोद से करने का फैसला लिया। राजस्थान में प्रोग्रेस-वे की लंबाई 78 किलोमीटर बढ़ गई है, लेकिन राजस्थान में इसके निर्माण कोई सुगबुगाहट नहीं है। घड़ियाल अभयारण्य को देखते हुए चंबल प्रोग्रेस-वे को चंबल नदी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1500 हैक्टेयर जमीन सरकारी है। वहीं 489 हैक्टेयर किसानों की जमीन आएगी। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी लाने के लिए चुनाव बाद नए दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। 394 किमी लंबे चंबल प्रोग्रेस-वे का काम 2017 में शुरू हुआ था। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को खर्चीला मानकर इस पर केंद्र सरकार ने काम बंद कर दिया था। विधानसभा उपचुनाव में वोट बटोरने के लिए भाजपा ने इसे अपने एजेंडा में शामिल कर प्रोग्रेस-वे का शिलान्यास करा दिया।

चंबल प्रोग्रेस-वे के लिए निजी जमीन के अधिग्रहण की सभी फाइलें मुरैना कलेक्टोरेट में दो महीने से बंद हैं। कारण है कि किसान अपनी उपजाऊ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए देने को तैयार नहीं हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा के मुताबिक अधिग्रहण के बदले दोगुनी जमीन देने के आदेश जारी नहीं किए हैं। इस हाल में 60 फीसदी किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा उपचुनाव से पहले ग्वालियर प्रवास के दौरान घोषणा की थी कि चंबल प्रोग्रेस-वे के लिए किसानों को उनकी जमीन के बदले सरकार दोगुनी जमीन देगी। यह घोषणा इसलिए करना पड़ी क्योंकि अंबाह-पोरसा समेत श्योपुर क्षेत्र के किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन चंबल प्रोग्रेस-वे के लिए देने से साफ मना कर दिया था और इस संबंध में कलेक्टर से लेकर आयुक्त तक को ज्ञापन दिए थे। उपचुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद भी प्रशासन ने चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। प्रशासन को उस आदेश का इंतजार है जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिग्रहीत जमीन के बदले दोगुनी जमीन देने की बात कही है। बता दें कि भिंड-मुरैना-श्योपुर से कोटा जाने वाले 406 किमी लंबे चंबल प्रोगेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। इसमें श्योपुर की 960.59 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसमें निजी 593.87 हैक्टेयर भूमि है तो 350.34 हैक्टेयर सरकारी भूमि है।

भिंड-मुरैना और श्योपुर से कोटा तक जाने वाले चंबल प्रोग्रेस-वे के बनने से श्योपुर सहित मुरैना संभाग के जिलों में परिवर्तन होंगे। इसमें फैक्ट्री से लेकर रोड-वे मिलने से कारोबार बढ़ेगा। यहां चंबल के बीहड़ों के बीच भी हलचल होगी और पयर्टन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मालवाहक वाहनों को आने-जाने में सुविधा होगी तो यहां कई तरह के डेवलपमेंट होंगे। यहां फैक्ट्रियां डलने से भी लोग सीधे रोजगार से जुड़ेंगे। मुरैना, श्योपुर एवं भिंड के जिन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण चंबल प्रोग्रेस-वे के लिए होना है, उनको रिझाने के लिए प्रशासन तरह-तरह के वादे कर रहा है। अधिकांश किसान नकद मुआवजा मांग रहे हैं, स्थिति यह है कि हर जिले के अफसर किसानों को मनाने के लिए अलग-अलग बातें कर रहे हैं। श्योपुर में किसानों को दोगुनी जमीन देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन जमीन के बदले दोगुनी जमीन देने का सरकार का कोई नियम नहीं आया। मुरैना में जमीन के बदले जमीन तो भिंड में किसानों को जमीन या नकद मुआवजा देने जैसी बातें कही जा रही हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान के दीगोद से लेकर श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए उप्र तक को जोड़ने के लिए 404 किलोमीटर लंबा अटल चंबल प्रोग्रेस-वे बनाया जा रहा है। भारत माला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रोग्रेस-वे की लंबाई मप्र के श्योपुर, मुरैना व भिंड जिले में 309.08 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर 6 हजार 58 करोड़ 26 लाख रुपए का खर्च आंका जा रहा है। मप्र सरकार को जमीन का अधिग्रहण कर केंद्र सरकार को देना है। प्रोजेक्ट में 52 फीसदी जमीन सरकारी तो 48 फीसदी जमीन किसानों की आ रही है। किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने का जिम्मा मुरैना, श्योपुर और भिंड जिला प्रशासन को दिया है, लेकिन अधिग्रहण 20 फीसदी भी नहीं हो पाया है। मुरैना में 55 गांव के 1700 से ज्यादा किसानों की 4200 बीघा से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होना है, पर अभी 100 किसानों से भी जमीन अधिग्रहित नहीं हुई। श्योपुर में करीब 1100 किसानों से 3000 बीघा जमीन का अधिग्रहण होना है। इनमें से जिला प्रशासन 408 किसानों की सहमति ले चुका है, लेकिन 700 किसान जमीन देने अब तक तैयार नहीं हैं। किसानों को जमीन के बदले दोगुनी जमीन देने का प्रस्ताव श्योपुर कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने चार माह पहले मप्र सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। श्योपुर में 408 किसानों से यह कहकर जमीन अधिग्रहण की सहमति ले ली है कि उनकी अगर एक बीघा जमीन जाएगी तो उन्हें 2 बीघा जमीन सरकार देगी। मुरैना में किसानों को जमीन के बदले उतनी ही जमीन देने का वादा किया रहा है।

मुरैना के डिप्टी कलेक्टर एलके पांडेय कहते हैं कि किसानों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी चल रही है। दोगुनी जमीन देने का कोई सर्कुलर हमारे पास शासन से नहीं आया, इसलिए किसानों को उतनी ही जमीन देने की बात कह रहे हैं जितनी अधिग्रहित होगी। वहीं श्योपुर के एसडीएम रूपेश उपाध्याय का कहना है कि हां श्योपुर जिले में किसानों को दोगुनी जमीन देने का वादा किया जा रहा है। श्योपुर की ओर से ही किसानों को दोगुनी जमीन देने का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था, लेकिन शासन से कोई आदेश नहीं आया। फिलहाल जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति ले रहे हैं। जबकि भिंड के एसडीएम उदयवीर सिंह सिकरवार कहते हैं कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए भिंड में जमीन अधिग्रहित होनी है। किसानों को जमीन के बदले जमीन मिलेगी या नगद मुआवजा दिया जाता है इसे लेकर चर्चा चल रही है। अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ।

● **प्रवीण कुमार**

जमीनों की जालसाजी रुकेगी

पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है इंदौरी राजस्व मॉडल

जमीनी घोटालों, भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनियों के लिए इंदौर सबसे अधिक बदनाम रहा है। राजस्व से संबंधित मामलों में कलेक्टर ने बिचौलियों, दलालों पर कार्रवाई करवाते हुए अब आम जनता से लेकर कॉलोनाइजर और बिल्डरों के लिए सीधे अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू की है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि अगले एक महीने में राजस्व से संबंधित अविवादित लंबित प्रकरणों को निराकृत कर दिया जाएगा। अभी रोजाना औसतन 300 प्रकरण निराकृत हो रहे हैं। इधर राजस्व से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि इंदौर कलेक्टर द्वारा की जा रही यह पहल सराहनीय है और पहली बार इस मामले में सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं और इंदौर का यह राजस्व मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार किसानों से लेकर आम लोगों को राजस्व के संबंध में दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े इसके निर्देश कलेक्टरों को देते रहे हैं और अभी 4 दिन पहले भी उन्होंने भोपाल कलेक्टोरेट का औचक निरीक्षण भी किया था। इंदौर कलेक्टोरेट में भी पूरा राजस्व अमला सूत-सांवल में आ गया है। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टोरेट अपनी भर्राशाही के लिए बदनाम है। लेकिन जबसे मनीष सिंह कलेक्टर बनकर आए हैं, यहां की व्यवस्थाएं धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि नई व्यवस्था से लोगों को समय पर राहत मिलेगी।

अविवादित नामातंरण, सीमाकंन, बंटवारा से लेकर राजस्व से संबंधित कार्यों को समय सीमा में करने और लोगों को चक्कर ना कटवाने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिससे जमीनों की जालसाजी तो रुकेगी ही, वहीं नामांतरण और बंटवारे के बाद खसरा रिकॉर्ड में अमल दरामत यानी रिकॉर्ड संशोधन होगा और बकायदा इसकी पावती आवेदक से नकल और रिकॉर्ड सौंपते हुए ली जाएगी। बिचौलियों से पूरी तरह से राजस्व फाइलों को मुक्त करवाते हुए कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है कि वे जारी आदेश की प्रति, ऋण पुस्तिका और रिकॉर्ड की प्रति सीधे आरआई या पटवारी से प्राप्त करें।

अभी अपर कलेक्टर, तहसीलदार या पटवारी राजस्व प्रकरणों में जो आदेश करते हैं उनकी अंतिम प्रविष्टि रिकॉर्ड में नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए किसी प्रकरण में नामांतरण आदेश किया गया मगर जब रिकॉर्ड रूम में फाइल भेजी जाती है तो उसके पहले खसरे में संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाता और ना ही उसे नकल, बी-1 और नक्शा ट्रैस की कॉपी दी जाती है। इसके चलते वह इधर-उधर चक्कर लगाता है और फिर सालों बाद जब खसरे की नकल निकाली जाती है तो पुराने व्यक्ति का ही नाम उसमें पाया जाता है, जिसके चलते कई बार जमीनों की जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। यानी रजिस्ट्री और नामांतरण, बटांकन करवा लेने के बावजूद राजस्व रिकॉर्डों में संशोधन नहीं हो पाते हैं। मगर अब कलेक्टर मनीष सिंह ने गत दिनों एक विस्तृत आदेश जारी किया है, जिससे इस तरह की सभी अनियमितताएं दूर हो सकेंगी।

इंदौर जिले में अविवादित नामांकन, अविवादित बटवारा एवं सीमांकन आदि की कार्यवाही त्वरित एवं समय-सीमा में करने के लिये कलेक्टर मनीष सिंह ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनेक राजस्व प्रकरण लोक सेवा गारंटी द्वारा विनियमित किए जा रहे हैं तथा इन सभी का उद्देश्य यह है कि आवेदकों को असुविधा न हो उनका राजस्व कार्य समय पर हो सके। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश अत्यंत स्पष्ट है तथा उनमें समय सीमा भी निर्धारित की गई है, इसका अक्षरशः पालन किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग के आदेशों का शब्दशः पालन किया जाए। तदानुसार राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी किसी भी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने के उपरांत उस प्रकरण को समाप्त कर रिकार्ड रूम दाखिले संबंधी आदेश नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी, इस आदेश में पांच कार्य दिवस का समय देते हुए संबंधित अधीनस्थ राजस्व अधिकारी-कर्मचारी को रिकार्ड अद्यतन का आदेश देंगे तथा वेब जीआईएस में अद्यतन कराया जाएगा। आदेश अनुसार प्रविष्ठियां कर अद्यतन किए गए रिकार्ड की प्रति इसी समयावधि में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

कलेक्टर मनीष सिंह जहां रोजाना तहसील कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं वहीं उन्होंने राजस्व अमले को प्रोटोकॉल सहित अन्य ड्यूटियों से भी मुक्त कर दिया है, ताकि किसी तरह की बहानेबाजी ना हो। राजस्व के संबंध में जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया उसे तत्काल प्रभाव से जहां लागू कर दिया, वहीं राजस्व संबंधित क्षेत्र के एसडीओ और अपर कलेक्टरों की जिम्मेदारी रहेगी कि वह प्रत्येक सप्ताह लंबित प्रकरणों की समीक्षा पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में जाकर करें और जिस भी कार्यालय में लंबित प्रकरण मिलेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

पूर्व में भी भू-प्रबंधन द्वारा राजस्व अमले को लैपटॉप से लेकर अन्य साधन उपलब्ध करवाए गए थे, मगर उनका इस्तेमाल कम ही हो पा रहा है। अभी कलेक्टर मनीष सिंह ने जो राजस्व सुधार लागू किए हैं उसके चलते पूरे राजस्व अमले को सुबह साढ़े 10 बजे से देर रात तक काम निपटाना पड़ रहे हैं। अभी सभी तहसीलों के 4-4 वरिष्ठ पटवारियों को भी लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जिसके संबंध में भू-अभिलेख प्रबंधन को नाम सौंपे जा रहे हैं, ताकि इन पटवारियों को जल्द ही लैपटॉप उपलब्ध हो सकें। वैसे भी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारियों को साधन-संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर की इस पहल की खूब सराहना हो रही है।

● **विकास दुबे**

बदलेंगी औद्योगिक तस्वीर

कोरोना के कारण विदेशों के साथ देश के अन्य शहरों से प्रदेश लौटे युवाओं को इंडस्ट्री से जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में 3000 प्लॉट आवंटित करने की योजना है, इनमें से आधे इंदौर के पांच क्लस्टर में होंगे। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वर्चुअल कार्यक्रम में भूमिपूजन कराया जाएगा। खास बात यह है कि इनके लिए सरकार कोई करार नहीं करेगी। जमीन आवंटित कर सीधे काम शुरू करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि जल्द लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

औद्योगिक प्लॉटों के जल्द आवंटन के लिए सरकार नई औद्योगिक और आईटी नीति का ऐलान करेगी। अब औद्योगिक जमीन फ्री होल्ड नहीं होगी, क्योंकि इससे जमीन का अन्य उपयोग शुरू होने की आशंका रहती है। उधर, नई नीति में उद्योग एकेवीएन और उद्योग विभाग दोनों के लगाए जा रहे दोहरे टैक्स से मुक्ति चाहते हैं। ये समस्या एकेवीएन के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में आ रही है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रमोद डाफरिया के मुताबिक, मंत्री सकलेचा को हमने मांगें बता दी हैं।

डीआईसी पीथमपुर क्षेत्र के संभावित निवेशकों की बैठक में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 150 उद्योगपति 1300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे 17 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पेपर इंडस्ट्री, ऑटो मोबाइल, केबल एंड कंडक्टर आदि उद्योग लगेंगे। उन्होंने निवेशकों की सूची मंत्री के सामने रखी। इन निवेशकों से मंत्री सकलेचा ने एक-एक कर चर्चा की। उन्होंने बताया नई औद्योगिक नीति घोषित की जाएगी और पीथमपुर क्षेत्र की इकाइयों को पूंजी अनुदान समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। दिसंबर में 50 फीसदी एवं मार्च तक बची हुई 50 फीसदी अनुदान राशि उद्योगों को दे दी जाएगी।

मंत्री सकलेचा ने बताया कि एमएसएमई विभाग द्वारा मप्र में लगभग 5000 हैक्टेयर सरकारी जमीन प्राप्त की जा रही है जो निवेशकों को कलेक्टर गाइडलाइन की दर से 90 फीसदी छूट के साथ दी जाएगी। इससे नए निवेशक भूमि में निवेश के बजाय प्लांट एवं मशीनरी तथा नई तकनीक में निवेश कर सकेंगे। प्रदेश में भंडार क्रय नियम में भी संशोधन किया जा रहा है, जिसमें एमएसएमई उद्योगों को अत्याधिक लाभ होगा। हरित उद्योगों को प्रदूषण प्रमाण-पत्र महाप्रबंधक सुनील त्रिपाठी द्वारा ही दिया जाएगा। हर माह अलग-अलग एक्सपर्ट के माध्यम से नए निवेशकों को मार्केटिंग तकनीक एक्सपोर्ट एवं अन्य के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि यदि किसी निवेशक को कोई समस्या आती है तो वह महाप्रबंधक त्रिपाठी एवं उद्योग आयुक्त को बताने के साथ मुझे भी सीधे मेल कर जानकारी दे सकता है।

पेपर इंडस्ट्री के मालिक राजेंद्र अग्रवाल 15 करोड़ का, ऑटो मोबाइल की ज्योति दुबे दो करोड़ व केबल एंड कंडक्टर बनाने वाली कंपनी के एमडी हिफाजत अली 12 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट कंपनी के एमडी एचएस शर्मा 12 करोड़, कोल्ड स्टोरेज के एमडी प्रकाश मकवाना 6 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की भी कंपनियां यहां आ रही हैं। औद्योगिक विकास व रोजगार के लिए इंदौर रीजन में पांच बड़े औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसमें कन्फेक्शनरी, फॉर्मा, खिलौना, फूड प्रोसेसिंग एवं फर्नीचर क्लस्टर शामिल है। इन क्लस्टरों को स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और भूमि चयन का कार्य प्रारंभ हो गया है।

वहीं पीथमपुर में मप्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा सेक्टर-4 और 5 को विकसित किया जा रहा है, जिसमें कुल 1400 एकड़ जमीन शामिल है। मगर उसमें से 600 एकड़ जमीन तो सरकारी है वहीं 800 एकड़ निजी जमीनों को लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत अधिग्रहित किया जाएगा, जिसमें 20 प्रतिशत की राशि नकद मुआवजे के रूप में और शेष 80 प्रतिशत आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के रूप में आवंटन होगा। शासन की मंजूरी के बाद 95 करोड़ रुपए की राशि 121 किसानों को 20 प्रतिशत मुआवजे के रूप में बांटी जाना है, जिसके चेक बनना शुरू हो गए हैं।

● **रजनीकांत पारे**

नया क्षेत्र होगा विकसित

मप्र औद्योगिक विकास निगम अब पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर-4 और 5 को विकसित करने की तैयारी कर रहा है। पहले एकेवीएन अलग था, मगर अब उसे एमपीआईडीसी में ही मर्ज कर दिया गया है। इसके इंदौर रीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन सक्सेना का कहना है कि पीथमपुर निवेश क्षेत्र और प्रबंधन योजना 2016 में लागू की गई थी, जिसमें औद्योगिक विकास में निजी भू-धारकों को पार्टनर बनाते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग योजना 2019 में लागू की गई। अभी सेक्टर-4 और 5 के लिए 586 हैक्टेयर यानी लगभग 1400 एकड़ जमीनों पर पहले और दूसरे चरणों में विकास किया जाना है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को दो चरणों में विकसित करने की अनुमति शासन ने भी 22.09.2020 को हुई कैबिनेट बैठक में दे दी थी, जिसके चलते 121 किसानों की लगभग निजी 320 हैक्टेयर यानी 800 एकड़ जमीन लैंड पुलिंग पद्धति से अधिग्रहित की जा रही है और इन सभी किसानों ने भी अपनी सहमति दे दी है। एमपीआईडीसी के पास पहले से अविकसित भूमि 76.19 के अलावा सरकारी भूमि 189.90 एकड़ भी मौजूद है। इस तरह निजी, सरकारी और अविकसित कुल जमीन 586 हैक्टेयर होती है, जिसमें यह प्रोजेक्ट अमल में लाया जाना है। जमीन मालिक और एमपीआईडीसी के बीच भूमि हस्तांतरण अभिलेख यानी अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

बीमारियां 3 गुना ज्यादा बढ़ीं

2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल के हजारों-हजार लोगों के लिए अभिशाप बन गई। यहां पुराने भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसो साइनेट ने हजारों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। जो बचे वो बीमारियों से ग्रस्त हो गए। गैस त्रासदी का नतीजा आने वाली पीढ़िया भुगत रही हैं। गैस त्रासदी की बरसी से ऐन पहले संभावना ट्रस्ट क्लीनिक ने गैस पीड़ितों की बीमारी के बारे में बड़ा खुलासा किया है। 15 साल के इलाज के दौरान गैस पीड़ितों में बीमारियां तीन गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। क्लीनिक के डॉ. संजय श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 15 साल में गैस पीड़ितों में करीब 3 गुना ज्यादा बीमारी बढ़ गई है। ये खुलासा संभावना ट्रस्ट क्लीनिक की मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है। 15 साल में 27 हजार 155 गैस पीड़ितों के इलाज के दौरान ये आंकड़े सामने आए। श्रीवास्तव ने बताया कि विश्लेषण में यह बात भी सामने आई है कि यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस से पीड़ित लोगों में वजन और मोटापे की समस्या स्वस्थ लोगों की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। इनमें आम पीड़ितों के मुकाबले थायराइड संबंधित बीमारियों की दर करीब 2 गुना ज्यादा है।

ट्रस्ट के प्रबंधक सतीनाथ षडंगी ने बताया कि गैस पीड़ितों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, किडनी, लीवर समेत कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि गैस पीड़ितों में थायराइड बीमारियों का दर लगभग दोगुना है। इससे ये पता चलता है कि गैस कांड की वजह से पीड़ितों के शरीर के अन्य तंत्रों के साथ-साथ अंदर के तंत्र को स्थाई रूप से नुकसान हुआ है। गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे इन संगठनों के दावे और आंकड़े डराने वाले हैं। क्योंकि सरकार तमाम स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद गैस पीड़ितों में लगातार बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस कांड की 36वीं बरसी पर संभावना ट्रस्ट क्लीनिक के सदस्यों ने हादसे के पीड़ितों में सामान्य से अधिक मोटापे और थायरॉयड की समस्या पाए जाने के आंकड़े पेश किए। साथ ही, उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ क्लीनिक द्वारा पिछले 8 महीने में किए गए समुदाय आधारित सफल काम का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।

चिकित्सक डॉ. संजय श्रीवास्तव ने कहा- क्लीनिक में पिछले 15 वर्षों से इलाज ले रहे 27,155 गैस पीड़ितों व अन्य लोगों के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया है कि यूनियन कार्बाइड से पीड़ित लोगों में अधिक वजन व मोटापा होने की संभावना सामान्य लोगों से 2.75 गुना ज्यादा है। उनमें गैस से सामान्य के मुकाबले थायरॉइड संबंधित बीमारियों का दर 1.92 गुना ज्यादा है। संभावना ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी सतीनाथ षडंगी ने कहा, गैस पीड़ितों में मोटापा ज्यादा होने से उनमें डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द और लंग्स, किडनी, स्तन और गर्भाशय के कैंसर व अन्य बीमारियों का खतरा ज्यादा होने की आशंका है। गैस पीड़ितों में थायरॉइड की दर लगभग दोगुनी पाया जाना दर्शाता है कि गैस कांड से पीड़ितों के शरीर के अन्य तंत्रों के साथ-साथ, अंत स्त्रावी तंत्र को भी स्थाई नुकसान पहुंचा है।

क्लीनिक की सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तबस्सुम आरा ने बताया कि ट्रस्ट क्लीनिक और चिंगारी पुनर्वास केंद्र के कार्यकर्ताओं ने पिछले 8 महीनों में कोरोना महामारी से जूझने के लिए 42 हजार की कुल आबादी वाली 15 मोहल्लों में जागरूकता फैलाने, समुदाय से स्वास्थ्य स्वयंसेवी बनाने, जरूरतमंदों का विशेष ख्याल रखने और कोरोना की जांच और इलाज में मदद पहुंचाने का काम किया है। हमें खुशी है कि हमारे काम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में कोरोना महामारी के खिलाफ समुदाय आधारित काम के मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। 1996 में यूनियन कार्बाइड के जहर से पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए स्थापित संभावना ट्रस्ट क्लीनिक ने अभी तक 25348 गैस पीड़ितों और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से प्रदूषित भूजल से पीड़ित 7449 लोगों का इलाज किया है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

36 साल में भी नष्ट नहीं कर पाए जहरीला कचरा

भोपाल में दो व तीन दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को हुए दुनिया के भयावह गैस कांड का 346 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 36 साल बाद भी नष्ट नहीं किया जा सका है। इसके लिए दिल्ली से आने वाली उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें इस बात का पता चलेगा कि इंदौर के पीथमपुर में नष्ट किए 10 मीट्रिक टन कचरे का पर्यावरण और प्रकृति पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बचे 346 मीट्रिक टन कचरे के निपटान की कार्रवाई तय होनी है। यह निपटान 2015 में हुआ था, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को तैयार कर भेजनी है, जो अब तक नहीं मिली है। बता दें कि यूनियन कार्बाइड कारखाने की मालिक कंपनी डाउ केमिकल्स के परिसर में 346 मीट्रिक टन जहरीला कचरा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर पीथमपुर में 10 मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया है। इस निपटान से पर्यावरण पर कितना असर-दुष्प्रभाव पड़ा, इसकी रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है। मप्र के पास इस जहरीले कचरे के निपटाने के लिए न तो विशेषज्ञ है, न कोई व्यवस्था है। इस वजह से राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। यही वजह है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। यह कचरा यूनियन कार्बाइड कारखाने के जेपी नगर स्थित कवर्ड शेड में है जो कि गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन है।

करंट से बाघ का शिकार

मप्र में जिस तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से उनकी मौत भी हो रही है। प्रदेश के लगभग सभी अभयारण्यों में वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है। शिकारियों के निशाने पर प्रमुखता बाघ होते हैं। अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन महीने पहले करंट लगाकर बाघ का शिकार करने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के साथ की संयुक्त कार्रवाई में तीनों को शहडोल जिले के सरसी गांव से दबोचा। तीनों बाघ के अंग बेचने के लिए गांव के मंदिर पहुंचे थे। आरोपियों के पास से बाघ का शरीर, सड़ी खाल, चार दांत, 10 नाखून, मूंछ के बाल जब्त किए गए। शहडोल जिले के गोहपारू रेंज में वन्य जीव निरोधक प्रोटेक्शन 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया।

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के अभिजीत रॉय चौधरी और डीएफओ उमरिया के निर्देश पर टीम ने ये कार्रवाई की। टीम को सूचना मिली थी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन महीने पहले करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया है। तस्करों ने अंगों को बेचने के लिए बाघ का शिकार किया था। अब वे इसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। इस सूचना पर टीम शहडोल पहुंची। वहां ग्राहक बनकर आरोपियों से बात की। इसके बाद तस्करों ने सरसी गांव के बाहर मंदिर के पास सौदा तय करने के लिए बुलाया। रणनीति के तहत टीम पहले ही वहां पहुंच गई। बोरी में बाघ के अंग लेकर पहुंचे तीनों तस्करों को टीम ने दबोच लिया। गिरफ्त में आए तस्करों में दो सरसी गांव निवासी विनोद व रघुवीर चौधरी और तीसरा चोरमरा गांव निवासी संतोष चौधरी है। पूछताछ में पता चला कि संतोष का एक भाई पूर्व में भालू के शिकार में पकड़ा जा चुका है। इनके अन्य अपराध के बारे में भी पता किया जा रहा है। आरोपियों ने बताया कि तीन माह पूर्व करंट लगाकर बाघ का शिकार किया था। इसके बाद बाघ के शव को जमीन में दबा दिया था। टीम आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर गई। वहां से भी बाघ के अवशेष जब्त किए गए।

बाघों की सर्वाधिक संख्या के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा पाने वाले मप्र में बाघों पर संकट कायम है। बाघों की मौत के मामले में मप्र फिर देश में पहले स्थान पर है। यहां पिछले 10 महीनों में 22 बाघों की मौत हुई है जबकि बाघों की संख्या में देश में दूसरा स्थान पाने वाले कर्नाटक में इस अवधि में सिर्फ 8, तीसरे नंबर वाले उत्तराखंड में 3 तो चौथे नंबर वाले महाराष्ट्र में 11 बाघों की जान गई है। इससे मप्र के बाघ प्रबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 की बाघ गणना में मप्र में सबसे अधिक 526 बाघ पाए गए। वहीं, कर्नाटक में 524 बाघ मिले थे। मप्र से टाइगर स्टेट का दर्जा वर्ष 2010 में छिना था। तब प्रदेश में 257 बाघ बचे थे। वर्ष 2014 की बाघ गिनती में कुछ स्थिति सुधरी थी।

महज 8 साल के अंतर से मप्र ने टाइगर स्टेट का खोया तमगा तो पा लिया, पर उसे बरकरार रख पाने में संदेह है। यहां सरकार बाघ बचा नहीं पा रही है। ऐसा भी पहली बार हुआ था जब साल के शुरुआती पांच महीने में एक भी बाघ की मौत नहीं हुई, पर जून से शुरू हुआ बाघों की मौत का सिलसिला फिर नहीं थमा। अब तक शावक मिलाकर 22 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर बाघों की मौत का कारण क्षेत्र को लेकर लड़ाई (टेरीटरी फाइट) है। जानकारों का मानना है कि बाघों की संख्या बढ़ी है तो क्षेत्र को लेकर लड़ाई लाजमी है। हालांकि तीन मामले शिकार के भी सामने आए हैं। वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉ. सुदेश वाघमारे बताते हैं कि प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ गई है इसलिए उनका रहवास क्षेत्र भी बढ़ाना होगा। अभी क्षेत्र कम है, इसलिए बाघों में लड़ाई होती है। कुछ दुर्घटना और शिकार के मामले भी हैं। जिनमें वन विभाग को चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक आलोक कुमार कहते हैं कि बाघों की संख्या ज्यादा है, तो क्षेत्र को लेकर लड़ाई के मामले भी बढ़े हैं। इस साल 95 फीसदी ऐसे ही मामले हैं। समस्या के निदान के लिए बाघों के लिए नए क्षेत्र विकसित कर रहे हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ और बाघिन का मूवमेंट

भोपाल के आसपास और रातापानी सेंचुरी में 45 बाघ और बाघिन का मूवमेंट है। इस बारे में पहली बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। इससे रातापानी सेंचुरी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन गई है। जंगल से एक और अच्छी खबर यह भी है कि यहां 12 नए शावकों की चहलकदमी भी देखी जा रही है। इसकी तस्दीक वन विभाग के ट्रैप कैमरों ने की है। इनके आंकड़े वर्ष 2022 की गणना में जुड़ेंगे, तब तक ये वयस्क हो जाएंगे। भोपाल-सीहोर में करीब 19 बाघ हैं। रातापानी सेंचुरी भी देश में पहली ऐसी सेंचुरी बनी है, जहां पर बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब यहां के बाघों के स्वभाव के संबंध में रिसर्च की जा रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि इलाका कम होने के बावजूद भी बाघ बिना टेरोटोरियल फाइट के अपना कुनबा कैसे बढ़ा रहे हैं। भोपाल के आसपास बाघों की उपस्थिति को लेकर तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जितेंद्र अग्रवाल ने सर्वे कराया तो यहां पर 80 से अधिक गुफाएं जंगल में मिली। जहां पर बाघिनें शावकों को सुरक्षित रूप से जन्म देने आती थी। इसके बाद यहां की कुछ गुफाओं को बंद करा दिया गया था। ताकि बाघ रहवासी इलाके में ज्यादा मूवमेंट न कर सकें।

सरकार सख्त प्रशासन पस्त

शिवराज के सख्त फैसलों में नए अध्याय के संकेत

उपचुनाव के बाद सरकार मजबूत होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कमर कस ली है। अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से लेकर मंत्रालय और फील्ड में पदस्थ अफसरों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की हिदायत दे दी है। सरकार के इस सख्त रुख से अधिकारी संकट में फंस गए हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वे सरकार के निर्देशों पर सख्त होते हैं तो उन पर कभी भी गाज गिर सकती है।

● राजेंद्र आगाल

म प्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान एक ऐसे शासक के रूप में होती है जो **परहित सरिस धर्म नहिं भाई** के सिद्धांत पर काम करते हैं। वे हमेशा से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए यह कोशिश करते हैं कि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, विशेषकर गरीब तबके, किसान, दिहाड़ी मजदूर, महिलाओं और विशेष पिछड़े इलाकों के रहवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए वे समय-समय पर मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के लिए गाइडलाइन बनाते रहते हैं। लेकिन उसका पालन कम ही हो पाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। जहां सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं प्रशासन पस्त नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार प्रशासन के लिए नित्य नए दिशा-निर्देश जारी कर रही है। अफसरों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे किस दिशा-निर्देश का पालन करें और किसका नहीं।

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अपने मंत्रियों और आला अफसरों को लेकर 13 साल की अपनी तीन पारियों में सामान्यत: नरम रवैया अख्तियार करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई पारी में नए अंदाज में हैं। वह अब कामकाज में कोताही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, खासकर जनता से सीधे तौर पर जुड़े मामलों में। कई मौकों पर तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव के बजाय मंत्री को ही तलब कर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। नतीजा यह मिल रहा है कि अब विभाग प्रमुखों के साथ ही मंत्री भी अलर्ट रहने लगे हैं और मुख्यमंत्री का बुलावा उनके दिल की धड़कन बढ़ा देता है।

नए अध्याय के संकेत

चुटकियों में कड़े फैसले, व्यवस्था की पड़ताल करने सीधे सड़क से सरकारी दफ्तरों का दौरा, वहीं अशांति की कोशिशों पर सीधे कार्रवाई। ये पहचान पिछले कुछ दिनों में बनी है मप्र की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग ही अंदाज में देखे जा रहे हैं, खासकर उपचुनाव के परिणाम के बाद से। विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में अंतत: भाजपा को चौहान का चेहरा आगे करना ही पड़ा था। 19 सीटों पर जीत के बाद से चौहान पूरे फॉर्म में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौहान को मप्र में सर्वमान्य ठहराने के बाद से सियासी हालात में अगल ही बयार महसूस की जा रही है। शिवराज ने लव जिहाद पर लगाम के लिए कानून से लेकर गौ-कैबिनेट तक के निर्णय लेकर अपनी कार्यशैली के नए अंदाज का अहसास करा दिया है। दरअसल, ये संकेत हैं कि प्रदेश की सियासत में उसी शिवराज दौर की वापसी हो रही है, जिसे उनके लगातार तीन कार्यकाल में प्रदेश पहले भी देखा जा चुका है। पिछले तीन कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अफसरों को मंत्रालय की बैठकों से लेकर सार्वजनिक मंचों तक पर हड़काते रहते थे। लेकिन अफसरों की चाल कभी नहीं बदली।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक खासियत यह है कि वे जनता की मानसिकता के अनुसार काम करते हैं। ऐसे में जब भी उनके सामने जनता से संबंधित शिकायतें पहुंचती हैं तो वे तत्काल नए निर्देश जारी कर देते हैं। उन निर्देशों का क्रियान्वयन हुआ या नहीं, इसकी कभी जांच पड़ताल नहीं की गई। लेकिन इस बार वे कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। न केवल वे निर्देश दे रहे हैं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। इससे अफसरों में पहले की अपेक्षा अधिक भय नजर आ रहा है।

आर्थिक गतिविधियों के लिए कसावट

उपचुनाव के बाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशासनिक कसावट में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर और आईजी-पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करने के बाद तय किया है कि वे विभागों में कसावट लाने के लिए स्वयं समीक्षा करेंगे। एक दिसंबर से यह सिलसिला शुरू होकर करीब ढाई माह चलेगा। इसमें विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को एक, दो और तीन साल की कार्ययोजना बतानी होगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित मामलों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। सबसे पहले समीक्षा राजस्व विभाग की होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री दिसंबर से फरवरी तक सभी विभागों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इसमें मंत्री और अधिकारी विभागीय कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण देंगे। आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप में विभाग के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना के आधार पर एक, दो और तीन साल के कार्यक्रम और उन्हें पूरा करने की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर विभाग की रणनीति, बजट के उपयोग की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित मामलों की प्रगति, केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रस्तावों की स्थिति के साथ अगले छह माह में होने वाले शिलान्यास, लोकार्पण और हितग्राहीमूलक योजनाओं के लाभ वितरण की भी समीक्षा होगी।

सूत्र के मुताबिक तय किया गया है कि

इस बार मंत्रियों को आर्थिक संकट से निपटने की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मंत्री आराम से न बैठें। अब एक मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी। मंत्रियों को हर माह रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। शिवराज सिंह ने सलाह दी है कि मंत्री अपने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। हर सोमवार को विभाग की समीक्षा करें। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में तेजी से काम करना है। इसके लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति अपडेट की जाए। कोरोनाकाल के कारण मप्र आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार के सामने विकास कार्यों को कराने की सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को स्पष्ट कर दिया है कि हमें आर्थिक संकट में राह निकालनी है। केंद्र की हर एक योजना में प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही जनता को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को नेस्तनाबूत कर देना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को उसके कामकाज के लिए बधाई दी है। जानकार मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मप्र में रेटिंग प्रणाली विकास की गति को रफ्तार देने के लिए लेकर आए हैं। साथ ही इससे धन की बचत भी होगी। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि किसी पुल का निर्माण होना है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। समय निर्धारित किया गया है कि इसे 6 महीने में पूरा कर लेना है। विभागीय शिथिलता की वजह से यह काम 6 महीने में पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बजट बढ़ जाता है। इससे आर्थिक नुकसान के साथ ही लोगों की असुविधा भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर मंत्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है लेकिन वे इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।

इस बार शिवराज को पूरी तरह मिला है फ्री हैंड

मंत्रिमंडल को लेकर दिए शिवराज के बयान से भी स्पष्ट है कि अब फैसले उन्हीं के हाथों में रहेंगे। शिवराज ने कहा है कि हाल-फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। चौहान की इस कार्यशैली से स्वतः साबित हो रहा है कि वह सत्ता से लेकर संगठन तक किसी के भी दबाव में नहीं है। दबाव तो पहले भी नहीं रहा होगा लेकिन उपचुनाव और कोरोना से निपटने की कोशिशों में वह बंधे से नजर आ रहे थे। अब उनकी सत्ता संख्या बल से मजबूत है और उन्हें अगले विधानसभा चुनाव तक के रोडमैप के मुताबिक परफॉर्म करना है। वैसे भी कोई मुख्यमंत्री अपने चौथे कार्यकाल तक कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। इस पड़ाव तक आते-आते सत्ता से लेकर संगठन तक उसके सहयोगियों और विरोधियों के ध्रुव स्पष्ट हो चुके होते हैं, वहीं जनता भी बदलाव पर विचार करने लगती है। चौहान बदलाव की मंशा को भांपने में कामयाब दिख रहे हैं, जो खुद एक नए नेतृत्व की तरह नए अंदाज में काम करने का मिजाज रखते हैं। इसे उनके हाल के कई फैसलों में कोई भी आसानी से देख सकता है। यह संकेत करता है कि शिवराज सिंह चौहान मप्र में सरकार को नई छवि के साथ जनता के सामने रख रहे हैं।

मुख्यमंत्री साल में कम से कम दो बार प्रत्येक विभाग की समीक्षा करेंगे। संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह बैठक के चार दिन बाद कार्यवाही विवरण अनुमोदन कराकर उसे सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग मैंनेजमेंट सिस्टम में अपलोड करेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभाग में पकड़ मजबूत करने के लिए विभागीय समीक्षा करें। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता में रखें। केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव तत्परता के साथ भेजे जाएं ताकि अधिक से अधिक राशि प्राप्त की जा सके। प्रत्येक केंद्रीय योजना में नंबर एक पर रहने के प्रयास किए जाएं। हर माह विभागों के कार्यों के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय रेटिंग करेगा।

न संवाद, न मैदानी दौरा

मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए अफसरों को जनता के हितों को प्राथमिकता देने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन अफसर इसका कितना पालन करेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अपने पूर्व के शासनकाल में भी मुख्यमंत्री ने ऐसे निर्देश बराबर दिए हैं, लेकिन अफसरों ने जनता के साथ न संवाद किया और न ही मैदानी दौरे किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो जनता से मिलने के लिए समय ही समय है, पर अधिकारियों के पास नहीं। दो साल में दो बार सत्ता परिवर्तन के बीच अधिकारियों ने जनता से दूरी बना ली है। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, वन बल प्रमुख सहित तमाम विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी जनता की पहुंच से दूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, समाधान ऑनलाइन और राज्य से लेकर तहसील स्तर तक हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई भी बंद है। इस कारण गांव से जिला स्तर तक समस्याओं का अंबार लग गया है और स्थानीय स्तर पर अधिकारी जनता की सुन नहीं रहे हैं। प्रदेश में नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद से वरिष्ठ अधिकारियों की जनता से रूबरू होने और उनकी समस्या सुनकर समाधान निकालने की परंपरा बंद हो चुकी है। न तो मुख्य सचिव का दरबार लग रहा है और न ही कलेक्टर एवं तहसील कार्यालय में कोई सुनवाई हो रही है। जिसका असर सीधे जनता पर पड़ रहा है। कोरोनाकाल में कई तरह की समस्याओं से परेशान जनता आखिर जाए तो जाए कहां। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर मैदानी अधिकारी भी सीधे लोगों से नहीं मिल रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान प्रशासनिक तंत्र को हो रहा है। सरकार तक योजनाओं और राहत कार्यों की सही जानकारी ही नहीं पहुंच रही है।

जनता से बढ़ रही दूरी

प्रदेश में जनता और अधिकारियों के बीच हमेशा से दूरी रही है। लेकिन पिछले 2 सालों में यह दूरी और बढ़ गई है। पूर्व मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह के कार्यकाल तक जनता दरबार चला। सिंह वर्ष 2018 में मुख्य सचिव थे और हफ्ते में एक दिन जनता दरबार लगाते थे। वे रूबरू या ऑनलाइन लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका मौके पर ही समाधान करते थे। उनके पहले अंटोनी डिसा ने हफ्ते में दो दिन जनता और महीने में एक दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए तय कर दिया था। इस दिन समय लिए बगैर मुख्य सचिव से मिला जा सकता था। डिसा के पहले मुख्य सचिव रहे आर परशुराम, अवनि वैश्य ने भी यह व्यवस्था बना रखी थी। वर्ष 1997 से 2001 तक मुख्य सचिव रहे केएस शर्मा ने तो कलेक्टर, कमिश्नर और प्रमुख सचिव को गांव तक पहुंचा दिया था। उनके कार्यकाल में जिला स्तर की बैठकें तहसील मुख्यालयों पर होने लगी थीं। शर्मा खुद रोजाना एक घंटा पहले मंत्रालय पहुचते थे और आम लोगों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी शिकायत सुना करते थे। पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार ने भी अधिकारियों को गांव में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए थे लेकिन अब वे आदेश सिर्फ कागजों में ही शोभा बढ़ा रहे हैं।

मप्र की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच कहती हैं कि चुनाव हो, कोरोना हो या और भी कोई स्थिति हो। अधिकारियों का तो जनता से जीवंत संपर्क होना ही चाहिए। यही तो वह कड़ी है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है। जब जनता की तकलीफ ही पता नहीं चलेगी, तो प्रशासनिक कसावट कैसे आएगी। कैसे पता चलेगा कि निचले स्तर पर क्या चल रहा है। हमेशा एक ही तरीका काम नहीं करेगा। विषम परिस्थितियों में भी जनता से संवाद बनाए रखने का तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या करना है यह तो सरकार को खुद मालूम होना चाहिए। दूसरे को बताने की जरूरत ही क्यों पड़े।

वहीं पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा कहते हैं कि अच्छे प्रशासन के लिए अधिकारियों का सुलभ होना बेहद जरूरी है। किसी राजनीतिक आपाधापी में जनता से किनारा नहीं किया जा सकता है। जब जनता से संवाद रखेंगे, तभी तो अधिकारियों को पता चलेगा कि निचले स्तर पर

कैसे तय होगी शिवराज के मंत्रियों की रेटिंग

मप्र में मंत्रियों के कामकाज के आधार पर उनकी रेटिंग तय होगी। मंत्रियों की रेटिंग उनकी मासिक रिपोर्ट कार्ड पर निर्भर करेगी। मासिक रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों को खुद ही तैयार करनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी हर महीने समीक्षा करेंगे। उपचुनाव के बाद गत दिनों शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले अपने मंत्रियों को अपनी मंशा के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा। मंत्रियों में काम के प्रति प्रतिस्पर्धा लाने के लिए मुख्यमंत्री ने रेटिंग प्रणाली की व्यवस्था की है। हर महीने विभाग के कामकाज को लेकर रेटिंग जारी की जाएगी। दरअसल, विकास की गति को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों में आत्मनिर्भर मप्र को लेकर एक रोडमैप तैयार किया था। बैठक की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार है। मंत्री इसे तेजी से अमल में लाएं। हमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें रिजल्ट देना है। प्रदेश में तेज गति से विकास और जनता का कल्याण करना है। इसके साथ ही प्रदेश में सुशासन भी सुनिश्चित करना है। हर सोमवार को मंत्री अपने विभाग के अफसरों के साथ कामकाज की समीक्षा करेंगे। मंत्री मासिक रिपोर्ट कार्ड में अफसरों से उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे। विभागीय योजनाओं के साथ-साथ केंद्र की योजनाएं कहां तक पहुंची हैं, इस पर भी संबंधित विभाग के मंत्री नजर रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के पास हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन पहुंचती है। इसी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभाग के कामकाज पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रेटिंग प्रणाली लेकर आए हैं। मंत्री हर महीने मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में सभी कामों का जिक्र होगा। मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री सभी विभागों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे। उसी के आधार पर रेटिंग तय की जाएगी कि किस विभाग ने अच्छा काम किया है। अच्छा करने वाले लोगों को वाहवाही भी मिलेगी। इस रेटिंग प्रणाली में मंत्रियों के सामने असली चुनौती यह होगी कि वे अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय के अंदर पूरा करवाएं। साथ ही जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं सही तरीके से लागू हो। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ लाभुकों तक असानी से पहुंचे, मंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए उन्हें ग्राउंड लेवल पर भी मॉनिटरिंग करनी होगी।

चल क्या रहा है। तभी जिला, तहसील स्तर पर होने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगी। योजनाओं की जानकारी मिलेगी। खामियां कहां हैं पता चलेगा। संवाद से जनता को भी भरोसा रहता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। जनता से संवाद बनाए रखने की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और आज भी कारगर है।

तबादले से चक्करघिन्नी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि अफसर उनकी मंशा के अनुसार चुस्त प्रशासन दें। लेकिन अफसरों की समस्या यह है कि वे तबादलों की चक्करघिन्नी में पिस रहे हैं। दरअसल, मप्र में एक परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि कोई भी अफसर लंबे समय तक एक विभाग या एक जगह पदस्थ नहीं रह पाता है। कई विभागों में यह स्थिति देखने को मिली है कि अफसर किसी योजना या निर्देश को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है उसे दौरान उसका तबादला हो जाता है। ऐसे में जब नया अफसर उस विभाग में आता है तो उसे नए तरीके से वही काम करना पड़ता है। इससे योजनाएं-परियोजनाएं अधर में लटकी रह जाती हैं।

मप्र में तबादलों का तिलिस्म आज तक किसी की समझ में नहीं आया है। अगर आंकड़ें उठाकर देखें तो हम पाते हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन किसी अधिकारी, कर्मचारी का तबादला न हुआ हो। तबादलों का असर सरकारी डायरी में देखा जा सकता है। हर साल सरकार डायरी छपवाती है, लेकिन डायरी छपते-छपते कई अधिकारी बदल जाते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि डायरी छपने के 6 माह के अंदर ही अधिकांश अधिकारियों, कर्मचारियों का तबादला हो जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों का पालन कैसे हो पाएगा यह सरकार के लिए सोचनीय है।

अपराधियों पर अंकुश

मुख्यमंत्री इस बार अपराध और अपराधियों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी कोई भी हो और किसी से भी जुड़ा हो, उस पर सख्ती से अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा है कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ किया कि सरकार अपराधियों के लिए वज्र से कठोर है और सज्जनों के लिए फूल से भी कोमल। अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए। भोपाल में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। अतिक्रमण करने वालों और माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। किसी को भी आमजन की जान से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी भी कार्रवाई में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गरीबों की रोजी रोटी न छिने। लोगों को समय पर सेवाएं मिलें। उन्हें किसी भी सेवा के लिए भटकना नहीं पड़े। सुशासन ऊपर से लेकर नीचे तक नजर आना चाहिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अवैध अतिक्रमण करने वालों और माफियाओं पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। यही कारण है कि राज्य के कई हिस्सों में ताकतवर लोगों की इमारतों को ढहा दिया गया है। इंदौर, जबलपुर ग्वालियर के साथ अन्य स्थानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। राज्य में पहली बड़ी कार्रवाई इंदौर में गोम्मटगिरी क्षेत्र में बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई थी। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर बनाए गए आश्रम को न केवल ढहा दिया गया था बल्कि कंप्यूटर बाबा और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर बाबा के करीबी रमेश तोमर के ठिकानों को नेस्तनाबूत किया गया। इतना ही नहीं

नगर निगम के दस्ते ने खजराना क्षेत्र के चार सूचीबद्ध गुंडों के अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। इसके अलावा जबलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे गजेंद्र सिंह सोनकर के भान तलैया स्थित कार्यालय और आलीशान बंगले के एक हिस्से को भी नगर निगम ने तोड़ दिया। गजेंद्र उर्फ गज्जू के घर पर पुलिस ने दबिश दी थी तो जुआ पकड़ा गया था और पुलिस ने साढ़े सात लाख रुपए भी जब्त किए थे। इसी तरह ग्वालियर में भी पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेता अशोक सिंह के परिजनों द्वारा संचालित मैरिज गार्डन के एक हिस्से को गिरा दिया, जिसका कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया तथा जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी बख्शा न जाए। ताकि बदमाशों के मन में खौफ होना और अपराधी तत्वों के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई हो। कांग्रेस ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाईयों पर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर की कार्रवाई पर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केके मिश्रा ने तंज कसा है और ग्वालियर कलेक्टर की इस कार्रवाई को काबिल-ए-भारत रत्न करार दिया है।

मप्र मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर

मंत्रियों और अधिकारियों पर नकेल कसने के साथ ही मुख्यमंत्री का फोकस मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन के गठन पर भी है। मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें इन दिनों तेज हो गई हैं। विगत दिनों सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के बाद संभावना जताई जा रही है अगले महिने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही निगम-मंडलों में नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। शिवराज सरकार में 5 लोगों की जगह खाली है। बताया जा रहा है कि इमरती देवी सहित उपचुनाव हारे तीनों पूर्व मंत्रियों को मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। जानकारों की मानें तो सिंधिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके हारे लोगों को सरकार में पद मिल जाए। इमरती देवी, एदल सिंह कंसाना और गिर्राज दंडोतिया शिवराज सरकार में मंत्री थे। तीनों की उपचुनाव में हार हुई है। सभी सिंधिया के कहने पर पद और विधायकी छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे में चर्चा है कि तीनों को किसी बोर्ड या निगम में जगह दी जा सकती है।

उधर, प्रदेश में भाजपा के संगठन में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही वीडी शर्मा अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। वीडी शर्मा की टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। बता दें कि सिंधिया खेमे के 6 नेताओं को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि संगठन में 3 या 4 सिंधिया समर्थकों को पद मिल सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी को पार्टी का प्रवक्ता और भांडेर से विधायक रक्षा सिरोनिया को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इमरती देवी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनका राजनीतिक कद बरकरार रखा जा सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा जल्दी ही अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। उनकी टीम के ज्यादातर चेहरे नए होंगे।

माफिया के खिलाफ अभियान

राजधानी के विकास के प्लान को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। मास्टर प्लान 2031 को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने अब भोपाल के मास्टर प्लान पर खुद अफसरों से जानकारी लेना शुरू किया है। अफसरों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने भोपाल के विकास का प्लान 2 हफ्ते में पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को शहर का सुनियोजित विकास करने के लिए जरूरी प्रावधान करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने मास्टर प्लान की खामियों को दूर करने और मास्टर प्लान को बेहतर तरीके से बनाने को कहा है। भोपाल में माफिया राज के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी मुख्यमंत्री ने संतोषजनक बताया है। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की तारीफ की और अफसरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ मुहिम चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को इस बात की भी हिदायत दी है कि विकास का प्लान इस तरीके से तैयार हो कि राजधानी प्रदेश के लिए मॉडल बने। भोपाल की सुंदरता को कायम रखते हुए विकास का प्लान तैयार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विकास के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही मेट्रो की समीक्षा कर उसे समय-सीमा में पूरा के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सुशासन पर फोकस करने को भी कहा है। भोपाल के कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अफसरों को सुशासन स्थापित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के मामले में भोपाल में रैंकिंग को सुधारने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के मामले में राजधानी को एक नंबर राजधानी बनाने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के विकास और माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रहे माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई से जनता को राहत मिलेगी।

7 दिसंबर को समीक्षा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 दिसंबर को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेंगे। इसमें मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वीसी में आत्मनिर्भर मप्र योजना, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हर जिले में मिलावटखोरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का अपडेट लेंगे। पिछली बैठक 13 नवंबर को हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन जिलों में रोजगार की दिशा में बेहतर काम होगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अफसरों की फील्ड में पोस्टिंग भी मैरिट के आधार पर की जाएगी। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के संबंध में राज्य शासन ने गत दिनों एक पत्र सभी जिलों व विभागों को भेजा है। जिसमें कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान मिलिंग, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, नवीन पात्रता पर्ची धारी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता उत्थान योजना, स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण कोविड-19 की स्थिति, एक जिला-एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसम्पत्ति की जानकारी वर्तमान स्थिति दर्ज करना तथा समस्त नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करना आदि विषयों की समीक्षा होगी।

किसान आक्रोश के भंवर में सरकार

वित्तीय पूंजी और कारपोरेट हितों के दबाव में किसान-विरोधी काले कानूनों को लागू करने की प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी तो समझ में आती है, पर लगता है, चालाक मोदी-शाह से अबकी बार इस आंदोलन की संभावनाओं के मूल्यांकन में बड़ी भूल हो गई है, जो राजनीतिक तौर पर उन्हें भारी पड़ सकती है। किसानों ने उचित ही वार्ता के लिए गृहमंत्री अमित शाह की अहंकार और धमकी भरी शर्त को खारिज कर दिया है कि पहले वे बुराड़ी ग्राउंड पहुंचे तब वार्ता होगी।

किसानों के मन में इस सरकार के इरादों को लेकर गहरा शक है, एक तरफ मोदी मन की बात में नए कानूनों के कसीदे काढ़ रहे हैं, स्वयं अमित शाह हैदराबाद में उसे दोहरा रहे हैं और दूसरी ओर वार्ता का ढोंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी केंद्र के इरादे का भंडाफोड़ कर दिया, जब अस्थायी जेल बनाने के लिए ग्राउंड्स की उसकी मांग को उसने सार्वजनिक तौर पर खारिज कर दिया। दरअसल, अपने पहले कार्यकाल में भी मोदी ने ऐसा ही दुस्साहस भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किया था, जिसमें अंततः किसानों ने उन्हें धूल चटाई थी। सरकार ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई थी। तब से वे देशी-विदेशी कारपोरेट लॉबी के निशाने पर थे। अब कोरोना का फायदा उठाते हुए उन्हें संतुष्ट करने के लिए यह नया दुस्साहस किया है। पर किसान आंदोलन जिस प्रचंड आवेग के साथ बढ़ रहा है और किसानों का जैसा दृढ़ निश्चय है, उसे देखते हुए आसार यही हैं कि सरकार फिर मुंह की खाएगी।

अगर सरकार पीछे न हटी तो आंदोलन और व्यापक आयाम ग्रहण करता जाएगा, इसकी तीव्रता और आक्रामकता बढ़ती जाएगी और यह एक लंबी लड़ाई में तब्दील होता जाएगा। जाहिर है किसानों का यह जुझारू आंदोलन देश के पूरे विमर्श को बदलकर रख देगा और देश में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावनाओं के द्वार खोल देगा। अन्ना आंदोलन की तरह, लेकिन विपरीत दिशा में, शिकारी अब शिकार बनेगा! इस आंदोलन की यह कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि अब पूरे देश में किसानों के बीच एक नया नारा गूंज रहा है, अडानी-अंबानी की ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी... कंपनी राज, हो बर्बाद। यह मोदी के साढ़े 6 साल के शासन में पहली बार हो रहा है कि किसानों को अब यह साफ समझ आने लगा है कि मोदी सरकार दरअसल अंबानी-अडानी, कारपोरेट और वित्तीय पूंजी के धनकुबेरों की सरकार है! यह ठीक वैसे ही है जैसे कभी लोकप्रिय धारणा में कांग्रेस हुकूमतें टाटा-बिड़ला की सरकार हो गई थीं और उनका पतन होता गया। यह धारणा एक बार देश के किसानों की अनुभूति का हिस्सा बन गया, तो फिर मोदी की गढ़ी गई आत्मत्याग की मसीहाई छवि और **उनके छद्म राष्ट्रवाद** की हवा निकल जाएगी। उनके कामों को देखने का, उनके बारे में सोचने का किसानों का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा और यह मोदी परिघटना के अंत का आरंभ होगा।

इस बात से कोई इंकार नहीं है कि पंजाब के किसान इस समय जबरदस्त समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें से कुछ-कुछ को उन्होंने खुद ही पैदा किया है। हालांकि ये तीन कृषि कानून उन समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको पंजाब की खेती-बाड़ी के स्वरूप में आए बदलाव पर नजर डालनी होगी। 1981 से 2011 तक के जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कुल कार्यबल की संख्या में खेतीहर किसानों और कृषि कामगारों की संख्या में गिरावट आई है। 2011 में खेती करने वालों का प्रतिशत तकरीबन 22.6 प्रतिशत था और श्रमिकों का प्रतिशत लगभग 16.3 प्रतिशत था, जिससे यह पता चलता है कि कृषि में लगे लोग पंजाब के कुल कार्यबल के 39 प्रतिशत से कुछ ही ऊपर हैं। कृषि से दूर इस बदलाव को समझने के लिए जरूरी है कि भू-स्वामित्व और खेतीबाड़ी करने के स्वामित्व के बीच के फर्क को समझा जाए। जहां तक भू-स्वामित्व का सवाल है, तो ज्यादातर लोग सीमांत या छोटे-छोटे जोत वाले भू-स्वामी हैं। भू-स्वामी वर्ग के कई लोग या तो सफेदपोश नौकरी करने शहर का रुख कर गए हैं या विदेश चले गए हैं, और यह प्रवृत्ति निरंतर जारी है, या फिर वे इतने बुजुर्ग हैं कि अपनी जमीन पर खेती करने लायक नहीं रह गए हैं। जो लोग खेती करते हैं, उनके पास छोटी-छोटी जोते हैं और अक्सर ये लोग उन लोगों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, जो गांवों से बाहर निकल गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पंजाब में कृषि पर निर्भर लोगों की कुल तादाद 1981 से काफी कम हो गई है।

● **राजेश बोरकर**

कई समस्याओं से घिरे किसान

पंजाब की कृषि की खासियत उसकी एकल कृषि है। यहां बारी-बारी से गेहूं-धान की खेती की जाती है। फसलों की विविधता 1967 यानी हरित क्रांति के शुरुआती साल से ही गायब हो गई है। समय के साथ पंजाब में किसानों के बाजार उन्मुख होने की वजह से कई फसलें गायब हो चुकी हैं। किसी जमाने में बठिंडा और मनसा जिले तो तकरीबन रेगिस्तान थे। जब सिंचाई की नहर प्रणाली वहां पहुंची, तो ये क्षेत्र भी एकल-कृषि वाले क्षेत्र हो गए और पानी की आसान उपलब्धता के चलते यहां धान की खेती शुरू हो गई। यह पंजाब के हित के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले सालों में इस सूबे को मामूली नहीं, बल्कि एक जबरदस्त जलसंकट का सामना करने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंचाई के लिए पंजाब के किसानों को बिजली की आपूर्ति मुफ्त की जाती है और इससे भू-जल का व्यापक दोहन हुआ है। सरकार द्वारा गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने के साथ-साथ कहीं ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत वाले इन फसलों की खेती जारी है। यहां कीटनाशक के बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होना भी एक समस्या है। पंजाब का शहरी मध्यम वर्ग पंजाब में उत्पादित गेहूं नहीं खरीद रहा है। वे मप्र से गेहूं खरीदते हैं और मल्टीग्रेन या तैयार आटे का इस्तेमाल करते हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति बड़ी-बड़ी कंपनियां कर रही हैं। सब्जियों की कहानी भी इस कहानी से अलग नहीं है। पंजाब की सब्जियों में कीटनाशक की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि किसान कीटनाशक के इस नुकसान पहुंचाने वाले असर से बेखबर हैं। वे अपने खुद के खाने के लिए इसे अलग से उपजाते हैं।

क्या बदलेगी भाजपा की राजनीति?

बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन वहां की जनता ने भाजपा के कई मुद्दों को नकार दिया। इससे संभावना जताई जा रही है कि भाजपा आने वाले दिनों में अपनी रणनीति में बदलाव करेगी।

बिहार चुनाव में बदलाव की बयार के बरक्स चुनाव नतीजे आश्चर्यजनक रहे हैं। महागठबंधन की 110 सीटों के मुकाबले एनडीए ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए की जीत पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नजदीकी अंतर वाली 20 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को प्रशासन की मिलीभगत से हराया गया है। चुनाव आयोग से उन्होंने इन सीटों पर फिर से मतगणना कराने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव की मांग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन यह निश्चित है कि इस चुनाव का भारतीय राजनीति पर दीर्घकालीन असर होगा। इसलिए इस चुनाव के मायने समझने होंगे।

वामदलों का उभार भी इस चुनाव का महत्वपूर्ण पहलू है। सीपीआई (माले), सीपीआई और सीपीएम तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां महागठबंधन में शामिल थीं। 2015 में केवल 3 सीटें जीतने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 पर जीत हासिल की। इनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन माले का रहा। माले ने 16 सीटों में से 12 पर जीत हासिल की। माले ने इस चुनाव में दलित और पिछड़े नौजवानों को तरजीह दी। जातिगत समीकरणों को ठीक से समझते हुए माले के नेताओं ने जमीन पर मेहनत की। राजद के समर्थन का भी उसे फायदा मिला। बंगाल से सीमा साझा करने वाले बिहार में आजादी के बाद से ही कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आंदोलन का प्रभाव रहा है। लेकिन बिहार में वामपंथी राजनीति का विशेष उभार नहीं हो सका।

80 और 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जातियों और पसमांदा मुसलमानों को जोड़कर आगे बढ़े, उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने जाति को तवज्जो न देकर मजदूर और किसान आधारित वर्ग की राजनीति को ही आगे बढ़ाया। हिन्दुत्व के उभार के साथ अगड़ी जातियां भाजपा के साथ चली गईं। परिणामस्वरूप वामपंथी राजनीति आधारविहीन हो गई। लेकिन इस चुनाव में माले ने पिछड़ी जातियों के नौजवानों को आगे करके चुनाव लड़ा और जीता। इस दौर में वामपंथी दलों की जीत ज्यादा मायने रखती है।

पिछले 6 साल में भाजपा की सत्ता और आरएसएस खुलकर वामपंथ पर हमलावर हैं। इस पूरी वैचारिकी को सुनियोजित तरीके से बदनाम किया गया। वामपंथियों को नक्सलवादी और विदेशी विचारधारा का पोषक घोषित किया गया। वामपंथ समर्थक बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सल कहा गया। हिंसक हिन्दूवादी संगठनों द्वारा एमएम कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश की हत्या की गई। भाजपा समर्थकों ने इन हत्याओं को न्यायसंगत ही नहीं ठहराया बल्कि जश्न भी मनाया। कवि वरवर राव, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, जीएन साईंबाबा, फादर स्टेन स्वामी जैसे कई प्रख्यात बुद्धिजीवियों पर यूएपीए और सीडीशन जैसी संगीन धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया। भाजपा का आईटी सेल और आरएसएस द्वारा वामपंथियों को हिंसक, हिंदू विरोधी और देशद्रोही तक घोषित किया गया है। जेएनयू पर लगातार हमला होना इसका हिस्सा है।

बिहार चुनाव की एक स्थाई महत्ता है। इस चुनाव में भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चल सका। हालांकि इसकी भरपूर कोशिश हुई। सांप्रदायिक एजेंडे के लिए उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया गया था। उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दों पर बात की। लेकिन सीमांचल में योगी आदित्यनाथ द्वारा घुसपैठियों को बाहर निकालने की हुंकार को नीतीश कुमार ने ही 'फालतू बात' कहकर खारिज कर दिया। चुनाव प्रचार के पहले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। सैनिकों की शहादत को उन्होंने मुद्दा बनाना चाहा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में दो बिहार के सैनिक शामिल थे। बिहार के शहीदों के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगने की कोशिश की। लेकिन जनमानस पर इन मुद्दों का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों को छोड़ दिया।

चुनाव में कई दबे मुद्दे आए बाहर

पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बिहारी मजदूर प्रताड़ना और अपमान का शिकार होते हैं। नीतीश के 15 साल के शासनकाल में कई चीनी मिलें बंद हो गईं। अन्य उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। नए कल कारखाने स्थापित नहीं हुए। इससे रोजगार के अवसर कम हुए। तेजस्वी ने सीधे जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। वे कहीं भटके नहीं। हिंदू अस्मिता के बरक्स तेजस्वी ने बिहारी अस्मिता को खड़ा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार का चुनाव विकास और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रहा। यह तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। तेजस्वी अपना एजेंडा स्थापित करने में कामयाब रहे। आने वाले चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द हों तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तेजस्वी ने बिहार में भाजपा ने हिंदुत्व और विभाजन के नैरेटिव को चलने नहीं दिया। उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव खड़ा किया। सांप्रदायिकता के बरक्स रोजगार और विकास का काउंटर नैरेटिव। तेजस्वी ने भाजपा और नीतीश को अपने एजेंडे पर आने के लिए मजबूर किया। चुनाव के नतीजे कुछ भी रहे हों लेकिन बिहार चुनाव का हासिल बहुत मानीखेज है।

तेजस्वी का दिखा चमत्कार

सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के बावजूद तेजस्वी यादव बिहार चुनाव का सबसे आकर्षक और विश्वसनीय चेहरा बनकर निखरे। उनकी रैलियों में नौजवानों की उमड़ी भीड़ तेजस्वी में नए बिहार की उम्मीद देख रही थी। इसकी वजह केवल उनका नौजवान होना ही नहीं है बल्कि उन्होंने अपने भाषण और नीतियों से सबको प्रभावित किया है। लंबे अरसे के बाद भारत की राजनीति में बेरोजगारी और महंगाई चुनावी मुद्दे बने। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने का वादा किया। सरकारी नौकरियों के मुद्दे की अपील ने नीतीश कुमार और भाजपा को रक्षात्मक प्रचार करने के लिए मजबूर कर दिया। निजी हमला करते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा कि सरकारी नौकरियां कहां से देंगे और इसके लिए राजस्व का इंतजाम कहां से होगा? तेजस्वी ने पूरी तैयारी के साथ ऐसे सवालों का जवाब दिया।

हमेशा की तरह इस चुनाव में भी पाकिस्तान आया। लेकिन इस बार थोड़े जुदा अंदाज में। पुलवामा में हुए हमले का जिक्र करते हुए इमरान सरकार के एक मंत्री फवाद चौधरी ने इसे पाकिस्तान सरकार और कौम की कामयाबी बताया। विरोधियों ने इसकी टाइमिंग को लेकर शंका जाहिर करते हुए भाजपा पर सवाल उठाए। क्या पाकिस्तान के साथ भाजपा नेताओं की कोई सांठगांठ है? क्या बिहार चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए यह बयान दिलवाया गया है? अथवा यह महज इत्तेफाक है? यह सवाल बराबर बना रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार चुनाव में भाजपा का हिंदुत्व का मुद्दा हावी नहीं हो सका। तब नरेंद्र मोदी ने इसके विपरीत जाकर एक रैली में पूछा, क्या एनआरसी-सीएए से किसी की नागरिकता खत्म हुई?

भाजपा चुनावी रणनीति में कई स्तरों पर काम करती है। हिंदुत्व उसका स्थाई चुनावी मुद्दा ही नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा है। प्राथमिक एजेंडा है। भाजपा का लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र। बहुमत आधारित संसदीय लोकतंत्र में भाजपा और संघ हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को अपना दायित्व ही नहीं बल्कि अधिकार भी समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब उनके लिए सिर्फ बहुमत है। जबकि लोकतंत्र का असली मकसद कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की रायशुमारी है। लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना बहुमत का। लेकिन संघ और भाजपा के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत है। बहुमत उनके लिए सत्ता प्राप्त करने का महज एक हथियार है। भाजपा और संघ विशेषकर कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद जैसे दलों ने सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। लेकिन संघ और भाजपा ने दलित, आदिवासियों और पिछड़ों पर आधारित राजनीति को यानी सामाजिक न्याय के प्रश्न को सीधे तौर पर कभी खारिज नहीं किया। हिंदुत्व के भीतर इन समुदायों की क्या हैसियत है, यह किसी से छिपा नहीं है। आरएसएस स्त्रियों के प्रति आज भी संकीर्ण और असंवेदनशील है। मोहन भागवत सिर्फ आरक्षण की समीक्षा की ही बात नहीं करते बल्कि वे खुले तौर पर स्त्री विरोधी बयान देते हैं। उनका यह वक्तव्य गौरतलब है कि पत्नी अगर पति की सेवा ना करे तो पति उसे त्याग सकता है।

यह दरअसल, मनुस्मृति के विधान का 21वीं सदी वाला संस्करण है। गनीमत है कि उन्होंने ऐसी स्त्री को शारीरिक दंड देने की बात नहीं कही। इन सब विसंगतियों के बावजूद संघ हिंदू बहुमत के साथ होने वाले अन्याय का नैरेटिव गढ़ने में सफल हुआ है। इस नैरेटिव से ध्रुवीकरण करके चुनाव में सफलता भी मिली है। जबकि बहुमत के नैरेटिव की सच्चाई कुछ और है। 1966 में भारत में फ्रांस के राजदूत ने एक लेखक से बातचीत में कहा था कि अगर भारत का लोकतंत्र सफल होता है तो यहां बहुजनों की सत्ता स्थापित होगी क्योंकि इनका बहुमत है। जाहिर तौर पर बहुमत के आधार पर सत्ता दलित और पिछड़ों के पास होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का सवाल राजनीति के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन भाजपा और संघ के हिंदुत्व में सामाजिक न्याय का सवाल नहीं होता बल्कि पारंपरिक सामाजिक सत्ता को बरकरार रखने की चिंता होती है। इस सामाजिक सत्ता में सवर्णवाद के साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी शामिल है।

चुनाव में जब हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलता है तब भाजपा-संघ कथित जातिवाद की राजनीति का मुद्दा सामने लाते हैं। जातिवाद की राजनीति का सच क्या है? दरअसल, यह 80 और 90 के दशक में दलित और पिछड़ों के उभार वाली राजनीति है। इसे मंडल की राजनीति भी कहा जाता है। विदित है कि मंडल की राजनीति में नेतृत्व पिछड़ी जाति के नेताओं के पास था। सामाजिक न्याय की दूसरी किश्त में बीपी मंडल आयोग की अनुशंसा को वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया। पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सरकार बनाम इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों के 27 फीसदी आरक्षण को न्यायसम्मत मानते हुए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी। आरक्षण से प्राप्त विशेष अवसर का लाभ उठाकर पिछड़ी जातियां मजबूत हुईं। उनमें जातिगत चेतना और शोषण के प्रति रोष भी पैदा हुआ। इससे सदियों से अनवरत स्थापित सामाजिक सत्ता को चुनौती मिली।

सरकारी नौकरियों में पिछड़ों की बढ़ती भागीदारी का एक सच यह भी है कि हाशिए की कमजोर जातियों को इसका विशेष लाभ नहीं मिला। मजदूरी, दस्तकारी और पशुपालन पर जीवन गुजारा करने वाली छोटी जातियों को पेट भरना भी मुश्किल था। जबकि आरक्षण का फायदा तो पढ़े-लिखे लोगों को मिलता है। इसी के मद्देनजर यूपीए सरकार के समय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने 2005 में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किया। लेकिन सवाल जातिवाद का है। जेपी आंदोलन से निकले नेताओं के सत्ता में पहुंचने के कारण उनकी अपनी पिछड़ी जातियां मजबूत हुईं। आरक्षण से भी उनका सशक्तिकरण हुआ। समाज का शक्ति संतुलन बदलने लगा। यादव, कुर्मी, जाट जैसी जातियां अब सवर्णों के बरक्स खड़ी हो गईं। इसे सामाजिक परिवर्तन कहा गया। आज बिहार की राजनीति में इनका वर्चस्व है।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस केंद्र के साथ ही राज्यों में भी धीरे-धीरे पस्त होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस को दमदार नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। आज देश में जहां भाजपा की जड़ें मजबूत हो रही हैं, वहीं कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। इससे पार्टी का भविष्य सवालों में घिरा हुआ है।

राज्यों में पस्त होती कांग्रेस

भारत की आजादी के पश्चात कांग्रेस ने लंबे समय से केंद्र और राज्यों में शासन किया। बदलते हुए समय के अनुसार अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उसकी विपक्षी दर्जे के दौरान औपचारिकता भी पूरी नहीं हो पाती और उसके अनुसार उसकी सीटें भी नहीं आ रहीं। एक समय ऐसा था कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार होती थी और लंबे समय तक चली भी। बदलते समय के अनुसार अब विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस की अनेक जगह पर तो हालत ऐसी है कि उसका खाता भी नहीं खुल पाता। लोकसभा चुनाव में तो उसकी हालत इतनी खस्ता है कि वह बड़े राज्यों में लंबा शासन करने के बाद भी उसके सदस्य ही बड़ी मुश्किल से जीत पाते हैं। बल्कि इस बार के चुनाव में तो अपनी सीट गंवा कर कांग्रेस एक सीट जीतकर उप्र जैसे बड़े राज्य में अपनी इज्जत ही बचा पाई।

इस तरह से लगातार चुनाव हारने के पश्चात कांग्रेस इस बात की समीक्षा नहीं कर रही कि उसके कमजोर होते जाने के पीछे क्या वजह है। बदलते समय के अनुसार अपने विधायक तथा संसद सदस्य और पुराने समय में कांग्रेस में जुड़े हुए अनेक नेता इस दुर्गति को देखते हुए कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। कांग्रेस को अपनी विचारधारा तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने पर जमीन से जुड़े नेताओं की कद्र करनी होगी। मौजूदा कांग्रेस की यही हालत रही तो आने वाले समय में विभिन्न राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी।

कांग्रेस के लिए बिहार का विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनाव एक बड़ा मौका था, जहां वह बेहतर प्रदर्शन कर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर सकती थी। क्योंकि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी के बाद मचा बवाल हो या आंतरिक चुनाव कराने की मांग को लेकर पार्टी नेताओं की बयानबाजी, यह कहा जाने लगा था कि चुनाव जीतना तो दूर, कांग्रेस अपने संगठन को ही दुरुस्त नहीं रख पा रही है। ऐसे में बिहार के साथ ही मप्र, गुजरात, उप्र के उपचुनाव में उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें लगी हुई थीं। लेकिन नतीजे आने के बाद उसने उससे सशक्त विपक्ष बनने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को सिर्फ निराश ही किया है।

इसी तरह गुजरात में वह 1 भी सीट नहीं जीत पाई, मप्र में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, विधानसभा के 2018 के चुनाव में इनमें से 27 सीटें उसने जीती थी लेकिन इस बार उसे सिर्फ 9 सीटें मिलीं। उप्र में 7 सीटों के उपचुनाव में प्रियंका गांधी प्रचार करने तक नहीं आईं और पार्टी बुरी तरह धराशायी हो गई और सिर्फ 1 सीट पर वह दूसरे नंबर पर आई है। 2015 में कांग्रेस आरजेडी, जेडीयू महागठबंधन के भरोसे

राहुल को फिर अध्यक्ष बनाने की तैयारी

कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्यसमिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगेगी। अधिवेशन में नई कार्यसमिति के 12 सदस्यों का भी चुनाव होगा, वहीं अन्य 12 सदस्य चुनने का अधिकार नए अध्यक्ष को होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अध्यक्ष चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और इसे टाला नहीं जा सकता। वहीं, राहुल समर्थक नेता भी आश्वस्त हैं कि बिहार व कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजों को संगठन के नेतृत्व से नहीं जोड़ना चाहिए। राहुल के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते भी हैं। इससे पहले, कांग्रेस के 23 नेताओं के नेतृत्व के खिलाफ मुखर व खुला पत्र लिखने के बाद सोनिया गांधी ने कार्यसमिति की बैठक में पद छोड़ने की पेशकश की थी। काफी मान मनौव्वल के बाद वह अगले चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष पद संभालने को तैयार हुई थी। लिहाजा अब कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद पार्टी कार्यसमिति की बैठक बुलाकर उसमें फैसला लेना चाहती है।

चुनाव लड़ी थी, इस बार भी वह आरजेडी के साथ महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ी। नतीजे बताते हैं कि अगर उसे गठबंधन में जगह न मिले, तो वह शायद शून्य से आगे न बढ़ पाए। इसका मतलब साफ है कि बिहार में कांग्रेस संगठन की हालत बदतर है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उसके बेहद पस्त सांगठनिक ढांचे की वजह से ही उप्र में लोकसभा चुनाव से पहले बने बीएसपी, एसपी और आरएलडी के महागठबंधन में उसे जगह नहीं मिली थी। इसके बाद वह अकेले लड़ी लेकिन उसे सिर्फ एक सीट मिली और कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी भी कांग्रेस गंवा बैठी।

बिहार और कई राज्यों के उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर एक बार फिर स्थायी अध्यक्ष के चयन का मसला जोर पकड़ सकता है। कांग्रेस डेढ़ साल से किसी तरह घिस-घिसकर चल रही है। प्रियंका और राहुल आम लोगों के मुद्दे सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं लेकिन इतने भर से भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में काम कर रहे नेता स्थायी अध्यक्ष के मसले का हल चाहते हैं। शशि थरूर से लेकर कई नेता इस पर बोल चुके हैं लेकिन पार्टी कोई फैसला ही नहीं ले पाती। वह चाहती है कि हाईकमान के खिलाफ कोई नेता आवाज न उठाए। हाल ही में गुलाम नबी आजाद के पर कतरकर उसने यह संदेश दिया भी था।

लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि राज्यों में उसकी पस्त होती हालत उसे राष्ट्रीय राजनीति में बौना कर देगी। दूसरी ओर, भाजपा तेजी से विजय अभियान की ओर बढ़ रही है। बिहार में उसने अपनी सीटों में जबरदस्त इजाफा किया है और अब वह बंगाल, असम, केरल के विजय अभियान पर निकल पड़ी है। इन तीनों ही राज्यों में अगले 6-7 महीनों में चुनाव होने हैं और यहां कांग्रेस दूसरे दलों के भरोसे है और वह खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं दिखती। ऐसे में पार्टी को आगामी चुनौतियों के लिए कमर कसनी होगी वरना 'कांग्रेस मुक्त भारत' के रास्ते पर चल रही भाजपा 2024 तक कांग्रेस जिन राज्यों में है, वहां से भी उसे उखाड़कर उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म करने की जल्दी में है।

बिहार में महागठबंधन सत्ता से महज कुछ सीट दूर रह गया। कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और राजद के मुताबिक, उसके सहयोगी दल ने चुनावों में उतनी मेहनत नहीं की जितनी की जानी चाहिए। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने सीधे-सीधे कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। बकौल तिवारी, चुनाव अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है? उन्होंने कहा कांग्रेस ने चुनाव में 70 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 70 सार्वजनिक रैलियां भी नहीं कीं। राजद का यह आरोप खोखला नहीं है। राहुल गांधी के चुनावों के बीच या ठीक बाद, छुट्टियों पर चले जाना पहले भी सहयोगियों, यहां तक कि कांग्रेसियों को भी पसंद नहीं आता रहा है।

नेतृत्व क्षमता पर ढेरों सवाल

अब दूसरी बात पर आते हैं। कांग्रेस के ऐसे प्रदर्शन के कारण तो राज्यों में क्षेत्रीय दल उसके साथ गठबंधन बनाना ही छोड़ देंगे। जिस पार्टी ने देश की आजादी के बाद कई वर्षों तक एकछत्र राज किया हो, आज उसकी हालत यह है कि वह गिने-चुने राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है और महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार में एक सहयोगी दल की भूमिका में अपनी सियासी इज्जत बचा रही है। कांग्रेस के पास राज्यों में बड़े सहयोगी दलों के नाम पर आरजेडी के अलावा एनसीपी, डीएमके और जेडीएस बची है। बंगाल में वह तृणमूल कांग्रेस के, असम में एआईयूडीएफ के, उप्र में एसपी-आरएलडी के सहारे की बाट जोह रही है। लेकिन ऐसे हालात में कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर खुद का नुकसान नहीं करना चाहेगा। वह राज्य में ही कांग्रेस का विकल्प ढूंढने की कोशिश करेगा और अगर वह उससे गठबंधन करेगा भी तो बेहद कम सीटें देगा। ये बात राजनीतिक वास्तविकता से दूर नहीं है और इसका सीधा असर यह होगा कि अगर कांग्रेस राज्यों में लगातार कमजोर होती जाएगी तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका खत्म हो जाएगी।

पिछले साल दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव थे। आखिरी चरण के लिए प्रचार चल ही रहा था कि राहुल गांधी साउथ कोरिया चले गए। उसी वक्त देश में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ भी प्रदर्शन जोर पकड़ रहे थे। झारखंड के चुनावी समर से राहुल ने हाथ खींचे तो पार्टी ने आनन-फानन में प्रियंका गांधी को पाकुर में रैली करने भेजा। जबकि प्रियंका ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में प्रचार नहीं किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा में जब पिछले साल विधानसभा चुनाव करीब थे, राहुल गांधी ने कम्बोडिया का प्लान बना लिया। 21 अक्टूबर से चुनाव होने थे लेकिन राहुल 11 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे। उनकी गैर-मौजूदगी पर कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी महसूस की गई थी। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रणव झा ने कहा था कि राहुल गांधी की निजी स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए।

महाराष्ट्र में जब चुनाव खत्म हुए तो राजनीतिक सांठ-गांठ का सिलसिला शुरू हुआ। भाजपा और शिवसेना अलग हो चुके थे और नए समीकरण बन रहे थे। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को लेकर सरकार बनाना चाहती थी लेकिन राहुल देश में नहीं थे। उस वक्त, राहुल के यहां न होने से पार्टी वक्त रहते फैसले नहीं कर सकी। दूसरी तरफ, भाजपा ने एनसीपी में सेंध लगाकर शपथ ग्रहण करा दिया। हालांकि बाद में तीनों पार्टियां एक साथ आईं और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं का मानना था कि राहुल की गैर-मौजूदगी के चलते पार्टी शुरुआत में हिचकती रही।

2018 में कर्नाटक के भीतर कांग्रेस संकट से जूझ रही थी। जेडीएस के साथ उसका गठबंधन टूटने के कगार पर था। इसी बीच, राहुल गांधी का ट्वीट आया कि वे विदेश जा रहे हैं। उसी दौरान, वेटरन कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का निधन हुआ। उनके संस्कार में भी राहुल शामिल नहीं हुए थे। 2017 में पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई थी। इसके बाद राहुल गांधी के दिल्ली में एक हॉलीवुड मूवी देखने जाने की बातें सामने आईं। भाजपा ने भी राहुल के इस कदम का खूब मजाक उड़ाया था। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को ट्वीट कर सफाई देनी पड़ी कि राहुल किसी अन्य भारतीय की तरह हैं, वे भी फिल्में देखते हैं।

● इन्द्र कुमार

नक्सलवाद के खात्मे का ब्लू प्रिंट तैयार

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच पिछले दिनों दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के 28 जिलों में से 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं। पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से यहां नक्सवाद ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। पुलिस और सुरक्षाबलों ने अब जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ साझा रणनीति बनाकर काम करना शुरू किया है उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉइंट ऑपरेशन कर नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने की तैयारी है। पैरामिलिट्री फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स के अधिकारी नक्सलियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई की बात कह रहे हैं।

नक्सल समस्या पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है जिससे नक्सलियों का हौसला बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार नक्सलियों को घुसकर मारने का काम कर रही है। पहले भाजपा सरकार में नक्सली पुलिस कैंपों पर हमला करते थे, लेकिन अब पुलिस फोर्स नक्सलियों के कैंप में घुसकर उन्हें मार रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा रणनीति नक्सलियों के खात्मे के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि यदि दोनों सरकारों की साझा रणनीति काम कर जाती है तो राज्य से नक्सलवाद का सफाया होना तय है।

विगत दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की सलाह दी है, ताकि युवा नक्सली समूहों में शामिल न हों। बघेल ने पत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों, खासतौर पर बस्तर के विकास के लिए पांच सुझाव दिए हैं और केंद्र से सहयोग की मांग की है। शाह को लिखे पत्र में बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगार लोग नक्सली गुटों में शामिल न हों। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बघेल ने शाह को पत्र लिखकर बस्तर अंचल में नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बघेल ने पत्र में लिखा कि बस्तर में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार लोग विवश होकर नक्सली समूहों में शामिल न हों।

गौरतलब है कि पहले नक्सली हाईवे पर स्थित गीदम में थाना लूट लिया करते थे, अब अबूझमाड़ में भी उनकी इतनी हिमाकत संभव नहीं है। साल 2013 में झीरम में कांग्रेस नेताओं के नरसंहार तक नक्सलियों की दीदादिलेरी चलती रही, पर अब हालत बदल गए हैं। फोर्स उनकी मांद तक जाकर चुनौती दे रही है। बस्तर के जंगलों में 6 अरब की लागत से सड़कें बन रहीं हैं। इंजरम से भेज्जी, दोरनापाल, बासागुड़ा व दंतेवाड़ा से नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले जगरगुंडा तक सड़क बन रही है। दंतेवाड़ा से नारायणपुर को जोड़ने वाली बारसूर पल्ली सड़क नक्सलियों ने दशकों तक बंद रखी। अब इंद्रावती के उस पार घने जंगलों में फोर्स के कैंप खुल गए हैं। उन गांवों में राशन दुकान खुली, तो वनवासियों ने बस्तर आईजी सुंदरराज पी को कंधे पर उठाकर नृत्य किया। नक्सलवाद के खिलाफ पहली बार युवा मुखर हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों की सूची बनाई और उनके परिजनों को समझाया। दो महीने में डेढ़ सौ युवा बंदूक छोड़ मुख्यधारा में शामिल हो गए। सुकमा जिले का भेज्जी गांव धुर नक्सल इलाका माना जाता है। नक्सली छटपटाते रह गए और फोर्स ने भेज्जी से 6 किमी आगे पालोड़ी में कैंप बना लिया। बीजापुर के पामेड़ में पुल बनाने के लिए चिंतावागु नदी के तट पर कैंप बनाया जा रहा है। नदी उस पार से नक्सली राकेट लांचर दाग रहे हैं, पर जवान डटे हुए हैं। अबूझमाड़ को बुझने के लिए दंतेवाड़ा व बीजापुर की ओर से इंद्रावती पर तीन पुल बनाए जा रहे हैं।

नारायणपुर से सोनपुर तक जंग लड़कर सड़क बनाई गई है। अब अबूझमाड़ के भीतर महाराष्ट्र के मरोड़ा तक सड़क की योजना है। जुडूम के वक्त बंद हुए स्कूलों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। जिन नक्सलियों ने तब स्कूल तोड़े थे, मुख्यधारा में आने के बाद वही अब स्कूलों को बना रहे हैं। सुकमा व बीजापुर के पहुंच विहीन गांवों में गांव के ही पढ़े-लिखे लड़के शिक्षादूत बनकर बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। राशन दुकानें गांव तक पहुंचीं तो वनवासियों को नमक के लिए मीलों पैदल चलने की दिक्कत से निजात मिली। पुल बने तो गांव तक एंबुलेंस पहुंचने लगी। तरक्की दिखने लगी तो युवाओं का नक्सलवाद से मोहभंग होने लगा।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

जंगल तक पहुंचा विकास

चार दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर में अब विकास की रोशनी दिखने लगी है। सड़कें विकास लेकर उन जंगलों तक पहुंच रही हैं, जो नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलवाद सिमटकर हाशिए पर चला गया है। यहां नक्सलवाद से लड़ाई छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद शुरू हुई। जगदलपुर से बीजापुर के भोपालपटनम तक बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) ने सड़क निर्माण शुरू किया, तब सीआरपीएफ की जरूरत पड़ी। साल 2005 में बीजापुर से नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडूम की शुरुआत हुई। नक्सली बौखला गए। उस दौर में आम नागरिकों और सुरक्षाबलों की बहुत हत्या हुई। जुडूम के विरोध में दो साल 2006 से 2007 तक नक्सलियों ने बस्तर की बिजली लाइन ठप कर भीषण गर्मी में जनजीवन बेहाल किया। यह उस दौर की बानगी भर है। मगर, अब हालात काफी अलग हैं। जो नक्सली राज्य गठन से पहले करीब 800 गांवों में जनताना सरकार चलाते थे, वे अब 200 गांवों में ही प्रभावी रह गए हैं। इसी तरह सक्रिय हार्डकोर नक्सलियों की संख्या भी तीन हजार से कम होकर हजार पर पहुंच गई है। सुरक्षा बल आज 120 गांवों में कैंप लगाए हैं।

घिरीं वसुंधरा

राजनीति में यादें कभी धुंधली नहीं पड़तीं। लेकिन सियासी दांवपेच की तेज रफ्तार कब, किसे फिसड्डी और किसे माहिर साबित कर दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कब, कौन महारथी गुमनामी की खोह में धकेल दिया जाए, तो अचरज नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो भाजपा की धारदार नेता वसुंधरा राजे इन अप्रिय स्थितियों के कुहासे में घिरी हुई हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीति में वसुंधरा की स्थिति क्या है? लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए, तो ढेरों अप्रिय तथ्य लुका-छिपी करते नजर आएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई अल्का सिंह गुर्जर को तो बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों में शामिल कर लिया गया, लेकिन राजस्थान और राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री से लेकर दो बार मुख्यमंत्री की पारी खेल चुकी राजे को तवज्जो तक नहीं की गई? इससे पहले भी वसुंधरा को हरियाणा समेत अन्य राज्यों के चुनावी अभियान से दूर रखा गया। साख, लोकप्रियता और रसूख की बात करें, तो वसुंधरा राजे आज भी नूर-ए-नजर हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें सियासी महिफल से दरकिनार किया जाता है, तो साफ इशारा है कि राजे विरोधी लहर एक दुष्चक्र गढ़ने में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ भट्ट कहते हैं कि राजनीति में कद और पद का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। पद जाते ही बड़े-बड़े नेता अज्ञातवास में चले जाते हैं।

वसुंधरा राजे को जिस तरह कॉर्पोरेशन चुनाव समिति और पंचायत चुनाव संचालन समिति से अलग रखा गया। उसके पीछे भी कमोबेश यही विरोधाभासी राजनीति हो सकती है। विश्लेषक कहते हैं कि वसुंधरा राजे की गिनती ऐसे नेताओं में नहीं की जा सकती। उन्हें चुका हुआ मान लेना भाजपा की सबसे बड़ी गलती होगी। राजे सियासत की इस नब्ज को बखूबी टटोलना जानती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम माथुर भी यही बात दोहराते हैं। लेकिन शब्दों की बाजीगरी के साथ की पार्टी में कोई साइडलाइन नहीं होती। सिर्फ भूमिका बदल जाती है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे की चुप्पी ने प्रादेशिक राजनीति में एक खालीपन भर दिया है। उनका जैसा राजनीतिक कौशल, दमखम और प्रतिद्वंद्वियों पर प्रहार करने की क्षमता किसी दूसरे नेता में नहीं है। वैसे भाजपा में इस विरोधाभासी राजनीति ने कितना विध्वंस रचा? इस बारे में भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कह देती है कि निकाय चुनावों में उनकी अनदेखी का ही नतीजा रहा कि पार्टी की जबरदस्त दुर्गति हुई।

राजमहल कांड नहीं भूलीं दीयाकुमारी

राजमहल पैलेस होटल को लेकर वसुंधरा राजे और जयपुर राज परिवार में ठनी जंग का रहस्य क्या था? आखिर नौबत क्यों राजे की गद्दी छिन जाने की दहलीज तक पहुंच गई? महलों से शुरू हुई यह कहानी आखिर कहां जाकर पहुंची? उस समय यह अबूझ पहेली भले ही थी, लेकिन देखते-देखते राख में दबी वह चिंगारी अब इस कदर भड़क चुकी है कि वसुंधरा को सत्ता की सियासत से महरूम करने की नौबत आ चुकी है। जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित राजमहल पैलेस राजपरिवार की संपत्ति माना जाता रहा है। राजमहल पैलेस होटल को दिवंगत महाराजा मानसिंह ने अपने पुत्र भवानी सिंह को तोहफे में दिया था। सन् 2004 में जयपुर राजपरिवार में लग्जरी होटल ग्रुप सुजान को लीज पर दे दिया, लेकिन सुजान ग्रुप होटल के जैसल सिंह इसे अपनी मिल्कियत समझने का भ्रम पाल बैठे। जैसल सिंह वसुंधरा राजे के करीबी लोगों में गिने जाते हैं। बात का बतंगड़ तब बना, जब राजकुमारी दीयाकुमारी ने राजमहल होटल के नियंत्रण से जैसल सिंह को यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि हमें उन पर भरोसा नहीं रहा। अब होटल की बंदोबस्त हम संभालेंगे। भरोसा खत्म, सौदा खत्म। कहते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे अपना अपमान समझा।

बावजूद इसके भाजपा की प्रादेशिक राजनीति में वसुंधरा राजे की हैसियत को कम आंकने का क्या मतलब है? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का बढ़ता हौसला और अप्रत्यक्ष रहकर वसुंधरा राजे पर ताबड़तोड़ हमले सारी कहानी कह जाते हैं। गहलोत सरकार में चले अंतर्कलह पर राजे की चुप्पी को लेकर तो पूनिया ने मौका ताड़ते हुए अभियान छेड़ दिया कि राजे ने गहलोत से हाथ मिला लिया है। उनकी निष्क्रियता का सीधा फायदा डावांडोल होती गहलोत सरकार को मिल रहा है। निश्चित रूप से यह भाजपा और सहयोगी दल आरएलपी की साझा मुहिम रही होगी। अन्यथा आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल यह कहने का दुस्साहस नहीं करते कि 20 साल से मिला-जुला खेल चल रहा है। वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ की वजह से राजस्थान बर्बादी के कगार पर चला गया है। पूनिया की इस सारी कवायद के पीछे गहलोत सरकार गिराकर कुर्सी हथियाने की बेताबी थी। सरकार गिराओ अभियान में जिस तरह पूनिया दिन-रात एक किए हुए थे, उसमें सबसे बड़ी बाधा तो वसुंधरा राजे थीं। राजनीतिक ताकत के रूप में पूनिया का आंकलन करें, तो बेशक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक उनकी अच्छी पहुंच है। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में भी उनका पूरा दबदबा है और जातिगत समीकरण भी पूरी तरह उनके पक्ष में हैं, लेकिन विधानसभा में गिनती के विधायक ही उनके साथ खड़े हो सकते हैं। राजनीति में बढ़िया क्षेत्ररक्षण सबसे बड़ा कौशल होता है। इसके लिए एथलीट सरीखी दक्षता अनिवार्य होती है। इस नजरिए से पहली अहमियत पार्टी में बड़ा गुट होने की होती है। यह ताकत तो सिर्फ वसुंधरा राजे में है। वसुंधरा के पक्ष में विधायकों में गजब की एकजुटता है; जो वसुंधरा के इशारे पर कभी भी आक्रामक हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त जीतने की जी तोड़ भावना पैदा करने वाली इच्छा को समझें, तो वसुंधरा अकेली राजनेता हैं जो निर्दलियों को भी अपने साथ लाने का चमत्कार कर सकती हैं। कहने का लब्बोलुआब यह है कि वसुंधरा जैसा प्रभाव भाजपा के किसी भी नेता में नहीं है। गहलोत के साथ राजनीतिक गठबंधन के फरेबी आरोपों से आहत राजे ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आदि से मिलकर अपनी राजनीतिक लॉबी को जगाने की कोशिश में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन पूनिया ने खट्टे तजुर्बों का इतना डाटा जुटा रखा था कि राजे की उम्मीदों की जड़ों को जमने ही नहीं दिया। नतीजतन राजे की आवाज ही अनसुनी कर दी गई। जाहिर है कि पूनिया को नेतृत्व की पूरी छूट थी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

संकट में चीनी उद्योग

चीनी उत्पादन में अग्रणी महाराष्ट्र का चीनी उद्योग पिछले छह महीने से केंद्र सरकार के सामने निर्यात की नीति को स्पष्ट करने पर जोर दे रहा है। लेकिन, केंद्र उसकी इस मांग को लगातार अनसुना कर रहा है। दूसरी तरफ, मौसम शुरू होने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा निर्यात सब्सिडी रोके रखने से यह उद्योग भयावह वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हालांकि, कुछ जानकार इस मौजूदा वित्तीय संकट को राजनीतिक नजरिए से देख और समझ रहे हैं। इस सेक्टर के जानकार अर्नाल्ड लुइस मानते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा निर्यात सब्सिडी बंद रखे जाने से भारतीय चीनी उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे महाराष्ट्र में चीनी कारखानों की स्थिति साफ करते हुए कहते हैं कि राज्य में कई कारखाने बंद हो चुके हैं और कई कारखाने बैंकों से लिए गए कर्ज में डूबे हैं। इस कारण नकद की कमी आ गई है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसका असर खेतीबाड़ी पर भी पड़ रहा है और राज्य के गन्ना किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा है।

वहीं, राज्य में चीनी कारखाना प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को लगता है कि अबकी बार राज्य में प्रति टन चीनी निर्यात पर दी जाने वाली औसतन ग्यारह हजार रुपए की अनुदान राशि नहीं मिलने से वे फंस गए हैं। जबकि, कुछ प्रबंधकों की यह शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीनी उद्योग को मदद देने के मामले में अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हालांकि, केंद्र पर भाजपा शासित राज्यों के चीनी उद्योग को मामूली राहत देने और अन्य राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केंद्र ने उप्र, बिहार, मप्र और गुजरात के गन्ना किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम दिलाने और शक्कर भंडारण जैसे मुद्दे पर थोड़ी मदद की है। वहीं, इस मामले में केंद्र ने महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

कहा यह भी जा रहा है कि दुनियाभर के अलग-अलग देशों के चीनी बाजारों में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए भारत को भी अपनी चीनी निर्यात नीति स्पष्ट करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान शक्कर की कमी से जूझ रहा है, जहां खुले बाजार में 120 रुपए किलो की दर से शक्कर बिक रही है, ऐसे में वहां की सरकार 70 रुपए किलो की नियंत्रित दर पर शक्कर बेच रही है। फिजी में गन्ने की फसल में गिरावट राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। थाईलैंड में शक्कर के दाम कम करने के बाद म्यांमार ने अपने यहां भी शक्कर के दाम घटा दिए हैं। इथोपिया में चीनी मिलों का निजीकरण शुरू हो गया है। चीन और आस्ट्रेलिया ने शक्कर खरीदनी बंद कर दी है। जाहिर है कि इस तरह के रुझानों का दुनियाभर के चीनी उद्योग पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इन परिस्थियों को देखते हुए केंद्र सरकार को वैश्विक बाजार के अनुकूल चीनी निर्यात के लिए एक ठोस नीति पर विचार करना चाहिए। लेकिन, उसके ऐसा न करने से घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बता दें कि दुनियाभर में सल्फर-मुक्त शक्कर की मांग सबसे अधिक होती है। भारत और खासकर महाराष्ट्र में इसी किस्म की सफेद, चमकदार तथा बड़े दाने वाली शक्कर का उत्पादन किया जाता है। वहीं, महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सबसे अधिक हैं। इसके लिए यह उद्योग अन्य राज्यों से भी बड़ी मात्रा में शक्कर खरीदता है। इसी तरह, यहां से ब्रिटेन की कंपनी को भी सालाना ढाई लाख टन शक्कर की आपूर्ति की जाती है। लेकिन, फिलहाल अन्न सुरक्षा कानून के नियमों के चलते इस तरह की आपूर्ति करने में अड़चन आ रही है।

यहां यह बात भी मायने रखती है कि शक्कर में यदि नमी और अन्य घटकों की मात्रा अधिक रहे तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में 70 प्रतिशत से अधिक शक्कर का शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन, दिक्कत यह है कि उसके लिए राज्य में स्थानीय स्तर पर जरूरत के मुताबिक मार्केटिंग और वितरण के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। इन सबके बावजूद कुछ जानकार मानते हैं कि केंद्र यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत चीनी की अच्छी कीमत देना शुरू करें तो चीनी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 36 रुपए प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चीनी खरीदने की सिफारिश की है। बता दें कि आज देश में चीनी का उत्पादन उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीनी बेचने के लिए अच्छे नेटवर्किंग की दरकार है। लेकिन, महाराष्ट्र में चीनी बिक्री का नेटवर्क कुछ अन्य राज्यों के मुकाबले कमजोर है। इसलिए, यहां अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती दर पर चीनी बेचनी पड़ रही है।

● **बिन्दु माथुर**

चीनी कारखानों पर 30 हजार करोड़ का कर्ज

यदि केंद्र द्वारा चीनी निर्यात में दी जाने वाली सब्सिडी बंद होने के नतीजों पर फिर से बात करें तो कह सकते हैं कि राज्य का यह उद्योग पूंजी निवेश के लिए पूरी तरह से सहकारी बैंकों पर निर्भर हो गया है। बता दें कि राज्य के चीनी कारखानों पर 30 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। मौजूदा दौर में उसका ब्याज भरना भी आसान नहीं रह गया है। इस ब्याज के बोझ से सिर्फ कारखाना प्रबंधक ही नहीं किसान और ग्राहक भी त्रस्त हैं। लेकिन, राजनीति के शिकार कई सहकारी चीनी कारखाने बिकने की कगार तक पहुंचा दिए गए हैं। इससे पहले भी सहकारी चीनी कारखानों को तबाह करके राज्य के कई नेता खुद चार-पांच कारखानों के मालिक बन गए हैं। इसके बावजूद, आज भी महाराष्ट्र में 100 से अधिक सहकारी मिले हैं। स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की 200 से ज्यादा तहसीलों की दलगत राजनीति इन्हीं चीनी कारखानों के इर्द-गिर्द घूमती है। दूसरी तरफ, पिछले तीन वर्षों में राज्य के 25 कारखाने सहकारी से प्राइवेट में तब्दील कर दिए गए हैं।

लव जिहाद पर नकेल

उप्र में लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं कानून-व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही थीं। ऐसी घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बना दिया है। अब राज्य में छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए कानून लागू हो गया है। उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई महिला अथवा पुरुष एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के बाद अपने ठीक पूर्व धर्म में फिर से वापसी करता है तो उसे इस अध्यादेश के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। इससे पहले मप्र सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। हरियाणा, कर्नाटक और कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। माना जा रहा है कि उप्र सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़े विधेयक लाकर इसे पारित कराएगी।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के बाद अपनी स्वेच्छा से अपने ठीक पहले के धर्म में वापसी कर सकता है। कानून के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो मिथ्या, निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक, प्रभाव, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट ने 24 नवंबर को अध्यादेश को मंजूरी दी थी और उसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होगी।

उप्र में अब छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए कानून लागू हो गया है। इसके तहत धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन यानी दो महीने पहले जिलाधिकारी या संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति खुद से, अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी दबाव, बल या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है। घोषणा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी। जिलाधिकारी धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन व कारण की पुलिस के जरिए जांच कराने के बाद अनुमति प्रदान करेंगे।

अध्यादेश के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध होगा। विवाह के जरिए एक से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी कठोर अपराध की श्रेणी में होगा। यह अपराध गैरजमानती होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध भी सजा का प्रावधान होगा। जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में साक्ष्य देने का भार भी आरोपित पर होगा। यानी कपटपूर्वक, जबरदस्ती या विवाह के लिए किसी का धर्म परिवर्तन किए जाने के मामलों में आरोपित को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन एकमात्र प्रयोजन विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। पीड़िता या पीड़ित के अलावा उसके माता-पिता, भाई-बहन या रक्त संबंधी भी मामले में रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे।

अध्यादेश में छल-कपट से, प्रलोभन देकर, बल पूर्वक या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के सामान्य मामले में कम से कम एक वर्ष तथा अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कम से कम 15 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में कम से कम दो वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास तथा कम से कम 25 हजार रुपए जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कम से कम तीन वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना होगा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बरेली में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला केस

उप्र में बरेली के देवरनिया इलाके में एक छात्र-छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। आरोपी ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देवरनिया के गांव शरीफनगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद का बेटा उवैस अहमद ने पढ़ाई के समय से उनकी लड़की से जान पहचान बना ली थी। पीड़ित ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़ित के मुताबिक उनके व परिवार द्वारा कई बार आरोपी से मना किया जा चुका है। फिर भी वह मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बना रहा है। आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज की। लव जिहाद पर कानून बनने के बाद देवरनिया थाने में उप्र विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।

महागठबंधन की महाभूल

बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने 37-37 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किए। तेजस्वी रैलियों में भारी भीड़ खींचने में सफल दिख रहे थे, विशेष रूप से युवाओं का रूझान उनके पक्ष में था, लेकिन बहुमत से 12 सीट पीछे रह गए। एग्जिट पोल गलत तो ओपिनियन पोल सही साबित हुए। वैसे परिणाम देखकर सदमे में आया विपक्ष ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाने लगा। इधर, नीतीश को लेकर एंटी इकंम्बेंसी के बीच सत्ता बरकरार रहने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है, वहीं महागठबंधन की पराजय में तेजस्वी के प्रबंधन की कमजोरी तलाश की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब नीतीश और एनडीए के 15 साल के कार्यकाल से उदासीन हो रही जनता परिवर्तन की राह देख रही थी, तो तेजस्वी ये अवसर कैसे चूक गए?

तेजस्वी ने आसानी से आकर्षित करने वाले कमाई, दवाई, पढ़ाई, महंगाई और सिंचाई का मुद्दा उठाया। साथ ही युवाओं से रोजगार का वादा कर बड़ा दांव खेला। हालांकि ये मुद्दे नए नहीं हैं, बल्कि दशकों से चुनावों में सुने जाते रहे हैं। वैसे कोरोनाकाल में आर्थिक संकट से बेरोजगारी जैसे मुद्दे एक बार फिर से प्रभावी हो रहे हैं। तेजस्वी ने मुद्दों के साथ चुनाव को लेकर धारणा की तरफ शायद कम ध्यान दिया। धारणा अब नई वास्तविकता है। टीम मोदी की खासियत है कि वह एक विशेष धारणा बनाने में कामयाब रहती है। कोरोना महामारी के **बीच गरीबों** की मदद, नकदी और मुफ्त राशन को लेकर लोगों के बीच मोदी को लेकर खास धारणा बनाई। उन्होंने आरजेडी की सत्ता वापसी को जंगल राज की वापसी की धारणा को बनाने में भी सफलता हासिल की। ऐसे में मौजूदा शासन के असंतोष के बावजूद महिलाओं के एक वर्ग, मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध मतदाताओं के एक वर्ग ने महागठबंधन को लेकर विचार बाद में बदल लिया।

टिकट बंटवारे में तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें दीं, जो 2015 से 29 अधिक है। कांग्रेस ने महागठबंधन और एनडीए दोनों में देखें तो 27 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा, जिसने केवल 19 सीटें हासिल कीं। पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास में उच्च जाति के उम्मीदवारों को कई टिकट दिए, लेकिन बुरी तरह विफल रही। महागठबंधन में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा ही, वहीं आरजेडी ने भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। इसने 144 सीटों में से 75 पर जीत हासिल की, जिसमें 52 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट थी। भाजपा का स्ट्राइक रेट 61 प्रतिशत था, जो एनडीए का इन-फॉर्म खिलाड़ी था। आंतरिक स्रोतों की मानें तो आरजेडी से 85 सीटों के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत स्ट्राइक रेट की उम्मीद की जा रही थी। आरजेडी की लंबे समय से पहचान मुस्लिम-यादव पार्टी के रूप में है। हालांकि ये दोनों समूह पिछले 15 वर्षों से लालू की पार्टी को ध्रुव की स्थिति में लाने में सक्षम नहीं हैं। दोनों राज्य की आबादी का 31 प्रतिशत है। यदि आरजेडी चुनावी मुकाबले को दो ध्रुवीय बनाना चाहता है तो उसे 24 से 25 प्रतिशत वोट शेयर की और जरूरत पड़ेगी। 2015 में आरजेडी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में जीत हासिल की, क्योंकि दोनों दलों ने मिलकर एम-वाई, कुर्मी-कोरी, महापिछड़ा और दलितों, महादलितों के सामाजिक गठबंधन को सफलतापूर्वक संतुलित कर लिया था। तेजस्वी ने हम और वीआईपी को आसानी से बाहर कर दिया, जिसने एनडीए के खेमे से 8 सीटें जीतीं, जबकि उन्हें 18 सीटों पर मौका दिया गया था। क्या तेजस्वी इन दो दलों को कांग्रेस कोटे से 18 सीटें नहीं दे सकते थे? क्या इन पार्टियों को लेकर भरोसे का संकट था? ये दोनों महादलित और निषाद वोटों के एक हिस्से को महागठबंधन में ला सकते थे। उन्होंने इन चुनावों में 3 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया है, जो कांटेदार मुकाबले में अहमियत रखते हैं।

आंकड़ों में देखें तो दोनों गठबंधनों की स्थिति स्पष्ट होती है। पहले चरण में महागठबंधन 25 सीटों पर आगे दिख रही थी। इन चुनाव क्षेत्रों में दलितों की अधिक आबादी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के उम्मीदवारों की उपस्थिति के चलते एनडीए का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। दूसरे चरण में एनडीए के गढ़ में फंसने के बाद भी महागठबंधन 16 सीटों से आगे था। 78 सीटों पर हुए तीसरे चरण के मतदान को देखें तो इनमें अल्पसंख्यक प्रभाव वाले सीमांचल क्षेत्र (24 सीटें) और 22 अन्य सीटें शामिल थीं, जहां उनकी आबादी 17 और 21 प्रतिशत है। इसे आरजेडी का गढ़ माना जाता था। हालांकि, एनडीए ने इस क्षेत्र में 52 सीटें जीतीं और आरजेडी 21 पर सिमट गई। ओवैसी की एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीतीं। इससे समझा जा सकता है कि आरजेडी ने एआईएमआईएम की चेतावनी को हल्के में लिया। यहां एआईएमआईएम वोट कटवा नहीं बन सकी। इसने केवल एक सीट जीती, जहां इसने जीत के अंतर से अधिक मत हासिल किए, जिससे एनडीए को जीत मिली। कहा जा सकता है कि चूंकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतीं, इसलिए इसे आरजेडी को गठबंधन में शामिल करने के प्रयास करने चाहिए थे।

● **विनोद बक्सरी**

विपक्षी मतों के विभाजन को रोकने में विफलता

इस बार जेडीयू उम्मीदवारों को हराने के लिए एलजेपी पूरी तरह से बाहर थी। इसका एकमात्र उद्देश्य नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाना था। आरजेडी के पास एलजेपी के साथ औपचारिक गठबंधन नहीं होने पर मौन सहमति हो सकती थी। इससे महागठबंधन को महत्वपूर्ण दलित वोट हासिल करने में मदद मिलती। एलजेपी ने अनजाने में 32 सीटों पर महागठबंधन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। मुख्य विपक्षी दल और नीतीश कुमार के प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आए तेजस्वी की जिम्मेदारी थी कि वे महागठबंधन को लेकर औपचारिक या मौन स्वीकृति के आधार पर ऐसी जमावट करते, जिससे एनडीए के विरोधी वोटों का विभाजन न हो। जबकि अन्य ने 26 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया और विपक्षी वोट को विभाजित कर दिया। कुशवाहा की अगुवाई वाली जीएसडीएफ ने जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल करते हुए 23 सीटों पर महागठबंधन की संभावनाओं को नाकाम कर दिया।

लोकल के लिए वोकल का सपना
साकार होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

भारतीय संस्कृति का मूल भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुम्बकम और यही भाव सहकारिता का भी है। सहकारिता भारत की मौलिक सोच है, यह कहीं से आयातित विचार नहीं है। यही कारण है कि भारत के जन-मानस में, खासतौर पर किसानों, पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों आदि को सहकारिता मॉडल सर्वथा योग्य लगता है। व्यक्ति पीछे रहे और विचार आगे बढ़ें, स्वार्थ पीछे रहे और साथी आगे बढ़े, यही सहकारिता की असली ताकत है।

मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता आंदोलन के प्रति अपनी अनुकूल नीतियों और पिछले 15 वर्षों में लाभप्रद कृषि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन राज्य बनाया, जिसके कारण ही विगत 5 वर्षों से मध्यप्रदेश को भारत सरकार से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त होते रहे। प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर राज्य ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में लोकल के लिए वोकल को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है।

कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जैसे उत्पादन लागत के अनुपात में आय और लाभ को बढ़ाना, आदानों की लागत में कमी करना, जल, मिट्टी व जैव-विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ती फार्म मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, दक्ष, सस्ती और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियां विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान बनाने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी को विकसित करना, मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करना।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केंद्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर केपिटल फण्ड स्थापित किया जाएगा। इस फंड के माध्यम से कृषि तकनीकों के नए अनुसंधान को पेटेंट कराया जाएगा और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमांत कृषकों को मजबूत बनाने के लिए एपेक्स बैंक के माध्यम से एक वैंचर केपिटल फंड स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह वैंचर केपिटल फंड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें एपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायक नवाचारकर्ताओं, फेब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट-अप कंपनियों के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण, प्रौद्योगिकी और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचारों और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यह फंड नवाचारों के पेटेंट में भी सहयोग करेगा।

प्रदेश में 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं उनसे संबद्ध 4,523 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं। इन समितियों से लगभग 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन-सामान्य को विभिन्न सेवाओं का प्रदाय करने हेतु पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वसनीय तथा प्रभावी सिंगल प्वाइंट ऑफ सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके रिकार्ड डिजिटाइजेशन के साथ सहकारी बैंकों की कोर-बैंकिंग के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सहकारी साख संस्थाओं के तीनों स्तरों में डाटा लिंकिंग के जरिए कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके और दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से किसानों/समिति के सदस्यों को अन्य बैंकिंग संस्थाओं के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सुविधा के साथ बाधा-रहित इलेक्ट्रॉनिक पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। इससे ऋण वितरण सहित बैंकिंग कार्य में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। परिणामस्वरूप समितियों के प्रति किसानों में विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही समितियों को बैंकिंग की प्रभावी अंतिम कड़ी के रूप में विकसित करने में सफलता मिलेगी। शासकीय योजनाओं अंतर्गत ऋण व खाद वितरण, उपार्जन कार्य, खाद्यान्नों का विक्रय आदि के प्रबंधन हेतु विश्वसनीय अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

- फीचर

अमेरिका की साख गिरी

वक्त एक तरह से आज खुद अमेरिका को आईना दिखा रहा है। असल में अमेरिका विकासशील देशों की चुनाव प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर उनकी आलोचना करता रहा है। कई देशों में तो उसने चुनी हुई सरकारों को ही संदिग्ध करार दिया कि उन्होंने जबरन सत्ता हथियाई और वास्तविक विजेता को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आज वही अमेरिका खुद को अजीबोगरीब स्थिति में पा रहा है, जहां निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ चुनाव में धांधली हुई। वह अभी भी चुनाव नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अमेरिका और शेष विश्व जरूर इन नतीजों को स्वीकृति दे चुका है। वैसे ट्रंप अपनी हार को जीत में बदलने के लिए हरसंभव कानूनी तिकड़म आजमा रहे हैं। उनके वकील विभिन्न राज्यों में मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। शुरुआती दौर में इन राज्यों में ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंत में वोट जो बाइडन की झोली में चले गए हैं। साक्ष्यों के अभाव में अदालतें ट्रंप की शिकायतें खारिज कर रही हैं। यानी कानूनी मोर्चे पर भी ट्रंप को कामयाबी नहीं मिलने वाली। इतने पर भी ट्रंप को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा और वह पहले से ही विभाजित देश को और विभाजित करने पर तुले हैं।

अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण एवं तकनीकी परिवर्तन से खासे प्रभावित हुए हैं। जिन सामाजिक समूहों को इन परिवर्तनों से लाभ मिला है और जो उदार मूल्यों में विश्वास रखते हैं, वे व्यापक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडन के साथ हैं। वहीं ट्रंप को अमूमन उन परंपरावादी समूहों का समर्थन हासिल है, जो तकनीकी परिवर्तन की बयार में कहीं पीछे छूट गए। इन वर्गों के बीच में भारी कड़वाहट है। चुनाव के बाद होना यही चाहिए था कि अमेरिकी नेता देश को एकजुट करने और निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन का समर्थन करते, परंतु ट्रंप ने ऐसा नहीं होने दिया। ट्रंप का यह रवैया अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय साख को क्षति पहुंचा रहा है। यही कारण है कि ईरान जैसे अमेरिका के विरोधी देशों ने चुनावों का मजाक उड़ाया। कई अन्य देश खुलेआम ऐसी प्रतिक्रिया देने से परहेज करेंगे, क्योंकि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को कुपित करना नहीं चाहेंगे। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यदि अमेरिका अब दूसरे देशों में चुनावों की आलोचना करेगा तो उसे इन चुनावों में ट्रंप की शिकायतों का स्मरण कराया जाएगा। ट्रंप के ये कदम बाइडन को अपनी टीम बनाने और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में देरी की वजह भी बने हैं। इससे दुनियाभर में बाइडन की विजय पर भ्रम की स्थिति बनी, जिससे भारत जैसे तमाम देश प्रभावित हुए। कई नेताओं ने बाइडन को जीत पर शुभकामना संदेश भेजे। यह किसी से छिपा नहीं रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रंप से बहुत करीबी रिश्ते रहे। मोदी ने भी बाइडन को बधाई दी। यह बधाई वह थोड़ा और पहले देते तो कहीं बेहतर होता, क्योंकि दो देशों के बीच रिश्ते उनके हितों पर निर्भर करते हैं। नेताओं के आपसी रिश्ते कभी राष्ट्रीय हितों के बराबर महत्वपूर्ण नहीं होते। भारत-चीन रिश्तों के मामले पर भी यह कसौटी सही साबित होती है।

ट्रंप ने बाइडन को उनकी टीम बनाने में मदद नहीं की

होना तो यही चाहिए था कि ट्रंप प्रशासन बाइडन की जीत के संकेत के साथ ही उन्हें सत्ता हस्तांतरण में मदद करता। यही परंपरा सुनिश्चित करती कि 20 जनवरी को पद्भार संभालने के साथ बाइडन उसी क्षण से कार्य शुरू करते। चूंकि ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की तो उनके प्रशासन ने चुनाव के तीन हफ्ते बाद भी बाइडन को उनकी टीम बनाने में मदद नहीं की। हालांकि बाइडन ने व्हाइट हाउस से लेकर अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पद संभालने वालों के नाम घोषित करने के साथ शुरुआती नीतियों की झलक भी पेश की है। यह बहुत दूरदर्शी कदम है, क्योंकि अमेरिकी सरकार में असमंजस की स्थिति अमेरिका के साथ ही दुनिया के लिए भी अच्छी नहीं है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति को टीम बनाने और प्रारंभिक नीतियों को आकार देने के लिए ढाई महीनों से अधिक का वक्त मिलता है। यह अवधि यही मांग करती है कि मौजूदा और संभावित प्रशासन परस्पर सहयोग करें ताकि अमेरिकी नीतियों में स्थायित्व एवं निरंतरता कायम रहे, जिससे दुनिया में भी कम से कम हलचल हो। इस प्रक्रिया में ट्रंप प्रशासन के रवैये की वजह से देरी हुई, क्योंकि उसने यही दर्शाया कि सत्ता में तो वही रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो का चुनाव बाद सात देशों का दौरा यही जाहिर करता है। वह ट्रंप की विदेश नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में वह बाइडन प्रशासन के लिए मुश्किल विरासत छोड़ेंगे।

बहरहाल ट्रंप के रुख-रवैए ने एक बार फिर साबित किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पुरानी हो गई है, जिसमें परिवर्तन आवश्यक हो गया है। कई अमेरिकी राजनीति विज्ञानियों ने भी इसकी जरूरत जताई है। आपको जानकार हैरानी हो सकती है कि जनता के अधिक मत पाकर भी वहां कोई प्रत्याशी चुनाव हार सकता है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन के साथ यही हुआ। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से करता है। ये इलेक्टोरल प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक अमेरिकी राज्य अपने चुनावी नियमों के अनुरूप अपने कोटे के इलेक्टर्स चुनता है। ये इलेक्टर्स मुख्यत: अपने राज्य में अधिकांश मत पाने वाले प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान करते हैं। इस प्रकार कोई प्रत्याशी देश में अधिक मत प्राप्त करके भी चुनाव में पराजित हो जाता है। हालांकि इस चुनाव में बाइडन को देशभर में ट्रंप से 60 लाख से अधिक मत मिले हैं। अब सभी की निगाहें 14 दिसंबर पर टिकी हैं, जब इलेक्टर्स अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। अब यह मात्र औपचारिकता ही है, क्योंकि ट्रंप के 232 के मुकाबले बाइडन 306 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 270 है। अनुमान है कि 14 दिसंबर तक ट्रंप के सभी कानूनी दावे भी खारिज हो जाएंगे। हालांकि वह शायद अपना राग अलापना जारी रखें। इससे अमेरिका को और शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिसकी भरपाई के लिए बाइडन को ही प्रयास करने होंगे।

चुनाव से ठीक पहले पोंपियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्पर भारत में अपने समकक्षों के साथ टू-प्लस-टू वार्ता के लिए आए तो भारत को भी कुछ असहजता से दो-चार होना पड़ा। उस दौरे में सामरिक एवं रक्षा सहयोग से जुड़े अहम समझौते हुए। चूंकि अमेरिकी राजनीतिक बिरादरी में भारत-अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंधों के लिए व्यापक समर्थन है तो आशा है कि बाइडन भी इन समझौतों पर मुहर लगाएंगे। हालांकि मानवाधिकार जैसे कई मसलों पर बाइडन के तेवर ट्रंप से अलग होंगे, जहां भारतीय कूटनीति को कड़ी परीक्षा का सामना करना होगा।

● **कुमार विनोद**

अमानवीयता की इंतिहा

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हरियाणा में एक महिला के साथ हुए अत्याचार की इंतिहा ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार बढ़ोतरी देखी गयी है। हाल ही में शादीशुदा 35 साल की महिला को घर में ही पति ने एक साल से अधिक समय तक शौचालय में कैद रखा। उसे न सिर्फ मारा-पीटा जाता था, बल्कि एक तरह से पागल बताकर कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता था। इससे महिला हड्डियों का ढाँचा बन गयी। बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाली महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता की मदद से उसे निकाला गया। हरियाणा के पानीपत ज़िले के रिशपुर गाँव में फिलहाल इस महिला को पति को चंगुल से बचा लिया गया है और वह अपने चचेरे भाई के पास है। पति ने दावा किया कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन वह मानसिक रूप से स्वस्थ लग रही है और उसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसे लम्बे समय तक भूखा रखा गया। जैसे ही उसे बाहर निकाला, तो उसने सबसे पहले रोटी माँगी। जब नहलाकर उसे दूसरे कपड़े पहनाये गये, तो उसने चूड़ियाँ और लिपस्टिक की भी माँग की। हालत इतनी खराब हो गयी है कि उसकी टाँगे तक सीधी नहीं हो पा रही हैं।

महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि हमने पीड़ित महिला से बात की है, वह मानसिक रूप से ठीक है। 15 अक्टूबर को रजनी टीम के साथ गाँव रिशपुर पहुँची, तो पुलिस भी साथ में थी। नरेश घर के बाहर ताश खेल रहा था। पत्नी रामरती के बारे में पूछने पर वह चुप रहा। जब सख्ती से पूछताछ की, तो वह टीम को घर की पहली मंजिल पर ले गया, जहाँ शौचालय में उसने पत्नी को बंद रखा था। महिला के कपड़े बेहद गंदे थे, शरीर हड्डियों का ढाँचा बन गया था। जैसे ही बाहर निकाला, तो उसके चेहरे में खुशी का भाव दिखा। बताया गया कि रामरती के पिता और भाई की करीब 10 साल पहले मौत हो गयी थी, तबसे उसकी मानसिक हालत खराब बतायी गयी। हालाँकि रामरती सभी को पहचान रही है। उसके तीन बच्चे भी हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी अमानवीयता के बारे में इंसान सोच कैसे सकता है? बाद में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा-498 (ए) और 342 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति नरेश को गिरफ्तार कर लिया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो साल में हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 45 फीसदी की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके पीछे तर्क दिया है कि अब राज्य में 34 महिला थाने खोले गये हैं, जिसके बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें दर्ज होने लगी हैं। इससे यहाँ पर अपराध के मामलों में तेज़ी देखी गयी। पहले महिलाएँ संकोच या समाज में बदनामी की वजह से केस दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थीं; लेकिन अब महिला पुलिस स्टेशनों के खुल जाने से महिलाएँ अपने खिलाफ होने वाले अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने में नहीं हिचक रही हैं। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक दावा किया कि पुलिस द्वारा शिकायतों के पंजीकरण से कितने लोग संतुष्ट हैं, इसके लिए एक सर्वेक्षण भी कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे हर अपराध की शिकायत दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि हर पीड़ित को न्याय मिले। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों की बढ़ती संख्या पर उन्होंने कहा कि परिजन, गैर-सरकारी संगठन और अन्य संगठन युवाओं में महिलाओं के सम्मान के लिए नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाएँ। इधर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध कई गुना बढ़ गये हैं और एनसीआरबी के आंकड़े इसे साबित भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के पास न तो महिला सुरक्षा के लिए कोई नीति है और न ही अपराधों को नियंत्रित करने की कोई मंशा दिखती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा में भाजपा सरकार की अक्षमता ने एक शान्तिपूर्ण राज्य को अपराध केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने महज़ एक साल में अपराधों के 1,08,212 मामले दर्ज किये, यानी औसतन देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अपराध राज्य में दर्ज किये गये। राज्य में लगातार पाँचवीं बार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ हत्या के 1,140, दुष्कर्म के 1,296, सामूहिक दुष्कर्म के 155 और अपहरण के 5,070 मामले दर्ज किये गये हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

अपराधों में कमी नहीं

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के विगत दिनों जारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर होने वाले शोषण से जुड़े सामाजिक और व्यक्तिगत अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,29,243 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 3,38,954 पर पहुंच गया। 2017 में 3,59,849 और 2018 में 3,78,277 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों में यौन शोषण, हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, एसिड हमले, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और अपहरण आदि शामिल हैं। महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में उप्र अव्वल रहा। वहां 59,445 मामले दर्ज किए गए, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, जहां 35,497 मामले दर्ज हुए। 30,394 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर रहा।

महिलाओं को मिला संबंल

मध्यप्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों में संचालित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा अनेक ऐसे उत्पाद तैयार किए जा रहे है, जो न केवल उनके क्षेत्र में अपितु प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी पहचाने जा रहे है। गांव के इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रोत्साहन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब सरकारी खरीदी में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।

देश की कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिनका प्रमुख आधार खेती रहा है। प्रारंभ से ही ग्रामीण महिलाएं खेती कार्य में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करती रहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला शक्ति को पहचान कर मध्यप्रदेश सरकार ने उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। ग्रामीण अंचलों में महिलाओं द्वारा छोटी-छोटी बचत और घर पर बनाई गई वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी पहल मध्यप्रदेश में हुई है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर महिलाओं को मदद का सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे वे अपने हुनर को बढ़ाकर अपनी आय का स्थाई जरिया कायम कर सकें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के लिए बूस्टर डोज के रूप में राज्य शासन द्वारा इस वर्ष महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

इसके ऊपर का ब्याज राज्य सरकार देगी। सम्पूर्ण प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों की 33 लाख महिलाओं को स्व-रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिये की गई इस नवीन व्यवस्था से प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी। सशक्त महिलाएं ही प्रदेश को सशक्त बना सकती है। उन्हें आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने और स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों और विपणन के लिए स्व-सहायता पोर्टल भी तैयार किया गया है।

प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बेटियों और महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील है। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में बहन-बेटी का सम्मान सर्वोपरि है, अत: बहन-बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान मिले इसके लिए राज्य सरकार हर पहलू पर कार्य कर रही हैं। प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वे हर विपदा से बचाने में सक्षम है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गए मास्क और पीपीई किट ने आम लोगों और सरकार की बहुत सहायता की। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयार की गई सामग्री काफी उपयोगी साबित हुई।

- फीचर

गरीबी रेखा के नीचे के वास्तविक हकदारों को मिली अन्न सुरक्षा की गारंटी

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की श्रीमती सुनीता राय के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला यह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता था परन्तु राशन राशन कार्ड नहीं होने के कारण इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को पर्ची वितरण की सूची में जब इनके परिवार का नाम शामिल किया गया तो इनकी खुशी का पारावार न रहा। नये पात्र परिवारों में श्रीमती राय का नाम जुड़ने से माह सितम्बर से इन्हें एक रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलोग्राम खाद्यान्न एवं एक किलोग्राम नमक राशन सामग्री के रूप में प्राप्त होने लगा है। इनके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इनके परिवार को प्रतिमाह 20 किलोग्राम खाद्यान्न तथा एक किलोग्राम दाल नि:शुल्क प्राप्त होगी जिससे इनकी रसोई की आवश्यकता प्रति माह पूरी हो सकेगी।

अंतिम इच्छा

पूजा...पूजा...पूजा!

सासु मां ने आवाज लगाई, पूजा भागकर सासु मां के पास आकर घबरा कर बोली- मम्मी जी क्या हुआ?

सासु मां रोने लगी, 'पूजा तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे!'

उनकी हालत तो नाजुक थी, डॉक्टर ने भी कहा था कि कोई भरोसा नहीं है, भगवान ने चाहा तो कुछ साल भी निकाल सकते हैं नहीं तो कुछ दिन भी नहीं।

पूजा ने सासु मां को गले लगाकर चुप कराते हुए कहा- मम्मी जी सब्र रखिए।

खुद को संभालते हुए सासु मां ने पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा 'पूजा, आज ये गए हैं कल मेरी भी बारी आएगी।

बेटा तुमने हमें बेटे के गम में संभाला और परिस्थितियों का मुकाबला भी किया तुम्हारी उम्र बहुत कम है और जिन्दगी बहुत बड़ी। छोटे सजल के भविष्य के लिए ही तुम दूसरी शादी कर लो। पूजा तुमने हमें अपने मम्मी-पापा से भी ज्यादा मान-सम्मान दिया है। तुम चाहती तो आज से दो साल पहले ही जब हमारे बेटे की मौत हुई थी तुम हमें छोड़ कर कब की चली गई होती। तुमने अपने बेटी होने का फर्ज निभाया और मेरे और ससुर जी के कहने पर भी दूसरी शादी करके हमें छोड़ कर नहीं गई। आज तुम्हें अपने ससुर जी की अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी, वो यही कह कर गए हैं कि पूजा को बोलना अपनी जिंदगी संवार ले। पूजा सासु मां को हैरानी से देखकर लिपटकर और रोने लगी।

- कामनी गुप्ता

जब भी तुम्हारा दिल करे

लौट आना बेफिकर
जब भी तुम्हारा दिल करे।
तोड़ देना नींद तनहा
ख्वाब से मिलकर गले।।
मैं हर पल राह देखती हूं।
जब कोई आवाज सुनती हूं।।
वो इक दर्पण जिसे हमने
संग साथ था निहारा।
किसी इक स्याह लम्हे ने
बेतरह तोड़ डाला।।
मैं वो कतरे बटोरती हूं।
आंच से कांच जोड़ती हूं।।
कूज कोकिल की बागों
ढाई आखर बोलती थी।
शहद जीवन का हरपल
जो हृदय में घोलती थी।
मैं वह झनकार खोजती हूं।
जब कोई परिंदा देखती हूं।।
चली आती है खुशबू
भूले भटके मेरे आंगन में।
भिगो जाती है रग-रग देह की
मन के तड़ागों में।।
मैं वो हर बात खोजती हूं।
जब भी गुलाब देखती हूं।।
बात कोई बड़ी छोटी
समय की बात सब होती।
सुलगते रिश्तों के चूल्हों
जगत यह सेंकता रोटी।।
ये लिख तुम्हें रोज भेजती हूं।
हवा जब मुड़ते देखती हूं।।

- प्रियंवदा

रस्म अदायगी

भ्रष्टाचार और हत्या आदि के आरोपों से घिरे नेताजी ने गांधी जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई। सभी बारी-बारी से अपने कामों का विवरण दे रहे थे।

पहला बोला- सर, सौ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भाड़े पर भीड़ का प्रबंध हो गया है।

दूसरे ने कहा- हुजूर, गांव में आपके खेतों पर काम करने वाले कुछ बंधुआ मजदूरों को बुला लिया गया है, जिन्हें कल समारोह में दलित के नाम पर सम्मानित किया जाना है।

तीसरे समर्थक ने अपनी बात रखी- पहलवान जी को समारोह स्थल के चारों तरफ हथियारों से लैस गुंडों को तैनात रखने के लिए बता दिया गया है।

चौथे ने भी जानकारी दी- साहब, समारोह समाप्ति के बाद समर्थकों के लंच के लिए मटन और शराब की पूरी व्यवस्था हो गई है। साथ में नाच-गाने के लिए लड़कियां भी बुला ली गई हैं।

नेताजी कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे।

अगले दिन नेताजी का काफिला समारोह स्थल पहुंचा। पैसों के लोभ में आई भीड़ ने 'नेताजी जिंदाबाद' के नारे लगाए। नेताजी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा- देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हम सभी उन्हें सादर नमन करते हैं। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर ही हम रामराज्य की कल्पना साकार कर सकते हैं!

फिर नेताजी ने लंबा-चौड़ा भाषण दिया। और इस तरह, इस वर्ष भी गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाने की रस्म अदायगी कर दी गई।

- विनोद प्रसाद

कप्तानी के मोर्चे पर फंसे कोहली!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हारने के बाद विराट कोहली बेहद दबाव में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सरेंडर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर अभी एक वनडे बाकी है। जबकि टीम इंडिया को इसके अलावा टी-20 और टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। ऐसे में इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे की चुनौती विराट के लिए किसी अग्निपरीक्षा की तरह दिख रही है। पिछले 5 मैचों में टीम इंडिया को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले विराट के कप्तान रहते हुए टीम इंडिया को कभी भी इतने लगातार मैचों में हार का सामना नहीं करना पड़ा था।

विराट कोहली साल 2013 से टीम इंडिया की वनडे में कप्तानी कर रहे हैं। उनके कप्तान रहते हुए टीम इंडिया ने जीत के कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन पिछले 5 वनडे मैचों में टीम इंडिया को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। हार का ये सिलसिला पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन के मैदान पर शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड के इस दौरे पर टीम इंडिया को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया लगातार 2 मैच हार चुकी है। इससे पहले विराट की कप्तानी में टीम इंडिया को साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।

पिछले 46 सालों में टीम इंडिया को सबसे ज्यादा लगातार 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया की ये लगातार हार 1981 में सुनील गावस्कर की कप्तानी में हुई थी। हार का ये सिलसिला सिडनी के मैदान पर ही शुरू हुआ था। इसके बाद 1989 में भारत को लगातार 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। उन दिनों टीम इंडिया की कमान श्रीकांत और फिर वेंगसरकर के हाथों में थी। अब पांचवीं बार टीम इंडिया को लगातार 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। लगातार 5 मैचों में हारने वाले भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी और वेंकटराघमन भी हैं। 1978 में इन दोनों की कप्तानी में भारत को लगातार 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। 1983 में कपिलदेव की कप्तानी में भी भारत को 5 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था। 1988 में रवि शास्त्री, साल 2002 और 2005 में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के कप्तान रहते हुए भारत को लगातार 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।

उधर, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कप्तान विराट कोहली की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को पहले 2 मैचों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों मैचों में बुमराह ने बेहद खराब गेंदबाजी की है। मौजूदा दौर में बुमराह की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में होती है। लेकिन उनकी गेंदबाजी को क्या हो गया है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैच के बाद उपकप्तान केएल राहुल ने बुमराह का बचाव किया। बुमराह ने अब तक दो मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 152 रन खर्च किए हैं। वो मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया के सबसे महंगे तेज गेंदबाज हैं। टीम इंडिया के लिए 66 वनडे खेलने वाले बुमराह ने अब तक 4 बार 70 से ज्यादा रन खर्च किए हैं। सिडनी के मैदान पर उन्होंने पिछले दो मैचों 73 और 79 रन खर्च किए हैं। इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले हैं।

पिछले साल वर्ल्डकप के बाद ये दूसरा मौका है जब बुमराह का बेहद खराब प्रदर्शन रहा हो। इस साल जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी तो बुमराह वहां भी फ्लॉप साबित हुए थे। 3 मैचों में उन्होंने 30 ओवर की गेंदबाजी की थी। इस दौरान उन्होंने 167 रन खर्च किए थे। जबकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था। इतना ही नहीं पिछले 8 वनडे मैचों में बुमराह को सिर्फ 3 विकेट मिले हैं। जबकि इस बार आईपीएल में बुमराह ने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था। उन्होंने 27 विकेट लिए थे। वो रबाडा के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।

● आशीष नेमा

कोहली ने सबसे तेज बनाए 22,000 इंटरनेशनल रन

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म में वापस लौट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 83 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली। हालांकि, इस मैच में हार के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी गंवा दी है, बावजूद इसके विराट कोहली की रिकॉर्ड बुक में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारतीय रन मशीन ने सबसे तेज 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसी रिकॉर्ड में उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 22,000 रनों के आंकड़े को छूने के लिए 462 पारियां ली। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 493 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था। वहीं, ब्रायन लारा ने 511 पारियां और रिकी पोंटिंग ने 514 पारियों में इस कारनामे को अंजाम दिया है। भारतीय कप्तान के अब 22011 इंटरनेशनल रन हैं। तीनों फॉर्मेट में 50 के औसत से विराट ने टेस्ट में 7240 रन, वनडे में 12834 रन और टी20 इंटरनेशनल में 2794 रन बनाए हैं। ओवरऑल लिस्ट में विराट कोहली सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आठवें नंबर हैं। इस लिस्ट में 34357 रनों के साथ सचिन तेंदुलकर पहले नंबर हैं। इस लिस्ट में 24208 रनों के साथ दूसरे भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ हैं।

...जब यामी गौतम ने पिता को बताई थी विक्की डोनर की कहानी

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने 2012 में फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह आयुष्मान खुराना के अपोजिट नजर आई थीं। अपनी डेब्यू फिल्म में ही यामी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट आम बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले थोड़ा अलग था। फिल्म इनफर्टिलिटी और स्पर्म डोनेशन जैसे सब्जेक्ट पर थी जिसे इंडियन सोसाइटी में टैबू माना जाता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2018 में यामी ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, वो ऐसा दौर था जब मैं जबरदस्त तरीके से ऑडिशन दे रही थी। उस वक्त मेरे पर टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म से डेब्यू करने की चॉइस थी। मैंने सबकुछ अपने दम पर किया, उस समय मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था। जब मैंने विक्की डोनर के लिए ऑडिशन दिया तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा कि फिल्म किस बारे में है? कास्टिंग डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दीं। जब मुझे फिल्म मिली तब मुझे इसके सब्जेक्ट के बारे में मालूम चला। पेरेंट्स को यह बात बतानी जरूरी थी। मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि फिल्म किस बारे में है और मैंने उन्हें फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट थमा दी। जब मेरे पेरेंट्स ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनका रिएक्शन था-यह बहुत बेहतरीन है। फिल्म जबरदस्त सक्सेसफुल रही और इसने आयुष्मान और यामी के कैरियर को ऊंचाई दी।

भूत पुलिस की शूटिंग कर रहीं यामी... यामी ने बदलापुर, काबिल, उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक और बाला जैसी फिल्मों में काम किया। इस साल उनकी फिल्म गिन्नी वेड्स सन्नी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसमें वह विक्रांत मैसी के साथ नजर आई हैं। इन दिनों यामी धर्मशाला में फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग कर रही हैं जिसमें उनके अलावा सैफ अली खान, जैकलिन फर्नांडीज और अर्जुन कपूर नजर आएंगे।

शादी के दिन गौरी से बोले थे शाहरुख- 'चलो बुर्का पहनो, नमाज पढ़ो'

शाहरुख खान की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शाहरुख और गौरी स्कूल के समय से एक-दूसरे से प्यार करते थे और कई सालों के अफेयर के बाद दोनों ने अपने प्यार के बारे में अपने घरवालों को बताया। हालांकि, पहले शाहरुख के मुस्लिम होने की वजह से गौरी के घरवालों ने मना कर दिया लेकिन बाद में उनके प्यार के आगे आखिरकार घरवालों को झुकना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के दौरान भी एक दिलचस्प किस्सा हुआ था जिसके बारे में शाहरुख ने खुद सालों पहले एक इंटरव्यू में बताया था। सालों पहले एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने शाहरुख का एक इंटरव्यू लिया था जो कि इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख ने अपने वेडिंग रिसेप्शन का एक वाकया शेयर किया है। शाहरुख बोले-वेडिंग रिसेप्शन में जब मैं मेहमानों के बीच पहुंचा तो गौरी के रिश्तेदार धीरे-धीरे बातचीत कर रहे थे कि लड़का तो मुस्लिम है, क्या

ये लड़की का धर्म परिवर्तन कर देगा? शाहरुख ये बात सुनकर गौरी के पास गए और सबके सामने उनसे बोले-गौरी उठो, बुर्का पहनो, नमाज पढ़ो। ये सुनकर मेहमान और गौरी के घरवाले हक्के-बक्के रह गए। इसके बाद शाहरुख ने कहा, अबसे गौरी बुर्का पहनेंगी, घर से नहीं निकलेंगी, इनका नाम आएशा रख देंगे और इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर मेहमानों ने सोचा कि अभी तो शादी हुई है और शाहरुख ने अभी से ये सब करने को कह दिया लेकिन बाद में जब सबको पता चला कि शाहरुख मजाक कर रहे हैं तो सबकी जान में जान आई।

लताजी ने शेयर की जहर दिए जाने की घटना, बोलीं- 3 महीने बिस्तर पर रही

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि जब वे 33 साल की थीं, तब किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। अब खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाया है। उन्होंने एक बातचीत में कहा, हम मंगेशकर्स इस बारे में बात नहीं करते। क्योंकि यह हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल था 1963। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैं बेड से भी बमुश्किल उठ पाती थी। हालात ये हो गए कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। लताजी की मानें तो डॉ. कपूर के इलाज के बाद वे धीरे-धीरे ठीक हुईं। वे कहती हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉ. कपूर का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। तीन महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी।

यतो अधर्मः ततो जयः

परित्राणाय पापीनां, विनाशाय च सुकृताम।
अधर्मसंस्थापनार्थाय ,संभवामि नित्यप्रतिम।

आजकल सत्य का प्रतिष्ठान धूल-धूसरित और उपेक्षित हो गया है तथा झूठ की चमक-दमक बढ़ गई है, सत्यनिष्ठ प्रताड़ित-अपमानित हो रहे हैं तथा कपटी पुरस्कृत एवं आभामंडित हो रहे हैं। मंच और पार्श्व की भाषा का अंतर गहरा हो गया है। हमारे देश का महान नारा 'सत्यमेव जयते' अब मुंह चिढ़ाने लगा है। इसलिए हमारे परम मित्र घोंचूमल आजकल झूठ के व्यापार में अधिक रुचि लेने लगे हैं। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है- अखिल भारतीय मिथ्यावादी पार्टी। आगामी चुनाव में इस पार्टी को उतारने के लिए उन्होंने जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है- झूठ, नकल और कालाबाजारी को वैध बनाना। उनका कहना है कि झूठ, नकल और कालाबाजारी की प्रवृत्ति आदिम और मौलिक है। हजारों वर्षों से 'सत्यमेव जयते' कहने के बाद भी असत्य, कपट, दुराचरण और अनैतिकता की प्रवृत्ति अक्षुण्ण ही नहीं है, बल्कि निरंतर फल-फूल रही है। हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्यों और भावी योजनाओं की रूपरेखा खींची है। घोषणा-पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार है-

'मिथ्यावादी पार्टी का उद्देश्य झूठ को राष्ट्रीय महत्व देकर बहुसंख्यक जनता को न्याय दिलाना है। लोकतंत्र बहुमत का शासन है लेकिन बहुमत होते हुए भी झूठों को सत्ता से दूर रखा गया है। हमारी पार्टी मिथ्याचारवादियों को सत्ता में हिस्सेदार बनाएगी। हम झूठ बोलेंगे, झूठ सोचेंगे और झूठ ही करेंगे। हम झूठ की फसल उगाएंगे और विश्व के अन्य देशों में उसका निर्यात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपनी मिथ्या भाषा को शामिल कराने का प्रयत्न करेंगे। हमारा ओढ़ना-बिछाना सबकुछ झूठ होगा। हम प्रतिवर्ष ऐसे लोगों को 'झूठ रत्न' से सुशोभित करेंगे जो अपने मिथ्या आचरण से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन सके। अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले सात लोगों को 'नकल शिरोमणि' 'घोटाला पुरुष', 'कालाबाजार सम्राट', 'भ्रष्टाचरण गौरव', 'रिश्वतनंदन', 'भ्रष्टाधिपति', 'कपटी महाराज', 'धोखामूर्ति' पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे शिक्षकों को राष्ट्रीय अलंकरण से सज्जित किया जाएगा जो वर्ष में एक भी कक्षा नहीं लेंगे। ऐसी दवा कंपनियों को 'यमराज' पुरस्कार दिया जाएगा जो अपने दवा कारखानों में केवल नकली दवा बनाएंगे। ऐसे डॉक्टरों को 'कुंभीपाक प्रिय' की उपाधि दी जाएगी जो शल्य क्रिया के समय अपने मरीजों के पेट में कैंची अथवा रुमाल छोड़ देंगे। उन हकीमों को भी पुरस्कृत करने की हमारी आकर्षक योजना है

जिनके सर्वाधिक मरीज भगवान को प्यारे होकर कुंभीपाक की जनसंख्या बढ़ाएंगे। ऐसे क्लर्क भी पुरस्कृत किए जाएंगे जो हर फाइल पर कुंडली मारकर बैठेंगे। वैसे सेवापरायण अधिकारी जो सरकारी संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझकर उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे उन्हें भी पुरस्कार देने की हमारी भावी राष्ट्रीय योजना है। कल-कारखानों के श्रमिकों के लिए हमारी अनेक सुनहरी योजनाएं हैं। हम ऐसे श्रमिकों को 'अकर्मवीर पुरस्कार' से पुरस्कृत करेंगे जो बीडी फूंकने और गप्प लड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे।

हम इतिहास को फिर से लिखेंगे। हम मिथ्याचारियों, कालाबाजारियों, देशद्रोहियों और धोखेबाजों की गौरव गाथा को इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में लिपिबद्ध करेंगे। इनकी उदात्त परंपरा अक्षुण्ण रहे तथा हमारी भावी पीढ़ी इनके करतबों के बारे में जान सके, इसके लिए हम राष्ट्रीय संग्रहालय एवं स्मृति सदन की स्थापना करेंगे। घोटालेबाजों, आलसियों और अफवाहबाजों की राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची बनाएंगे और योग्यता के अनुसार उन्हें कोई न कोई सम्मानजनक पद देकर वर्षों से उपेक्षित-वंचित-प्रताड़ित देशरत्नों को सामाजिक न्याय देकर महिमामंडित करेंगे। निगमों, निकायों, बोर्डों के अध्यक्ष पदों पर आसीन अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। जो अधिकारी ईमानदार पाए जाएंगे और जिनका खाता स्विस बैंक में नहीं होगा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। सर्वत्र झूठ का साम्राज्य होगा। झूठतंत्र को मजबूत करने के लिए हम पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करेंगे। हमारे प्रमुख पत्र के नाम होंगे- असत्य दर्पण, झूठवाचक, मिथ्याचार दर्शन, अफवाह आदि। हम अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे और हिंदी पर प्रतिबंध लगा देंगे।

अंधविश्वास, जादू-टोना, तंत्र-मंत्र इत्यादि विज्ञानसम्मत विचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन विचारों के संवर्धन और उन्नयन के लिए 'झाड़-फूंक आयोग' तथा 'धार्मिक ढोंग शोध संस्थान' की स्थापना की जाएगी। देश के ओझों और तांत्रिकों को इन संस्थानों का अध्यक्ष बनाया जाएगा और अपने गुरु स्वामी झूठानंद को राष्ट्रीय साधु घोषित किया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज काले रंग का होगा जिस पर उल्लू का चित्र होगा और चित्र के ऊपर अंकित होगा- यतो अधर्मः ततो जयः। असत्य, हिंसा और कदाचार आदि मूल्यों को प्रोत्साहित कर हम ऐसा नारकीय शासन तंत्र स्थापित करेंगे जिसमें जनता को सब कुछ करने, न करने की आजादी होगी। इति सकल कलिकलुष विध्वंसने मिथ्या महात्म प्रथम सोपानः समाप्तः।

● **वीरेन्द्र परमार**

For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
Science House Medicals Pvt.Ltd.
17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge
Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5
Email : shbpl@rediffmail.com
PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687
Celebrating
25

समय पर जांच, उपचार एवं सावधानियां

आपको डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचा सकते हैं ...

डेंगू एवं चिकुनगुनिया का वाहक एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। पूरी बांह के कपड़े पहनें तथा पानी को जमा न होने दें। इससे बचने के लिए घरों के आस-पास सफाई रखें, सभी कंटेनर जिनमें पानी भरा हो एवं कूलर के पानी सप्ताह में एक बार खाली कर, सुखा कर, उनमें नया पानी भरें। आप दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

डेंगू के लक्षण

तेज बुखार, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, डेंगू हो सकता है।

चिकुनगुनिया के लक्षण

तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में असामान्य दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि चिकुनगुनिया के प्रमुख लक्षण हैं।

उपचार

यह लक्षण पाए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क खून की जांच कराएं, जांच में डेंगू या चिकुनगुनिया पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा उपचार लें।

डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचाव

- पानी के बर्तन ढंककर रखें।
- अनुपयोगी सामग्रियों जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें, दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हें अच्छी तरह सुखाएं।
- हैण्डपम्प के आस-पास भी पानी इकट्ठा न होने दें। जमा पानी पर मिट्टी का तेल या इंजन का जला हुआ तेल डालें।
- आस-पास सफाई रखें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहनें। पानी में मच्छर नहीं पनपने दें।

मास्क पहनें,
धोते रहें हाथ,
रहें दो गज दूर,
कोरोना से
बचेंगे जरूर।

हमारा पानी हमारी जवाबदारी

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनहित में जारी

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

D-17001/20